सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 मार्च, 2020

षोडश विधान सभा   05 मार्च, 2020 ई0
-------------   वृहस्पतिवार,तिथि------------------
पंचदश सत्र   15 फाल्गुन, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : आपने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको आप समय पर उठाइयेगा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-17(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)</u>

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिकरण (गठन एवं प्रक्रिया) नियमावली 2002 की कंडिका 3 (2) में यह प्रावधान है कि अधिकरण में एक अथवा अधिक सदस्य रहेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कोटि के कर्मियों से नियुक्त किये जायेंगे।

सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत सरकारी सेवक जो बिहार सरकार में विशेष सचिव स्तर से अन्यून नहीं होंगे। (ii) सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत बिहार सहकारिता सेवा के पदाधिकारी जो संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों के स्तर से अन्यून नहीं होंगे। (iii) सेवानिवृत्त वरीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश । परंतु यह कि किसी विशिष्ट कोटि से एक से अधिक कर्मी नियुक्त नहीं किये जायेंगे परंतु यह और कि एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा । बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिनांक 06.10.2017 एवं दिनांक 12.10.2019 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञापन निकाला गया था । उक्त विज्ञापन के आलोक में विभाग में विभिन्न सेवा संवर्गों यथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधाान न्यायाधीश, बिहार न्यायिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, मुख्य वैज्ञानिक, बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत पदाधिकारियों के कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए । उक्त प्राप्त अभ्यावेदनों को सूचीबद्ध कर संविदा के आधाार पर नियोजन हेतु संबंधित पदाधिकारियों के संबंध में वांछित सूचना/अभिलेख की मांग सामान्य

प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य संबंधित विभागों से करने एवं नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस महीने या अगले महीने तक यह पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि इसका दिनांक 06.10.2017 को विज्ञापन हुआ था और उसके बाद फिर दूबारा विज्ञापन हुआ 12.10.2019 को, इतने दिनों में जो स्वावलंबी समिति का गठन नहीं हुआ, लगभग बिहार में दस हजार समितियां हैं । इसके विवादों का निराकरण कैसे हो रहा है और दूसरा इतना दिन जो विलम्ब किया गया इसको, तीन वर्षों से ज्यादा हो गया और इसके लिए जो दोषी हैं कि अभी तक समिति का गठन नहीं हो सका, उसके खिलाफ सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री राणा रणधीर, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। हमलोगों ने इसकी समीक्षा की है और जैसी सूचना विभाग ने दी है कि इस महीने में या अगले महीने तक यह पूरी प्रक्रिया कर ली जायेगी, चूंकि इसमें विधि विभाग का भी राय लिया जायेगा और विधि विभाग में फाईल भेजकर परामर्श लेने में भी थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन इस विलम्ब को हमलोगा यथाशीघ्र दूर करेंगे । माननीय सदस्य की चिंता से विभाग वाकिफ है । हमलोग जल्दी इसका निष्पादन करेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पुन: इसको विधि विभाग में भी भेजना है, यदि विधि विभाग में भेजना है तो विधि विभाग को इस निर्देश के साथ भेजा जाय कि आप इतने दिनों में अपना परामर्श दे दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर में लिखा है कि एक बार अक्टूबर, 2017 में और फिर अक्टूबर, 2019 में विज्ञापन निकाला गया था दो साल के अन्तराल पर तो पहले वाले विज्ञापन में क्या नहीं हो पाया था?

श्री राणा रणधीर, मंत्री : महोदय, पहले वाले विज्ञापन में समस्या हुई, दो लोग आये थे, सिविल कोर्ट के जज साहेब थे, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसमें कौन वरीय होते हैं, इसके परामर्श के लिए विधि विभाग को फाईल भेजी गयी थी ।

अध्यक्ष : अब आप कह रहे हैं कि एक महीना, तो इसको दूर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18(श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)</u>

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

विगत सितम्बर, 2019 में राज्य में भारी बारिश हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पटना शहर के अधिकांश शहरों में भारी जल-जमाव हो गया था ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

पटना शहर में जल-जमाव की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जल-जमाव की परिस्थितियां एवं कारणों का निर्धारण वर्षाऋतु के पूर्व नालों की सफाई, जल निकासी पम्पों की मरम्मति, रख-रखाव एवं चालू रखने हेतु ससमय कार्रवाई करने में हुई कमी अथवा चूक की जांच हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गयी थी । उक्त गठित समिति के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है । समिति के प्रतिवेदन के कतिपय पदाधिकारी एवं अभियंताओं के विरूद्ध लापरवाही बरते जाने का उल्लेख किया गया है ।

3- उच्चस्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन में चिन्हित कतिपय पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के विरूद्ध लापरवाही बरते जाने के लिए उन्हें निलम्बित कर दिया गया है एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि खंड-1 में कि स्वीकारात्मक है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्षा तो होनी है हर साल, वर्षा के पूर्व क्या तैयारी की गयी थी सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा यह हम आपसे जानना चाहते हैं ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, वर्षा के पूर्व नगर निगम जो नाले की सफाई करता है, उसपर हमने स्पष्ट कहा है कि कहीं-न-कहीं चूक हुई है, जिस कारण से उनपर कार्रवाई हुई है और बुडको द्वारा जो हमारे वहां इक्युपमेंट है या जो पम्प हाउस है, उसमें कहीं-न-कहीं कोई विलम्ब हुआ है और उसपर कार्रवाई की गयी है और उसी के मद्देनजर उनको निलंबित भी किया गया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि चूक हुई और चूक होने के कारण पटना में जो परिस्थिति थी, उससे सारे माननीय विधायक और मंत्री अवगत हैं । तो अब जो चूक हुई, माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमिटी बनायी गयी और कमिटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है । महोदय, जैसे ये विभागीय मंत्री हैं तो विभागीय मंत्री का दायित्व होता है कि अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा करें और कार्यों की समीक्षा के अनुरूप वे निदेश देते हैं कि यह-यह कार्रवाई करनी है तो इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा वर्षा के पूर्व जो एक परम्परा रही है कि वर्षा के पूर्व नाले की सफाई करना या जो भी समस्या है, उसका निदान वर्षा के पूर्व खोजा जाता है, मगर जितनी बड़ी जगहंसाई दुनिया में हुई है और लोग डूबे

भी, मरे भी, हमारे ही घर में दस दिन तक पानी था तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवारी लेती है या नहीं लेती है?

अध्यक्ष : सिद्दिकी साहेब, जो आपका प्रश्न है या जो आप पूरक पूछ रहे हैं, सरकार ने माना है कि वर्षा पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए थी, नहीं हुई । अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गयी, उस समय जो कठिन परिस्थिति पैदा हुई, उसके आलोक में जो कार्रवाई हुई उच्चस्तरीय कमिटी बनाकर, किनकी लापरवाही से यह सब हुई, उसकी जिम्मेवारी भी चिन्हित और सुनिश्चित की गयी है तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई भी की गयी है । अब आपका क्या प्रश्न है?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, दो प्रश्न है, एक तो हम यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने किनको-किनको दोषी माना और किनको-किनको दोषी नहीं माना और दूसरा यह कि फर्जी निकासी की भी बातें जांच रिपोर्ट में आयी है तो इन्होंने कहा कि एफ0आई0आर0 करना, उसपर कार्रवाई करना, निलंबित करना तो उन्होंने सिर्फ छोटे लोगों पर ही कार्रवाई की या जो जिम्मेवार लोग थे उनपर भी कार्रवाई हुई ।

टर्न-2/राजेश-राहुल/5.3.20

श्री सुरेश शर्मा, मंत्री: महोदय, इसमे जो भी जिम्मेवार लोग थे, सब पर कार्रवाई हुई है, बुडको के एम0डी0 पर कार्रवाई हुई, नगर आयुक्त पर कार्रवाई हुई, चीफ इंजीनियर से लेकर एक्सक्यूटिव इंजीनियर से नीचे तक के ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है, 28 आदमी पर कार्रवाई हुई है ।

अध्यक्ष: अब आप किसपर कार्रवाई चाहते हैं ?

श्री अब्दुल बारी सिद्‌दकी: महोदय, एफ0आई0आर0 इन्होंने दर्ज किया, एफ0आई0आर0 दर्ज कराया कि नहीं, इतना बड़ा संकट के लिए जो जान-माल का नुकसान हुआ, उसका एफ0आई0आर0 हुआ कि नहीं और मुआवजा मिला कि नहीं एवं मंत्री जी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न में है और जो ये जानना चाह रहे हैं, तब एक ही हिस्सा बचता है कि अगर कोई फर्जी निकासी हुई है, बिना काम किए कोई पैसा निकाला गया है, तो जिम्मेवार लोगों को निलंबित करते हुए, क्या एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की भी व्यवस्था की गई है ?

श्री सुरेश शर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई फर्जी निकासी की जानकारी नहीं हुई है, फर्जी निकासी नहीं हुई है लेकिन जो लोग दोषी पाए गए हैं, उस पर एफ0आई0आर0 की भी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष: ठीक है, अब छोड़िये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, इन्होंने जो जांच कराई है डेवलपमेंट कमिश्नर से, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए और अगर सार्वजनिक नहीं करते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वह रिपोर्ट मंगाकर देख लें कि साहब उस रिपोर्ट में क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, जिन पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है, उसमें पिक एण्ड चूज किया गया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य जी, आप किन पर कार्रवाई चाहते हैं, वह बता दीजिए सरकार को।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, आनंद किशोर पर कार्रवाई होनी चाहिए वे कमिश्नर थे, आनंद किशोर पर कार्रवाई नहीं हुई है ।

अध्यक्ष: ठीक है, अब हो गया, आपने सूचना दी, सरकार ने ग्रहण कर ली ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, एक तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफ0आई0आर0 होनी चाहिए, वे जिम्मेवार हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए..............

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष: अब हो गया । अब आगे बढ़ने दीजिए । अब अल्पसूचित प्रश्न संख्या:19 नम्बर भी सिद्दिकी साहब आप ही का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी, किसी पर कार्रवाई ऐसे ही होती है क्या ? उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच हुई है और सिद्दिकी साहब ने कहा है कि जो जांच की रिपोर्ट होगी, हम देख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, सदन की कमिटी से इसकी जांच कराई जाय.............

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब अगला प्रश्न होने दीजिए । आप बहुत पूछ चुके हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, इस पर सदन की कमिटी बननी चाहिए..........

अध्यक्ष: ठीक है आपने कह दिया, अब हम देख लेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, आवश्यकता हो, तो सदन की कमिटी बना दी जाय ।

अध्यक्ष: भाई वीरेन्द्र जी, एक मिनट सुनिए, माननीय सदस्य सिद्दिकी साहब ने कहा है कि जो जांच कराई गई है उसकी जो रिपोर्ट है, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है,

इन्होंने कहा है कि उसको देख लेने के लिए, तो अगर जांच रिपोर्ट में पिक एण्ड चूज किया गया होगा, तो उसको हम जरूर देखेंगे । अब अगला प्रश्न होने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अगर यह नहीं होगा, तो आप लोगों के कहने से तो कार्रवाई नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, आनंद किशोर उस समय क्या थे, वे तो कमिश्नर थे, कमिश्नर की क्या भूमिका होती है, कमिश्नर की तो कोई भूमिका होती नहीं है, वे न तो नगर विकास विभाग के सचिव थे और न ही नगर आयुक्त थे, वे तो कमिश्नर थे, कमिश्नर की तो कोई भूमिका होती नहीं है............

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, सरकार का इतना स्पष्ट जवाब है, माननीय सदस्य आग्रह करना चाहते हैं महोदय और आने वाला जो प्रश्न है महोदय वह सिद्दिकी साहब का ही अल्पसूचित प्रश्न है महोदय । सदन को चलने दिया जाय महोदय, अपनी जगह पर जाय विपक्ष के माननीय सदस्य और इतना स्पष्ट उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया है, माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय, ने भी बात को रखा है महोदय, तो ये क्या चाहते हैं, इस प्रकार से सदन की कार्रवाई नहीं चलती है, सरकार का स्पष्ट जवाब है और उसके बाद भी सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, अभी अल्पसूचित प्रश्न भी हैं, तारांकित प्रश्न भी हैं, ध्यानाकर्षण भी हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसीलिए माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपनी जगह पर जा करके और अब सरकार की बात को भी सुने ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, जब सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं देती है और जब सरकार दोषी को बचाती है, तब सदन में इस तरह का माहौल पैदा होता है..........

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, सरकार का मकसद किसी को बचाना नहीं है और न ही किसी को फंसाना है । सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इस सरकार में न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है, सभी पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, सांच को आंच क्या, सदन की कमिटी बना दीजिए ।

(व्यवधान)

टर्न-3/सत्येन्द्र-मुकुल/05-03-2020

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: सिद्दिकी जी, आपने कहा कि जो जांच रिपोर्ट में आयी है उसमें अगर किसी को छोड़ा गया है या किसी के साथ पक्षपात किया गया है तो आसन देख ले, हमने कहा कि हम देखकर आपसे भी बात कर लेंगे, उसके बाद जो जरूरी होगा वह किया जायेगा तो अभी क्या करना है।

(व्यवधान जारी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मैं प्रश्नकर्ता सदस्य हूँ और जब प्रश्न स्वीकृत हो जाता है और सदन में आ जाता है तो ये सदन के सभी माननीय सदस्यों का प्रश्न हो जाता है। महोदय, मैंने सुझाव दिया जरूर मगर चूंकि ये बढ़-चढ़कर जब बोलने लगे तो जो वस्तुस्थिति है, अरे दुनिया ने देखा कि पटना में क्या हुआ, सिस्टम फ्लेयोर था।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: अभी आपका अगला प्रश्न पूछा हुआ है । उसका उत्तर माननीय नगर विकास मंत्री जी दीजिये।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या: 19 (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1-स्वीकारात्मक है।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत भागीदारी से अबतक पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 380 करोड़ रू0, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 382 करोड़ रू0, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 112.50 करोड़ रू0 एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 110 करोड़ रू0 विमुक्त किया गया है। सभी जगहों पर स्मार्ट सिटी का कार्य/निविदा प्रक्रियाधीन है। अबतक पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 93.38 करोड़ रू0, भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 17.07 करोड़ रू0..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: गुलाब जी, टेबल पीटने से आदमी ऊंचा नहीं उठता है।

(व्यवधान जारी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 03.45 करोड़ रू0 एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 06.44 करोड़ रू0 के खर्च संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है।

3-आंशिक स्वीकारात्मक है। पटना एवं भागलपुर को केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त की राशि निर्गत की जा चुकी है। बिहारशरीफ एवं मुजफ्फरपुर को द्वितीय किस्त की राशि केन्द्र सरकार द्वारा अभी निर्गत नहीं की गयी है। सभी जगहों पर स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्य/निविदा प्रक्रियाधीन है।

4- उपरोक्त खंडों का उत्तर पूर्णतः स्वीकारात्मक नहीं है। सभी जगहों पर स्मार्ट सिटी का कार्य/निविदा प्रक्रियाधीन है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न । श्री लाल बाबू राम। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-937 (श्री लाल बाबू राम)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री: अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सकरा एवं मुरौल प्रखंडों का वर्तमान में औसत जलस्तर 25 फीट से ऊपर है। सकरा प्रखंड में 3342 अदद और मुरौल प्रखंड में 1032 अदद चापाकल चालू अवस्था में है। पेयजल की फिलहाल कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं है। गरमी के दिनों में जल स्तर नीचे जाने पर तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न होने पर चापाकलों का राईजर पाईप बढ़ाकर या आवश्यकतानुसार नये चापाकल का निर्माण कर या टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: एक आदमी बोलिये। एक आदमी बोलिये, क्या बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान जारी)

फिर दोनों बोल रहे हैं। आप दोनों क्या बोल रहे हैं सदन की कमिटी, आपके नेता ने कहा है हमको स्वयं देखने के लिए, देखेंगे जरूरत होगी तभी बनायेंगे और क्या कहना है।

(व्यवधान जारी)

नहीं, आप जाइए। आप किसी अधिकारी का नाम लेकर सीधे कहियेगा कि इस पर कार्रवाई कर दीजिये ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपलोग पुराने सदस्य हैं, आजतक बताइए एक उदाहरण जो सरकार ने जांच करायी है, उसकी रिपोर्ट कुछ है और माननीय सदस्य कहें कि फलां अधिकारी को आप सस्पेंड कर दीजिये, यह कोई तरीका नहीं होता है इसलिए जो सिद्दिकी साहब ने कहा है वह होगा । अगर उसके आधार पर चलने देना है तो चलने दीजिये। अगर आपकी इच्छा है कि माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछें तो आसन मजबूर होकर खत्म कर देगा और इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है।

(व्यवधान जारी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, हम तो न ''ए'' के बारे में कहा, न ही ''बी'' के बारे में कहा मैंने न किसी ''ए'' का नाम लिया न ''बी'' का मगर मैंने ये अपेक्षा जरूर की थी कि...

(व्यवधान जारी)

मगर सरकार न तो पहले गंभीर थी और न सरकार अब भी गंभीर है। सरकार को चाहिए था कि जो लोग दोषी हैं जिन पर कार्रवाई की गयी है तो उनका तो कम से कम ये नाम बतलाते।

अध्यक्षः जिन पर कार्रवाई की गयी है वह सरकार...

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार भी गंभीर है और इस सवाल पर आसन भी गंभीर है महोदय और माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने जिन बातों को सदन में उठाया है आसन ने उसे गंभीरता से लिया है और आसन ने कहा है कि मैं खुद देखूंगा उसके बाद भी सदन में आकर हंगामा करना महोदय इनका मकसद यह है कि ये सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं और जो हमारा तारांकित प्रश्न है, इन प्रश्नों को बाधित करना चाहते हैं। इनको मतलब नहीं है कि सदन चले इनको मतलब सिर्फ है हंगामा खड़ा करना। ये अखबार में जाना चाहते हैं, ये टेलीविजन में जाना चाहते हैं, ये बिहार की जनता की भलाई की बात नहीं सोचते हैं। ये सदन का कार्य बाधित करना चाहते हैं, ये हठधर्मिता कर रहे हैं महोदय, इनको नियम-कानून से कोई मतलब नहीं है। जब नियमन हो गया, आसन का नियमन हो गया महोदय, ये वरीय सदस्य हैं और आर0जे0डी0 के वरिष्ठ नेता हैं और इनके कंट्रोल से बाहर है ये ललित यादव, और ये भाई वीरेन्द्र इनके कंट्रोल से बाहर हैं तो मैं इन लोगों से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर जाकर जो प्रश्न है उसका उत्तर सुनें।

(व्यवधान जारी)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः महोदय, आसन सर्वोपरि है आसन को आपके जैसे लोगों की मदद की जरूरत नहीं है और आपको पता नहीं किसने संसदीय कार्य मंत्री बनाया है, संसदीय कार्य मंत्री का जो रोल है वह रोल आप नहीं करते हैं, ऐसे-ऐसे यह क्या होता है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, सिद्दिकी साहब ने कहा है कि जो जांच प्रतिवेदन आया है इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उस पर जिन पदाधिकारियों के खिलाफ या जिनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है उसका आप एक विस्तृत प्रतिवेदन, विधान सभा की कमिटी नहीं बनेगी, वह रिपोर्ट आप सदन पटल पर रख दीजिये।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्रीः महोदय, उसको दे देंगे और जिस पर जो कार्रवाई होगी वह भी होगी।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: ठीक, अब तो चलिये, आपके नेता की बात मान ली गयी है।

(व्यवधान जारी)

चलिये, लाल बाबू राम जी का तो प्रश्न होने दीजिए।

(व्यवधान जारी)

आपलोगों की तो इतनी बात मानते हैं कि आपको गिनती नहीं होगी, इतनी बात मानते हैं। अभी बैठिये लाल बाबू राम जी का होने दीजिये। लाल बाबू राम जी की लॉटरी खुली है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से अपने अपने स्थान पर लौट गये)

टर्न-4/मधुप-हेमंत/05.03.2020

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, फिर से माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम के तारांकित प्रश्न सं0 937 का जवाब पढ़ दीजिए । (व्यवधान) संजय जी, अब शांति रहने दीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सकरा एवं मुरौल प्रखंडों का वर्तमान में औसत जलस्तर 25 फीट से ऊपर है । सकरा प्रखंड में 3342 अदद और मुरौल प्रखंड में 1032 अदद चापालक चालू अवस्था में है । पेयजल की फिलहाल कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं है । गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे जाने पर या पेयजल की समस्या उत्पन्न होने पर चापाकलों का राइजर पाईप बढ़ाकर आवश्यकतानुसार नये चापाकल का निर्माण कर या टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, चापाकल की बात की है माननीय मंत्री ने, टोटल चापाकल बंद हैं । महोदय, सकरा एवं मुरौल प्रखंड की सभी पंचायत जल संकट से प्रभावित हैं। कई पंचायत में तो भयानक स्थिति है । सरकार द्वारा भी इसकी जॉच करायी गयी है जो सत्य पाया गया है कि सकरा एवं मुरौल में जल संकट की स्थिति है और अभी तक सरकार द्वारा कोई भी स्थायी निदान के उपाय नहीं किये गये हैं, तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो स्थिति है, इसको देखते हुए सकरा एवं मुरौल में जो जल संकट की स्थिति है, इसके स्थायी निदान के लिए कारगर उपाय करेंगे?

अध्यक्ष : स्थायी निदान में आप क्या चाहते हैं ?

श्री लाल बाबू राम : वहाँ पर पानी टंकी की व्यवस्था, प्रत्येक पंचायत में पानी टंकी का निर्माण करवाया जाय ।

अध्यक्ष : नल-जल योजना में चल रहा है न ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, नल-जल योजना कारगर नहीं है ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो जानकारी दी है कि फिलहाल अभी पेयजल की कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं है । विभाग के अनुसार अभी औसत जलस्तर 25 फीट से ऊपर है, जब 25 फीट से नीचे जायेगा तो चापाकल सामान्यतया काम करना बन्द कर देता है । वह परिस्थिति अभी नहीं आयी है । गर्मी के दिनों में ऐसी परिस्थिति आने पर या पेयजल की समस्या उत्पन्न होने पर चापाकलों का राइजर पाईप बढ़ाकर या आवश्यकतानुसार नये चापाकल गाड़कर या टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है । जहाँ तक स्थायी व्यवस्था का सवाल है तो आपको ज्ञात है कि सरकार हर घर नल से जल के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में समस्या का स्थायी निदान हो जायेगा ।

श्री लाल बाबू राम : नहीं महोदय । नल-जल योजना यह धोखा है..

अध्यक्ष : हो गया लाल बाबू जी, कोई आपका पूरक नहीं है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 938 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)</u>

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में वर्णित जर्जर भवन पूर्व में गठित भुल्ली, कन्हौली, गजपति, बहुधंधी सहयोग समिति का था जिसका बाद में परसौनी, खिरोधर पैक्स में विलय हो गया है । वर्तमान में परसौनी, खिरोधर पैक्स में आई0सी0डी0पी0 योजनान्तर्गत निर्मित 100 मे0 टन क्षमता के एवं राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित 200 मे0 टन क्षमता का गोदाम पैक्स कार्यालय के साथ उपलब्ध है।

जहाँ तक गोदाम भवन की चहारदीवारी सहित पुनर्निमाण का प्रश्न है, इस संबंध में विभाग द्वारा वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है । यदि भविष्य में विभाग द्वारा पैक्सों में पूर्वनिर्मित गोदामों की चहारदीवारी सहित मरम्मती हेतु कोई योजना लायी जाती है तो सरकार इसपर विचार करेगी ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, कन्हौली, गजपति, बहुधंधी सहयोग समिति बहुत पुरानी सहयोग समिति है, जिसके पास काफी जमीन है जिसको गलत ढंग से कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं । महोदय, इसीलिए चहारदीवारी आवश्यक है । माननीय मंत्री जी.

अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गए ? (व्यवधान) तब आप बैठे हैं ? कह रहे हैं, नहीं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, पूरे राज्य में चापाकल बन्द हैं और मंत्री जी झूठा आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, महोदय, कन्हौली, गजपति, बहुधंधी सहयोग समिति बहुत ही पुरानी सहयोग समिति है, जिसके पास काफी जमीन है जिसको गलत ढंग से कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं । महोदय, इसीलिए वहाँ चहारदीवारी अति-आवश्यक है ।

जवाब तो मिला है लेकिन सही नहीं है । थोड़ा दिखवा लिया जाय ।

अध्यक्ष : बाकी इसमें जो आपको पूरक सूचना देनी होगी, मंत्री जी को दीजिएगा, वे कार्रवाई करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-939 (श्री शमीम अहमद)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुतः छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत ग्राम धरहरी के वार्ड नं0 2 में तथा बनकटवा प्रखंड अन्तर्गत ईनरवा, फुलवार के वार्ड नं0 2 में वर्ष 2016 में सोलर आधारित मिनी पाईप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई थी जिसमें भेट और स्टैंड-पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति किया जाना था । वर्ष 2017 में गृह जल संयोजन के साथ कार्य कराने हेतु संवेदक के साथ पूरक एकरारनामा किया गया है। इसके आलोक में दोनों स्थलों पर बोरिंग कार्य कर दिया गया है । पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और अप्रील, 2020 तक कार्य पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है । यद्यपि वर्णित पंचायत में हर घर नल-जल का काम अब पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है ।

2- उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

3- उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब 2016 में संविदा निकाली गई तो उसमें टर्म-कंडीशन कितने साल का दिया गया था कि चार साल के बाद अभी भी पूरा नहीं किया गया है ? इतना लम्बित होने का कारण क्या था ? अभी तक कितना पेमेंट किया गया ? किन-किन तिथि में कब-कब पेमेंट किया गया कि अभी तक काम लम्बित है ? इसमें जो भी पदाधिकारी दोषी पाये जा रहे हैं, उसपर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कार्य की धीमी प्रगति के लिए संवेदक को नोटिस दिया गया है और संवेदक के विरुद्ध डेबार और काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री शमीम अहमद : इसकी समय-सीमा क्या है ? कब कार्रवाई की गई है, यह हम जानना चाहते हैं मंत्री जी से ।

अध्यक्ष : अब तो कार्रवाई भी कर रहे हैं, अप्रील 2020 तक पूरा करने का भी लक्ष्य है । अब क्या है ?

श्री शमीम अहमद : महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जब विधान सभा में मामला आता है तभी कार्रवाई और जवाब आता है, उससे पहले हमारे पदाधिकारी क्या करते हैं कि चार साल में एक कार्य को पूरा नहीं किया गया, इसपर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : मैंने तो जानकारी दी कि कार्य की धीमी गति को संज्ञान में विभाग लिये हुये है और उसपर कार्रवाई की जा रही है और उसको डेबार करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 940(श्रीमती रेखा देवी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मसौढ़ी नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत बस पड़ाव निर्माण के लिए भूमि की मांग अंचलाधिकारी धनरुआ से की गयी थी । मांग के आलोक में अंचल कार्यालय, धनरुआ के पत्रांक-462, दिनांक-27.02.2020 द्वारा 3.66 एकड़ एवं 0.89 एकड़ भूमि गैर मजरुआ आम उपलब्ध करायी गयी है । उक्त चिन्हित भूमि पर बस पड़ाव निर्माण नगर परिषद मसौढ़ी की उपलब्ध राशि के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वयन कराया जायेगा ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि मसौढ़ी बाजार में पाली, जहानाबाद एवं एकंगरसराय की सारी बसें रोड पर ही पड़ी रहती हैं और प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है, तो मंत्रीजी समय-सीमा बताने का प्रयास करेंगे कि कब तक वहॉं बस पड़ाव का निर्माण करा दिया जायेगा ? वहां प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी हुई रहती है और दुर्घटना की भी संभावना रहती है ।

अध्यक्ष : अभी आप बता दीजिये कि बस पड़ाव के लिए जो जमीन खोज रहे हैं वह प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : जल्द ही शुरू करवा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 941(श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत इस्लामपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, इस्लामपुर क्षेत्रान्तर्गत जगदम्बा द्वार (गेट) से दुर्गा स्थान होते हुए भारत माता तक जाने वाली

सड़क एवं नाला जर्जर स्थिति में है । वर्तमान में वर्णित योजना नगर पंचायत, इस्लामपुर के बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

अतः भविष्य में नगर पंचायत, इस्लामपुर के बोर्ड द्वारा इस योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदि इस योजना का चयन किया जाता है एवं पारित किया जाता है, तो नगर पंचायत, इस्लामपुर को उपयुक्त राशि के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, इस्लामपुर द्वारा कराया जायेगा ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमने किया है माननीय मंत्रीजी से और सवाल दे दे रहे हैं नगर पंचायत इस्लामपुर को । महोदय, मंत्रीजी का जवाब हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमने प्रश्न किया है माननीय मंत्री नगर विकास से और प्रश्न का जवाब दे रहे हैं नगर पंचायत इस्लामपुर से । ...क्रमशः...

टर्न-5/आजाद:अंजली/05.03.2020

..... क्रमशः .....

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री महोदय बतावें कि ये कब तक इस योजना को प्रायोरिटी के आधार पर पूरा करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये स्वीकार करके भेजवा दें, हम उसको तुरंत करवा देंगे ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-942 (श्री विजय प्रकाश)</u>

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, जमुई क्षेत्र में कुल 30 वार्डों में पक्की गली-नली योजना का कार्य कराया जा रहा है । इसके लिए आवंटन प्राप्त है ।

2. अस्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, जमुई क्षेत्रान्तर्गत कुल 30 वार्डों में पक्की गली-नली योजनाओं पर किये गये कार्यों के विरूद्ध वर्तमान में कोई भी भुगतान लंबित नहीं है ।

3. उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, सरासर माननीय मंत्री जी को झूठा प्रतिवेदन विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसका कि हम उदाहरण देना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी बतावें

कि आप तो कहे हैं कि 30 वार्डों में काम चल रहा है, आप बोल रहे हैं, आपके विभाग के जो भी कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, वे दे दिये होंगे और आप उसको सदन में रखने का काम किये । लेकिन इससे जो शर्म की बात हमको लगता है कि सफेद झूठ और ऐसे पदाधिकारी को आपको दंडित करना चाहिए । हम चुनौती देते हैं कि एक भी वार्ड में काम नहीं चल रहा है, आप एक कमिटी सदन का बना दीजिए और कल चलें हमलोग और यदि चलता होगा तो आप हमको बताईयेगा, जो दंड दीजियेगा, हम स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे । एक मिनट महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए न । आप कहां बीच में उठ गये ?

श्री विजय प्रकाश : महोदय, एक भी वार्ड में काम नहीं चल रहा है और दूसरा आपके माध्यम से महोदय हम पूछना चाहते हैं कि खंड-2 के बारे में, एक मिनट...

अध्यक्ष : रूकिए न, एक मिनट सुन लीजिए न । आपका प्रश्न है, आपने कहा है कि 17 में से 15 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया है ।

श्री विजय प्रकाश : हम उसी पर आ रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : आपने कहा कि जो कार्य पूर्ण हो गया, उसका भुगतान नहीं हो रहा है । आपका प्रश्न मूल है और अभी जो आप कह रहे हैं, काम नहीं चल रहा है या कहां रुका हुआ है । अभी आपका प्रश्न यह है कि जो काम पूरा हो गया, उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं तो मंत्री जी ने कहा कि कोई भुगतान लंबित नहीं है तो आप उसके लिए पूछिए, कौन से भुगतान की प्रक्रिया कब से पूरी है और मंत्री जी उसकी निश्चित जॉंच करायेंगे । अगर कोई भी पदाधिकारी, विजय प्रकाश जी वैसे भी स्पष्ट बात है, सरकार इतना जरूर सचेत रहेगी कि कोई अधिकारी किसी प्रश्न के जवाब में इस सदन को मिसलीड करने के लिए या गलत सूचना देते हैं तो यह सरकार की स्वाभाविक जिम्मेवारी है कि उस अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए । इसलिए आपका प्रश्न है कि कार्य पूरा हो गया है, भुगतान नहीं हो रहा है, मंत्री जी ने कहा कोई भुगतान लंबित नहीं है, आप उसकी सूचना दीजिए, ये जॉंच करायेंगे, अगर भुगतान लंबित होगा कार्य पूर्ण होने के बाद तो निश्चित रूप से उसपर कार्रवाई करेंगे गलत सूचना क्यों दिये, इसके अलावा क्या उपाय है ?

श्री विजय प्रकाश : महोदय, उसी पर तो हम आ रहे थे, खंड-1 में जो उन्होंने जवाब दिया, उसका हम जवाब दिये । दूसरा खंड-2 के बारे में जो इन्होंने माननीय मंत्री जी बताने का काम किया कि 17 वार्डों में सभी का भुगतान हो गया है, हम चैलेंज करते हैं कि 17 वार्डों में 15 वार्डों में जो नली-गली का कार्य हुआ, जिसका आप

कह रहे हैं कि भुगतान हुआ है, हमारे पास खाता नम्बर 7500 रू0 के हिसाब से अभी तक पेमेंट हुआ है, कनीय अभियंता को 4 लाख रू0 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, जिसका खाता संख्या भी है, चेक संख्या भी है तो उसके बाद 15 काम का जब नेक्सट पैसा मांग रहा है तो कह रहा है कि फाईल गायब है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह संचिका कहां गायब है, 15 काम का जिसमें कि एडवांस 7500 रू0 चेक के माध्यम से पैसा मिला जो कि मेरे पास है । इन कार्यों का पैसा कहां गया और कहां संचिका है......

अध्यक्ष : विजय प्रकाश जी, यह आप सूचना मंत्री जी को दे दीजिए, ये उसकी जॉच करवायेंगे ।

श्री विजय प्रकाश : जॉच करवायेंगे लेकिन इनको दिग्भ्रमित करने का काम वहां के कार्यपालक पदाधिकारी .....

अध्यक्ष : साबित होगा दिग्भ्रमित करने का तब न, आप उसको दे दीजिए, मंत्री जी उसकी जॉच करायेंगे ।

श्री विजय प्रकाश : हम दे देंगे लेकिन महोदय ......

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-943 श्री गुलाब यादव ।

श्री विजय प्रकाश : नहीं महोदय, दिग्भ्रमित करने वाले जो पदाधिकारी हैं, आपको क्यों गलत सूचना देने का काम किए और उसपर क्या कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी बतायें?

अध्यक्ष : पहले सूचना गलत साबित होगी तब न कार्रवाई करेंगे ! आपको कह रहे हैं कि जॉच करायेंगे ।

श्री विजय प्रकाश : तो ये बतायें कि यदि सूचना गलत साबित होगी तो क्या कार्रवाई करेंगे, यह तो बता दें ।

अध्यक्ष : आप आसन का सुनिए न । अगर सूचना गलत साबित हुई तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी । अब श्री गुलाब यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-943 (श्री गुलाब यादव)</u>

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर किया गया है माईनर इर्रीगेशन में महोदय, लघु जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-944. (श्री अशोक कुमार सिंह)</u>

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है,

2. आंशिक अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि 10.5 एच0पी0 का मोटर बोर में गिर जाने के कारण वर्तमान में 5 एच0पी0 के मोटर से जलापूर्ति की जा रही है । गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे जाने पर टैंकर से भी जलापूर्ति की जा रही है ।

3. वर्तमान बोरिंग से कम डिसचार्ज के कारण एक अतिरिक्त बोरिंग के निर्माण हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी सूचना सदन में वर्ष 17-18 में भी तारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार को दिया था । उस समय लिखित सरकार का हमें आश्वासन मिला था कि अगले वित्तीय वर्ष में नया बोर कराकर और उत्तम क्षमता का मोटर लगाकर और बाजारवासियों को पेयजल आपूर्ति दी जाएगी, अब तक पूरा नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न, आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अस्वीकारात्मक है । मैं जानना यह चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री मंत्री जी से कि कब तक वहां नया बोर करके और बाजारवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी प्रखंड मुख्यालय में और प्रतिदिन वहां दो टैंकर पानी जाता है, इसके बावजूद भी बाजारवासियों को पानी नहीं मिल पाता है । पूरे इलाके के लोग पानी के चलते परेशान हैं । मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कब तक इसको बोर करा देंगे ?

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार के हर घर, नल योजना के तहत दुर्गावति ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादित 5 वॉर्डों के सभी घरों में टैंक के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराने हेतु 57.76 लाख की योजना स्वीकृत है और अप्रैल, 2020 तक उसे हर घर जल देने का लक्ष्य है । लेकिन पुराने बोरिंग की क्षमता कम हो गई है । इसीलिए अतिरिक्त एक नया बोरिंग करने हेतु 17 लाख 65 हजार रुपए की एक नई बोरिंग निर्माण हेतु विभाग ने निदेश दे दिया है । प्राक्कलन स्वीकृत कर निर्देश दे दिया है ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से कि जो पुरानी जलापूर्ति योजना है, उसमें 50 लाख का पाईप लाइन का एक्सटेंशन का डी0पी0आर0 बनाया है सरकार ने, एकरनामा भी कर लिया है । जब कि उसका बोर ही खराब है । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो 50 लाख रुपए अतिरिक्त पाईप लाइन बिछाने के लिए व्यय कर रही है और जहां तक पाईप बिछा हुआ है, बाजारवासियों को पानी नहीं मिल रहा है तो मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या इस गर्मी के मौसम से पहले नया बोर कराकर उसमें 12 एच0पी0 का मोटर डालेगी ....

अध्यक्ष : उसमें मंत्री जी तो बता ही रहे हैं कि एक एडिशनल करा रहे हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरे वार्डों की बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, उस पंचायत के दूसरे वार्डों की बात कर रहे हैं, मैं बाजार की बात कर रहा हूं । जहां आपका जलापूर्ति योजना लगा हुआ है, वहां नल-जल की योजना सरकार नहीं लगा रही है । मैं पुराने जलापूर्ति योजना की बात कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री अशोक कुमार सिंह : हम चाहते हैं कि गर्मी के मौसम से पहले वहां नया बोर कराकर बाजारवासियों को पेयजल दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी इसको देखवा कर करवा दीजियेगा ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : ठीक है, करवा देंगे ।

टर्न-6/शंभु-धिरेन्द्र/05.03.20

तारांकित प्रश्न सं0 -945 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सिवान जिला के वसंतपुर प्रखंड में पूर्व से निर्गत राशन कार्डों की संख्या निम्नवत है । प्रखंड वसंतपुर पूर्वीक्ता प्राप्त राशन कार्ड संख्या 12731, अंत्योदय राशन कार्ड 1752, कुल राशन कार्ड 14483 । साथ ही जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड वसंतपुर के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नये राशन कार्ड हेतु कुल 5661 आवेदन प्राप्त है । कुल प्राप्त आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया है । जिसमें से कुल 2881 स्वीकृत किया गया है । शेष 2780 को अपात्र पाया गया है, पूर्व से राशन कार्ड निर्गत होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है । स्वीकृत आवेदनों के विरूद्ध 2508 राशन कार्ड निर्गत करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और शेष जो भी अगर इसके बावजूद छूटे होंगे तो उसके लिए भी विभाग स्तर पर प्रावधान है कि आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर आवेदन देंगे और उनको राशन कार्ड निर्गत होगा ।

अध्यक्ष : आप माईक पर बोलिये ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, मंत्री जी ने जो पढ़ा है मैं जिस पर अभियोग लगाया हूँ, उसी का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं । जिसको मैंने स्वयं चोर कहा, वो अपने को साबित करेगा कि हम चोर हैं, इनकी ये रिपोर्ट जिला के..........

अध्यक्ष : आपने किसी पर अभियोग कहाॅं लगाया है, आपने तो कहा है कि लोगों को राशन कार्ड मिला और मंत्री जी ने बताया है कि कितने आवेदन आये हैं कितनों को दिया गया है कितने को नहीं दिया गया है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अभियोग है कि सरकारी आदेश के अनुसार जिनका राशन कार्ड में नाम छूट गया है, उनसे आवेदन ली गई 6 माह पहले, बोड़ा में कस कर रखा गया प्रखंडों में जॉंच के लिए, 6 माह हो गया अप्लिकेशन आर0टी0पी0एस0 से दिया हुआ और जॉंच नहीं हुआ ....

अध्यक्ष : जॉंच करके उन्होंने बताया तो, दिया है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, गलत बोल रहे हैं । मैं कहता हूँ कि वो मेरा हेड क्वाटर है और मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं डी0एम0 का तो ये सच बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन में कोई झूठ नहीं बोलते हैं, जैसे आप नहीं झूठ बोलते हैं, वैसे कोई झूठ नहीं बोलते हैं ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, जो रिपोर्ट कलेक्टर साहब का है न, वो टोटल गलत है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ये जॉंच किसी वरीय पदाधिकारी से कराया जाय, कमिश्नर लेवल से ।

अध्यक्ष : ठीक है । मंत्री जी, किसी वरीय अधिकारी से जॉंच करा दें ।

श्री भोला यादव : मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है, जहॉं कि राशन कार्ड के लिए अप्लाई लोग किया हो और उसको ससमय मिला हो । हमारे जिले के ही माननीय मंत्री जी हैं दरभंगा की स्थिति यह है जो कोई पंचायत, कोई गॉंव नहीं है, जहॉं आवेदन लंबित हो । क्या माननीय मंत्री जी, ब्लॉक वाइज या पंचायत वाइज कोई स्पेशल कैंप लगा कर राशन कार्ड का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगें ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, पहले से हमलोगों ने व्यवस्था किया और इसी व्यवस्था के तहत पहले से तो 8 करोड़ 57 लाख और 1 करोड़ 62, अभी 1 करोड़ 68 लाख फैमली हो गया है राशन कार्ड हो गया है और लगभग 9 करोड़ लोगों को राशन कार्ड दे रहे हैं । उसके बावजूद भी हमलोग..........

अध्यक्ष : माननीय सदस्य की जो चिंता है वो जो छूटे हुए है उन लोगों की व्यवस्था करें ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उन्हीं की तो बात हम लोग कर रहे हैं । उन्हीं लोगों की व्यवस्था की गई है जो छूटे हुए हैं उसी को तो 10 लाख राशन कार्ड हमलोग दिये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अब नहीं । अब बात आगे बढ़ गयी । देख रहे हैं न भोला जी क्यों नहीं हम आपको दे रहे थे ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं - 946 (श्री शमीम अहमद)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, खण्ड - (क) अस्वीकारात्मक है ।

खण्ड-(ख) अस्वीकारात्मक है । महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा कोठी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय कार्यरत है । यह महाविद्यालय डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधीन संचालित है । इसलिए नया कॉलेज खोलने का मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पठन-पाठन का कार्यक्रम चल रहा है तो अभी तक 2019-20 में कितने बच्चे हैं और 2020-21 में कितने बच्चे हैं ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, इनके द्वारा जो प्रश्न किया गया था वो कृषि कॉलेज खोलने के संबंध में था लेकिन महोदय, मैं बताया कि पूर्वी चम्पारण जिला के पीपराकोठी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय वहाँ कार्यरत है । यह महाविद्यालय डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से संचालित है । अब महोदय, ब्योरा चाह रहे हैं । हम ब्योरा मंगवा लेते हैं और माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं - 947 (श्री संजय सरावगी)

श्री संजय सरावगी : इस प्रश्न में मैंने दो नालों का......

अध्यक्ष : मंत्री जी को जवाब देने दीजिए न ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा : महोदय, खण्ड-1 उत्तर स्वीकारात्मक है । कार्यपालक अभियंता बुडको, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में वर्णित योजना नगर निगम, दरभंगा के बोर्ड द्वारा चयन किया जा चुका है । अत: प्राक्कलन तैयार कर बुडको, दरभंगा के पत्रांक 45 दिनांक 01.01.2020 द्वारा तकनीकी स्वीकृति हेतु, प्रबंध निदेशक बुडको को समर्पित किया गया है । यह योजना प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में है । प्राथमिकता अनुसार इस योजना का क्रियान्वयन उपलब्ध राशि के आलोक में कराया जाएगा ।

खण्ड - 2, वस्तुस्थिति उपर्युक्त खण्डों में स्पष्ट कर दी जा चुकी है ।

खण्ड - 3, वस्तुस्थिति उपर्युक्त खण्डों में स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में, मैंने दो नालों का प्रश्न पूछा था, जो मेरे हाथ में है और आपके ही निर्देश पर कि आप दो नालों के लिए पूछ सकते हैं,

पहले हमलोग पाँच-छः-सात पूछते थे । उसमें से एक नाला जो है जो प्रश्न का प्रिंटिंग आया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है और वह काट दिया गया, पता नहीं किस स्तर पर कटा । एक दूसरा नाला है वॉर्ड नं0 44 बलभद्रपुर में एल0आई0सी0 चौक, पोखरिया महाविद्यालय एन0पी0 मिश्रा चौक के पास ब्रह्मस्थान तक नाला निर्माण और ये भी मेरे मूल प्रश्न में है और दूसरा प्रश्न है जो महोदय, इसपर भी माननीय मंत्री जी पूर्व में आश्वासन दिये थे कि राशि की उपलब्धता के आधार पर इसको बनवा देंगे । आज फिर माननीय मंत्री जी....

अध्यक्ष : अभी भी माननीय मंत्री जी अपनी बात पर कायम हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी फिर बोले, एक तो मेरा दूसरा नाला है उसको भी प्रोसिडिंग में जोड़वा दिया जाए और फिर माननीय मंत्री जी बोल रहे है कि राशि की उपलब्धता के आधार पर । अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा बजट है और ये छोटा-मोटा नाला है और इसमें जोड़ देते हैं राशि की उपलब्धता के आधार पर, तो सरकार के पास.....

अध्यक्ष : मंत्री जी इनको दिखवा लीजिए, पिछली बार भी.........

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों नाला इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा : महोदय, हमने कहा है हम इस नाले को दिखवा लेंगे, इसी वित्तीय वर्ष में इसको कराने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं - 948 (श्री मदन मोहन तिवारी)</u>

अध्यक्ष : अंतिम प्रश्न ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, लौरिया प्रखंड में मिट्टी जॉच प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया है । पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत जिला स्तरीय मिट्टी जॉच प्रयोगशाला कार्यरत है । जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से मिट्टी प्राप्त कर, उसकी जॉच कर कृषकों के बीच मृदा स्वास्थ कार्ड वितरित किया जाता है । लौरिया प्रखंड के किसानों के मिट्टी के नमूने का जॉच भी जिला स्तरीय मिट्टी जॉच प्रयोगशाला में की जाती है । लौरिया प्रखंड में मृदा स्वास्थ कार्ड वितरण की स्थिति निम्न है :- वर्ष 2016-17 में लक्ष्य था 1703 और संकलन हुआ है 1703 । विश्लेषण हुआ है 1703 और कार्ड वितरण हुआ है 6769 । लौरिया में 2017-18 में 1562 लक्ष्य था और 1387 संकलन किया गया है और 1381 का विश्लेषण किया गया और कार्ड वितरण हुआ है 1847 । वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर मिट्टी जॉच प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव

विचाराधीन नहीं है । महोदय, सवाल उठाया गया था कि लौरिया में 2000 में प्रयोगशाला खोला गया था । इसकी हम जॉच करा लेते है, जॉच कराने के बाद हमारा प्रयास होगा कि वहॉ पर भी व्यवस्था हो ।

टर्न-7/05-03-2020/ज्योति-पुलकित

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मझौलिया प्रखंड का है और मंत्री जी लौरिया का जवाब दे रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न देख लीजिये प्रिन्टिंग में क्या है महोदय ? क्या यह है बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया प्रखंड मुख्यालय में एन.आई.पी. योजना मद की 8 लाख रुपये की लागत से ...

अध्यक्ष : लगता है कि प्रश्न के भेजे जाने में त्रुटि है लेकिन प्रश्न में मझौलिया ही है । ठीक है, इस प्रश्न को स्थगित करके अगली तिथि को मझौलिया के बारे में कर लीजिये ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनाँक 5 मार्च, 2020 के लिए ...

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप कहां खड़े हो गए ? वह क्या है उसमें क्या लिखा हुआ है आपको पता है कि नहीं ? जो कागज रखे हैं उसमें क्या है ? वो बात कार्य स्थगन की है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और बाकी सब प्रश्न को छोड़ दीजिये, कार्य स्थगित कर दीजिये । कार्य स्थगन की मर्यादा भी रहने दीजिये । नहीं, पहले आप सुन तो लीजिये ।

(व्यवधान)

आपके कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना अमान्य कर दी गयी है । अब शून्यकाल।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में डाक बंगला रोड में बारी फार्मेसी के पास मुख्य नाला लगभग पचास वर्षों से निजी जमीन में बह रहा है । शहर की आबादी बढ़ने से जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम तो उनको कह रहे थे कि बैठिये पहले उनको बैठाईये । यही बात पहले मान लेते तो इतना समय सदन का नहीं बर्बाद होता । फिर आप खड़े हो जा रहे हैं, हम कहेंगे तब खड़े होंगे । भाई वीरेन्द्र जी कहे कि खड़े हो जाईये, बैठ जाईये तब मत मानिये । ये कहते हैं कि खड़े हो जाईये तो खड़े हो जाते हैं आप स्थिर से बैठे रहें जब कहेगें तो खड़े होइयेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है, पहले हम अपना नियमन कर देंगे । मेरा नियमन सुनेंगे कि इनकी सुनेंगे? पहले हम सदन को बता तो दें कि आपसे सूचना मिली है और बिना बताए आप सूचना पढ़ने लगते हैं ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 5 मार्च, 2020 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री उपेन्द्र पासवान, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री मो0 नवाज आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री शमीम अहमद, श्री सुधीर कुमार एवं श्री फराज फातमी ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान तथा राजकीय विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया

तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

समझ गए ना ? क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री महबूब आलम : महोदय, देश का सातवां पुराना पटना विश्वविद्यालय आज तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है । जबकि यह बिहार की जनता की लोकप्रिय मांगों में एक नहीं है । केन्द्रीय विश्वविद्यालय ना होने के कारण विश्वविद्यालय को कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है । उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन लगातार जारी है, खुद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग उठाई थी । लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली-पटना में डबल इंजन की सरकार होने के बाबजूद इस अत्यंत लोकप्रिय मांग को अनसुना किया जा रहा है ।

अध्यक्ष: अब शून्यकाल ।

शून्यकाल

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में डाक बंगला रोड में बारी फार्मेसी के पास मुख्य नाला लगभग 50 पचास वर्षो से निजी जमीन में बह रहा है । शहर की आबादी बढ़ने से जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गयी है । जनहित में अविलम्ब जल निकासी हेतु नाला निर्माण की माँग करता हूँ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: महोदय, महागठबंधन की सरकार में बक्सर सदन प्रखण्ड के किला मैदान के सौन्दर्यीकरण हेतु 1 करोड़ 25 लाख की राशि प्रदान की गई थी । लेकिन वो राशि अभी तक जिला में नहीं दी गई है । उक्त राशि को अविलम्ब जिला में भेजा जाय ।

डा0 शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, नरकटिया विधान सभा के छौड़ादानो प्रखण्ड के छौड़ादानो तियर नदी पर बना सेवा पथ क्षतिग्रस्त हो गया है । सेवा पथ के जगह आर0सी0सी0 पुल एवं सुलीस गेट बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी: जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड के पंचायत गोली में बाड़ाघाट योजना एकतरवा बड़मसिया के बीच में हदहदवा नदी में बांधा का निर्माण करावें।

श्री समीर कुमार महासेठ: श्री बच्चन पूर्वे, शिक्षक प्राथमिक विद्यालय, मधुबनीटोला, कलुआही, प्रखंड, मधुबनी, 31.05.2000 को सेवानिवृत्त हुए । डी0पी0ओ0 के ज्ञापांक-

2777, दिनांक- 03.09.2016 द्वारा उनको प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति मिली परंतु अंतर वेतन की राशि का भुगतान आजतक नहीं हुआ । श्री पूर्वे को अंतर वेतन की राशि का भुगतान कराया जाये ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में निर्मित बहुमंजिला मार्केट जिसमें 100 से ज्यादा दुकान में दुकानदार अपना रोजगार करते हैं । मूलभूत सुविधा रहित जर्जर भवन के कारण कभी भी बाजार में घटना दुर्घटना हो सकती है । अत: उक्त बाजार का शीघ्र जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमति भागीरथी देवी: माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामनगर एवं गौनाहा के नियोजित शिक्षकों को पुराने नियमित शिक्षकों को भाँति सेवा शर्त, वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा समान काम के बदले समान वेतन की मैं माँग करती हूँ ।

श्री शत्रुघ्न तिवारी: अध्यक्ष महोदय, राज्य में 17 फरवरी से शिक्षकों की हड़ताल के कारण विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य बंद है । मार्च महीने में विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा होती है । मैं राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के हित में शिक्षकों की हड़ताल समाप्त कराने की माँग करता हूँ ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, प्रदेश के सभी जिलों में जिस प्रकार से उर्दू, बांग्ला भाषाओं के शिक्षकों की बहाली की जाती है । वैसे ही प्रदेश के सभी प्राथमिक, मध्य विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत विषय के शिक्षकों की बहाली की जाय ।

श्री ललन पासवान : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के सोन उच्च स्तरीय नहर लोजी से निकलने वाली तेलारी वितरणी में गाद भर जाने से नीचले छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है । पटवन बाधित है, उक्त वितरणी की सफाई हेतु माँग करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉ राजाबाजार पटना द्वारा वर्ष 2018 में करीब 1200 छात्रों का नामांकन अपनी मान्यता मगध यूनिवर्सिटी से बतलाकर किया गया तथा फीस लिया गया है, परन्तु अभी तक न पंजीकरण किया गया न परीक्षा लिया गया है । इसकी जाँच करवाकर नामित छात्रों के भविष्य को बचाने की मांग करता हूँ ।

टर्न : 08/कृष्ण/05.03.2020

श्री मो0 नेमतुल्लाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपाालगंज जिला के बरौली प्रखंड मुख्यालय में मध्य विद्यालय, बरौली के प्रांगण में अनुसूचित जाति का छात्रावास अत्यंत जर्जर स्थिति में है । इस छात्रावास का पुन: निर्माण सरकार शीघ्र करावे ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बूढ़ी गंडक सिकरहना बायां तटबंध- लहलादपुर से जालिमपुर एवं दायां तटबंध - वारगंज से सेमरा तक जर्जर होने से वर्षा के दिनों में टूटने से बाढ़ की संभावना बनी रहती है एवं आवागमन भी बाधित है । उक्त दोनों तटबंधों का मरम्मति कर पक्कीकरण करावें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण के चकिया एवं मोतिहारी चीनी मिल बंद होने से इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । यहां 60 प्रतिशत गन्ना का उत्पादन होता है ।

चकिया या कल्याणपुर में नई चीनी मिल लगाकर गन्ना कृषकों के समस्या के समाधान हेतु मांग करता हूं ।

श्री मो0 महबूब आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के सातवॉं पुराना पटना विश्वविद्यालय आज तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन सका जबकि यह जनता की लोकप्रिय मांगों में यह एक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कार्य-स्थगन में भी इसको उठाये हैं । माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी, आप ही इनको समझाईये ।

श्री उपेन्द्र पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के गढ़पूरा प्रखंड के ग्राम पंचायत सोनमा के रामसोगारथ पासवान की मृत्यु दिल्ली के भजनपुरा के हिंसा में हो गयी है, जो सरकारी विद्यालय के पांचवी के छात्र थे । मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रूप्ये मुआवजा देने के लिये मांग करता हूं।

श्री मो0 नवाज आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा शहरी क्षेत्र के बिहिरी लख से बहिरो गांव तक पथ निर्माण कार्य आरा नगर निगम द्वारा कराना है लेकिन पथ का कार्य प्रारंभ होकर एक वर्ष से बंद है । इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई एवं अविलंब कार्य पूर्ण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत गोपालपुर थाना के ग्राम पंचायत तिनटंगा करारी को टंगरा अंचल से हटा कर पूर्ववत् गोपालपुर अंचल में जनहित में करने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष, महोदय, गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड के अंतर्गत गंडक नदी के किनारे बंगराघाट पुल और सतरघाट पुल के समीप लाखों हिन्दुओं के अंतिम संस्कार हेतु केन्द्र सरकार के नमामी गंगे परियोजना को राज्य सरकार द्वारा विस्तृत प्रस्ताव भेजकर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण शीघ्र कराया जाय ।

श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत जिला सहकारिता पदाधिकारी के गलत नीति के कारण जिला के किसानों का धान पैक्स के माध्यम से नहीं लिया जा रहा है और जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा 40 रूपया प्रति क्वींटल वसूली किया जा रहा है । जिला सहकारिता पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की मांग करता हं ।

श्री फराज फातमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत वर्ष 2019 में दरभंगा सहित संपूर्ण उत्तरी बिहार क्षेत्र बाढ़ की चपेट में घिरा था । सरकार की ओर से दी जानेवाली मुआवजा राशि प्रखंड केवटी एवं सिंहवाड़ा के लगभग 10 प्रतिशत लोगों को अबतक उपलब्ध नहीं हो सकी । अत: वंचित लोगों को मुआवजा राशि उपलब्ध करायी जाय ।

श्री जफर आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपरु अनुमंडल में डीलर रहते चार किलोमीटर नदी पार डीलर से जोड़ा गया, एक डीलर को आधा, दूसरे को साढ़े तीन वार्ड, एक को बारह, दूसरे को एक वार्ड, डीलर अपना राशन दूसरे डीलर से लेते हैं । सरकार चार माह के आवंटित सूची की जांच कराये।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के बुधनगरा घाट पर बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण की पुरानी मांग रही है, उपरोक्त पुल के निर्माण की घोषणा कभी एक बार बिहार सरकार द्वारा की गयी है, इसको लेकर स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन भी चल रहे हैं ।

बुधनगरा घाट पर अतिशीघ्र पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत पूणियां विश्वविद्यालय के अधीन फारबिसगंज कॉलेज, फारबिसगंज में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने से इस क्षेत्र के गरीब एवं निर्धन छात्र हेतु स्नातकोत्तर की पढ़ाई अगले सत्र से प्रारंभ की मांग करते हैं ।

श्री तार किशोर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के कटिहार नगर सहित सभी नगरों में वर्षा के समय जल-जमाव से आम नागरिकों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने हेतु नालों की जल निकासी के लिये नालों की सफाई एवं जीर्णोद्धार हेतु सरकार विशेष अभियान चलावे तथा कटिहार में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम कार्य प्रारंभ करे।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण-सूचना । सर्वश्री मिथिलेश तिवारी, श्याम बाबू प्रसाद यादव एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त सूचना । श्री मिथिलेश तिवारी, पढ़ें ।

(व्यवधान)

क्या है ? निर्णय नहीं हुआ है कि आप दोनों में से कौन बोलेंगे ?

श्री विजय शंकर दूबे, अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक ध्यानाकर्षण-सूचना दिया था आज के लिये, जो अमान्य हो गया है । महोदय, उस घटना में बिजली के 11000 वोल्ट के करेंट की वजह से, चूंकि लो लैंड तार था, डी0जे0 में तार सट गया, जिससे ट्रॉली में आग लग गयी और तीन बच्चे ऑन स्पॉट जल करके मर गये, 5 लोग 30 परसेंट से ऊपर जलकर घायल हो गये हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरा डिटेल्स सरकार को दे दीजिये, सरकार उसको देखेगी ।

(व्यवधान)

आप क्या चाहते हैं कि सरकार संज्ञान नहीं ले ? तो वही कह देते हैं । हमने विषय की गंभीरता को देखते ही कहा है कि आप पूरा डिटेल्स सरकार को दीजिये, सरकार इसका संज्ञान लेगी ।

माननीय सदस्य दूबे जी, आप बहुत पुराने सदस्य हैं । ध्यानाकर्षण-सूचना स्वीकृत कराने का यह तरीका नहीं होता है और ऐसे में ध्यानाकर्षण-सूचना स्वीकृत नहीं होती है । आप ने शून्यकाल के दरम्यान इसको उठाया है, आपकी बात को हमने कहा है कि सरकार संज्ञान लेगी । अब आप यहां बात उठाकर ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत कराईये, आसन से चाहिएगा कि हमारा स्वीकृत कीजिये तो यह तरीका सही नहीं है ।

माननीय श्री सदानन्द बाबू, आप बोलिये ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर उठता नहीं, नियमानुकूल नहीं है । लेकिन यह घटना अतिसंवेदनशील है और इस अतिसंवेदनशील मामले में विभाग जिस तरह का रवैया अपनाये हुये है, जिस तरह वहां लोगों की वहां मृत्यु हो गयी, लोगों ने बहुत पहले ही लिखकर दिया था, हाई टेंशन/वोल्टेज की जो तार है, वह बहुत लो लैंड पर है लेकिन उसको हटाया नहीं गया और आजतक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई । तीन बच्चों की मृत्यु और फिर झुलसे हुये लोग ...

अध्यक्ष : सरकार इसको देख लेगी ।

श्री सदानन्द सिंह : तो सरकार इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई कर उत्तर दे ।

अध्यक्ष : चलिये माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी, आप ध्यानाकर्षण-सूचना पढ़िये।

टर्न-9/अंजनी-अभिनीत/5.03.2020

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री मिथिलेश तिवारी, श्यामबाबू प्रसाद यादव एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(शिक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों में रसोईयों को खाना बनाने हेतु 1500 (एक हजार पांच सौ) रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जिससे रसोईयों को जीवनयापन में परेशानी हो रही है एवं उनके कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने अकुशल मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी 268 रूपये प्रतिदिन तय किया है जबकि रसोईयों को मजदूरी प्रतिदिन लगभग 45 रूपये ही मिलता है, जो कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है।

अतएव सरकार के तय मानक के अनुरूप कम-से-कम न्यूनतम मजदूरी सभी रसोइयों को उपलबध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है । संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पत्र संख्या-सो एण्ड सो, दिनांक 01.03.2017 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रत्येक रसोईया-सह-सहायक का कार्य अंशकालिक कार्य मानते हुए एक हजार रूपये मानदेय पर रखा गया है । इस एक हजार रूपये में 600 रूपये केन्द्र सरकार देती है एवं 400 रूपया राज्य सरकार वहन करती है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय एक हजार रूपये के अतिरिक्त प्रत्येक रसोईया-सह-सहायक को प्रति माह राज्य निधि से 500 रूपये टॉपअप के रूप में दिया जा रहा है । इस प्रकार वर्त्तमान में रसोईया-सह-सहायक को 1500 रूपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है । इसमें राज्य सरकार 900 रूपये वहन कर रही है । रसोईया-सह-सहायक का मानदेय वृद्धि करने हेतु निदेशालय के पत्रांक 395 दिनांक 05.03.2018, पत्रांक 469 दिनांक 15.03.2018 और पत्रांक 2017 दिनांक 31.01.2019 एवं पत्रांक 2695 दिनांक 22.11.2019 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इनके मानदेय का वृद्धि कर न्यूनतम दो हजार रूपये कर दिया जाय । भारत सरकार से इस बारे में अभी कोई निर्णय संसूचित नहीं है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां हमलोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, हमलोग चूंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिदिन हमलोगों का घेराव होता है तो माननीय मंत्री जी ने दो हजार रूपया का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जरूर भेजा है लेकिन कई ऐसी योजनायें हैं, जो सरकार अपने संसाधन से भी चला रही है । मसलन प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अलावे मुख्यमंत्री आवास योजना भी चला रहे हैं, सभी को पेंशन दे रहे हैं तो सरकार थोड़ा बड़ा दिल दिखाये इस मामले में । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम-से-कम न्यूनतम मजदूरी दिया जाय, वे अकुशल मजदूर नहीं हैं, वे बहुत बढ़िया से अच्छा खाना बनाकर बच्चों को खिलाती है, एक तरह से वे पूरी तरह से एक मां का रोल रसोईया के द्वारा वहन किया जाता है तो हमलोगों को इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार से जो मांगना है, वह आप जरूर मांगिए लेकिन राज्य सरकार की ओर से कम-से-कम उनको न्यूनतम मजदूरी जरूर दिया जाय, इसका मैं आग्रह जरूर माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से करेंगे ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, रसोईया को दस महीने का ही पेमेंट किया जाता है और जबकि वे 12 महीना काम करती हैं ।

अध्यक्ष : आप सूचना दे दीजिएगा ।

सर्वश्री राजेश कुमार, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी जिलों में लगभग 114000 वार्ड सचिव पिछले 2-3 वर्षों से चलाई जा रही सात निश्चय योजना के तहत गली-नली एवं हर घर नल का जल योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, जिसके बदले उन्हें आज तक कोई भी मानदेय भत्ता के रूप में राशि नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बिहार राज्य के वार्ड सचिव आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं।

अत: बिहार राज्य के वार्ड सचिवों को मानदेय या भत्ता के रूप में राशि दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री कपिल देव कामत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के अधिसूचना सं0-5685 दिनांक 28.06.2017 के कंडिका-04 में वार्ड सचिवों के चयन की व्यवस्था प्रावधानित है। जन भागीदारी के आधार पर अपने ही राजस्व ग्राम के संबंधित वार्ड के अंतर्गत ही वार्ड सचिवों से कार्य लिया जाता है। यथा प्रावधानित व्यवस्था के आधार पर उनके

लिए कोई स्थाई तौर पर मानदेय अथवा संविदा आधारित नियोजन की राशि नियत नहीं है। विभागीय पत्रांक-1153 दिनांक-13.02.2019 के कंडिका-5 एवं 6 में प्रावधानित है कि यदि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति चाहे तो वार्ड सचिव को ही अनुरक्षक के रूप में वार्ड सभा की सहमति से अनुबंधित किया जा सकता है। जिसको 500/- रू0 मासिक रिटेनर शुल्क एवं राज्य सरकार द्वारा परामर्शित मद से 1000/- रू0 प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जितने भी वार्ड सचिव हैं, वे वार्ड सचिव आपके साथ सात निश्चय योजना को सफल बनाने में इनकी अह्म भूमिका रही है और जैसा कि सरकार कह रही है कि इनके लिए कोई मानदेय नहीं है तो ये भी कहीं-न-कहीं सरकार के कामों में, जनहित के कामों में लगे हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुफ्त में इनसे काम करा रहे हैं तो कोई भी आदमी एक दिन का देहारी भी करता है तो उनको आशा रहती है कि तीन सौ, चार सौ, पांच सौ रूपये मिलेंगे और आपकी इतनी ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है और इनको आप कोई भी आर्थिक मदद नहीं करना चाह रहे हैं और उसमें भी सरकार कह रही है कि पांच सौ रूपया, हजार रूपया....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : एक मिनट सर । महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि सरकार को इसमें देने में कोई परेशानी तो नहीं है, चूंकि आपके योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, तो क्या सरकार देने का विचार रखती है और यदि विचार रखती है तो सदन में सरकार कहे कि इनको कोई निश्चित मापदंड पर मानदेय भत्ता देंगे ।

श्री कपिल देव कामत, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति को प्रति माह 500 रूपये तथा रिटेनर शुल्क एक हजार रूपया परामर्शित मद के रूप में राशि दी जा रही है । वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सहमति से अनुरक्षक के रूप में वार्ड सचिव को भी रखा जा सकता है और उसका लाभ उन्हें प्रदान किया जा सकता है ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : यह आपका अंतिम पूरक है ।

श्री राजेश कुमार : माननीय मंत्री जी मानदेय के संबंध में कह रहे हैं कि वार्ड क्रियान्वयन का तो यह भी उनको नहीं मिल रहा है, उनके पास तो आर्थिक तंगी है, वे इस आशा में काम कर रहे हैं कि सरकार हमको पैसा देगी । जो तय मापदंड सरकार जो कह रही है, वह भी उनको नहीं मिल रहा है, उसको भी तो वे नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष : आप पूरक न पूछिए कि सरकार इसको सुनिश्चित कराये ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो तय मापदंड है, उसको भी तो रेगुलराइज कराये ।

टर्न-10/राजेश-राहुल/5.3.20

श्री फराज फातमी: महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है, एक लाख 14 हजार हमारे तकरीबन जो वार्ड सचिव हैं, जैसा कि अभी सरकार ने उत्तर दिया, मैं सरकार का उत्तर सुन रहा था अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जबकि सरकार बिहार में 7 निश्चय के तहत जो भी क्रियान्वयन चल रहा है, जो भी कार्यक्रम चल रहा है पंचायत में इन्हीं वार्ड सचिवों के द्वारा चलता है और चलाया जाता है और जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एक हजार और 500 रुपये तकरीबन 1500/-रुपये हम मानदेय देने का काम करेंगे तो आज के जमाने में जबकि इतनी मँहगाई है, तो मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि क्या सरकार कोई आगे की रणनीति या पॉलिसी बनाना चाहती है कि मानदेय को बढ़ाया जाय.............

(व्यवधान)

अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजा है ।

श्री फराज फातमी: जी सर । अध्यक्ष महोदय, कब तक ?

अध्यक्ष: यह तो उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा में हैं भारत सरकार से ।

श्री फराज फातमी: महोदय, कोई समय-सीमा तय कर दें कि कब तक यह हो जायेगा ?

अध्यक्ष: भारत सरकार कब तक रेसपौंस करेगी, यह माननीय मंत्री जी कैसे तय करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर पंचायती राज के बारे में स्पष्ट है कि यह सरकार पहले से भी उनके प्रति कहीं न कहीं............

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ: महोदय, तो हम यह चाहते हैं कि कब तक, कम से कम पॉच हजार रुपये का प्रस्ताव ये भेजें और उनको अगले महीने से देने का काम करें ।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/सत्येन्द्र-मुकुल/05-03-20

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। वित्तीय कार्य।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	60 मिनट
जनता दल (यू0)	51 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	40 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	01 मिनट
निर्दलीय	04 मिनट

अब माननीय मंत्री शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' शिक्षा विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 351,91,04,56,000/-(तीन सौ इक्यावन अरब इक्यानवे करोड़ चार लाख छप्पन हजार) रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यइ प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामदेव राय, श्री मो0 नेमतुल्लाह एवं श्री कुमार सर्वजीत से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है। अतएव माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय''

मेरी पार्टी की ओर से प्रो0 सुरेन्द्र कुमार जी पक्ष रखेंगे महोदय कटौती प्रस्ताव पर।

श्री सुरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्तुत मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए सदन में समय दिया गया उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही माननीय सामाजिक न्याय के योद्धा एवं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधान सभा में विपक्ष के माननीय नेता एवं राज्य के तमाम लोगों के दिल के भावी नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी हार्दिक बधाई। सदन में राजद पार्टी के मुख्य सचेतक अनुभवी सदन में कई वर्षो से अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे श्री ललित कुमार यादव एवं औराई विधान सभा के महान जनता, मालिकों जिनकी बदौलत मैं इस पवित्र सदन बिहार विधान सभा का सदस्य हूं उनको भी बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज इस पवित्र सदन में शिक्षा विभाग की मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में भाषण के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भूमिका से अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि ज्ञान क्या है और ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है और इस विषय पर बोलने से पहले कुछ तथ्य सदन में रखता हूं कि संसार में पूर्व के जितने भी युग हुये, उन सभी की जीवन संस्कृति अलग-अलग रही, सत्युग हो, द्वापर हो वगैरह-वगैरह। इन युगों में जो निर्गुण ज्ञान है वह निर्गुण ज्ञान अत्यधिक प्रभावकारी रहे हैं सगुण ज्ञान की तुलना में। अध्यक्ष महोदय, द्वापर युग में जब महाभारत की तैयारी चल रही थी उससे पहले वासुदेव कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कुछ उपदेश दिये, उसको आप ज्ञान कहिये प्रदान किये, उसका कुछ अंश मैं सदन में रखना चाहता हूं। वासुदेव कृष्ण जी अर्जुन जी को अपना उपदेश दे रहे थे कि कर्म ऐसा करें जैसे यज्ञ किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, कर्म लोक संग्रह है जो लोकहित में हो उसके बाद अर्जुन जी वासुदेव कृष्ण जी से पूछते हैं कि..

अध्यक्ष: सुरेन्द्र जी अच्छा बोल रहे हैं सब आदमी ध्यानपूर्वक सुनिये।

श्री सुरेन्द्र कुमार: यज्ञ क्या है और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पार्थ, यज्ञ चार प्रकार के होते हैं- द्रव्य यज्ञ, कर्म से अर्जित द्रव्य से जो जनकल्याणार्थ होता है वह भी द्रव्य यज्ञ में आता है। तपो यज्ञ, कर्म की तपस्या में लगाना और उससे जो जनकल्याणार्थ होता है वह तपो यज्ञ कहलाता है। योग यज्ञ, कर्म की बदौलत ध्यान से जो जनकल्याणार्थ होते हैं वह योग यज्ञ में आता है। ज्ञान

यज्ञ, यह यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम है, ज्ञान के आधार पर जो कर्म हो और जिससे जनकल्याणार्थ हो उसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं- न ही ज्ञानेन: संदेश: पवित्र महीविद्‌यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मानी विद्वन्ति, इसका अर्थ है ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं होता । भाषा अपवित्र भी हो जाती है इसका मतलब ज्ञान नहीं होता और असत्य भाषा को अपवित्र करता है। भाषा की पवित्रता ही उसकी सत्यता है जो सही ज्ञान है। अध्यक्ष महोदय, कबीर दास जी हों, तुलसीदास जी हों, संत रविदास जी हों अपने सुनहरे काल में अपना जो मंथन-चिंतन इस संसार को दिये, ज्ञान का जो एक प्रकाश जलाया जिस पर हमारा आर्यसामाजिक जो संस्कृति है वह वर्तमान में विद्यमान है। महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर जी, राम मनोहर लोहिया जी जैसे हमारे महापुरुष भी ज्ञान का प्रकाश अपने कर्म की बदौलत प्रकाशित किये और हमलोग जितने भी हैं आज उस राह पर चल रहे हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए। सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षा का अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शिक्षित बनो, संघर्ष करो उनकी उक्ति है। अध्यक्ष महोदय, हमलोग के प्रथम इस देश के राष्ट्रपति रहे डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी ने गांधी जी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं (क्रमश:)

टर्न-12/मधुप-हेमंत/05.03.2020

...क्रमश:..

श्री सुरेन्द्र कुमार : जिसमें एक किताब है - गांधी जी की देन । उसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी की विचारधारा हिमालय से निकलने वाली निर्मल गंगा की तरह पवित्र है और उन्हीं धाराओं से जो कुछ जल मैं सिंचित कर सका उसके बल पर मुझे भी जनता-जनार्दन की सेवा करने का थोड़ा-बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी की भावना महात्मा गांधीजी के प्रति लिखित है ।

अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान में जो बिहार की शिक्षा नीति है और पूर्व में जो शिक्षा पद्धति रही है, अगर दोनों की तुलना की जाय तो आकाश-पाताल का अन्तर है । पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, हम लोग भी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कालेजेज से अध्ययन कर करके यहां तक आये हैं और इसमें जितने भी हमारे जो माननीय सदस्य अभिभावक तुल्य हैं पक्ष के, विपक्ष के शायद ग्रामीण परिवेश में जो प्राइमरी स्कूल की पद्धति थी आज से 20-25 वर्ष पहले, चाहे हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हृदय पर हाथ रख कर बोलें कि जो ज्ञान की बात हमारे पूर्वजों ने बताई है क्या आज उसपर खरा

उतर रही है सरकार ? आज महात्मा गांधी जी इस कलियुग के, ज्ञान के वर्द्धक रहे हैं और अहिंसा परमो धर्मः एक ही उनका सूत्र और उस पर सारे देश में वे अपना नाम, अपना कृतित्व स्थापित किये हैं लेकिन न जाने कौन-सा बादल छा गया बिहार राज्य की शिक्षा पद्धति पर कि आज हम जितने भी यहां बैठे हैं अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या ग्रामीण या शहरी परिवेश में जो आपके प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं क्या अपने बच्चों को उसमें पढ़ाना चाहते हैं ? क्या स्थिति बन गयी है ? कहां चली गयी गुणवत्ता ? कहां चली गयी वह शिक्षा की पद्धति जिसमें हम लोगों को अनुशासन के साथ सब्जेक्ट का ज्ञान दिलाया जाता था? आज लगता है जैसे एकदम मरणासन्न की स्थिति में सरकार की जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वे पड़ी हुई हैं । (व्यवधान) 15 साल पर भी आ रहे हैं, आ रहे हैं उस पर, सब बात होगी और इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि आज अपने बच्चे को हम लोग 10वीं पास करा कर के राजस्थान के कोटा में भेजते हैं । इससे कितना बड़ा राजस्व इस राज्य का राजस्थान में जा रहा है ? काश यदि ऐसा प्राजेक्ट बिहार में स्थापित होता तो 15 साल में हम हों या हमारी जो 15 करोड़ आवाम है, अपने छात्र-छात्राओं को, अपने बच्चे-बच्चियों को यहीं रखते, घर के पास रखते, अपने शहर के पास रखते । कौन-सी स्थिति बन गयी है और आज उतनी दूर तक नहीं जाना चाहते । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि आपका जो बजट अरबों में आया है जो आप पढ़े हैं फिर पढ़ियेगा क्या उसका सही रिजल्ट आपके धरातल पर उतर रहा है ? याद रखियेगा कि आज फिर एक बात मैं कहना चाहता हूं गांधी जी की महानता, गांधीजी के सिद्धांत, रचनात्मक कार्यक्रम, खादी का अर्थशास्त्र, गांधीजी के जीवन की गंगा, जो किताब मैंने पढ़ी है गांधी जी की, उसके इतने चेप्टर में, वह जो बुक है, उसमें चेप्टर है, गॉधी जी का मार्ग, शक्ति का स्त्रोत, कार्य के विविध पहलू, गॉधी जी के सिद्धांत का धर्म, गॉधी जी के सिखावन, कल्याणकारी विचारधारा, सत्य और अहिंसा, विचारों पर अमल की आवश्यकता, मृत्यु से शिक्षा, अहिंसा परमो धर्मः, हमारी जिम्मेवारी, गॉधी जी की देन, और उन गॉधी जी की तुलना आप नाथूराम गोडसे से करते हैं ? कहॉ हमारा ज्ञान आ गया देश और राज्य के अन्दर, जो सामाजिकता है, कहॉ पर ज्ञान आकर थम गया है ? यह बहुत चिन्तनीय सवाल है । यह साधारण विषय नहीं है । जितने भी हमलोग हैं, यह जो स्थायी आपका सदन है, हमलोगों का सदन है, यह रहेगा, हो सकता है कि हमलोग इसमें नहीं आयें, इसके बाद जितने भी लोग हैं, जो नेचुरल फेनोमेना है, हो सकता है कि हमलोग इस धरती पर नये हैं, कोई न कोई

यहां आयेंगे लकिन शिक्षा की जो पद्धति बिहार में 15 साल में शर्मसार हुई है, किसी भी सरकार के रीजन में इस तरह की शर्मसार शिक्षा पद्धति नहीं हुई है ।

आज डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी, डॉ0 जगन्नाथ जी इसी सदन के मुख्यमंत्री रहे हैं, एल0एस0 कॉलेज में पढ़ते थे । डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी, हमलोग इतिहास में पढ़े हैं कि एल0एस0 कॉलेज में जाकर वे पढ़ाते थे लेकिन आज उस एल0एस0 कॉलेज को देखा जाय, पटना साइंस कॉलेज को देखा जाय, कहॉ स्थिति थी और कहॉ स्थिति आकर रह गई है । इसलिए बड़ा चिंतनीय सवाल है, इसपर सभी लोग गम्भीर हों । सरकारें आयेंगी, सरकारें जायेंगी लेकिन शिक्षा पद्धति अगर ध्वस्त होगी तो आने वाली पीढ़ी हमलोगों को माफ नहीं करेगी । इस बात को समझना होगा और हमारे विपक्ष के साथी, पिछली बार भी मैं शिक्षा पर बोला था, यह बजट जो बढ़ा है, यह आपकी और मेरी देन नहीं है, यह जो आर्थिक स्थिति आई है, आर्थिक उदारीकरण हुआ है, उसकी देन है । उसका उपयोग होना चाहिए, उसका पोजिटिव एक्शन होना चाहिए । इस चीज को हमलोगों को समझना होगा । साईकिल, पोशाक और खिचड़ी बॉट देने से आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा नहीं होगा, हमारे बच्चे का भविष्य सुनहरा नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वर्तमान की जो सरकार है, शिक्षा पद्धति में सुधार करे । बच्चे, नौनिहाल बच्चे भविष्य हमारे हैं, आप उनको रोड पर खड़ा कर देते हैं ? पिक-अप वैन पर लादकर लाते हैं और उसको रोड पर खड़ा कर देते हैं । दूसरे राज्य के लोग हॅसी और मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसी बिहार की सरकार है कि वहॉ के नौनिहाल बच्चों को पिक-अप वैन पर लादकर मानव श्रृंखला में रोड पर खड़ा कर देती है, धूप में, जाड़े में, बरसात में, इसका क्या औचित्य है ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, पठन-पाठन कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और 51 विभाग हमारे बिहार राज्य के पास है, जिमसें शिक्षा विभाग को सर्वोपरि रखना चाहिए, और बजट देना चाहिए, और योजनाएॅ प्लान करनी चाहिए कि हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हमारे गॉव से लेकर शहरी परिवेश तक आये । याद करियेगा हमलोग, यदि अपने पूर्वजों के, मैं फिर वहॉ पर आना चाहता हूॅ, यदि हम अपने पूर्वजों के कृतित्व और व्यक्तित्व को भुला देंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, अपने जीवन में उनको नहीं लायेंगे तो उस परिवार और उस समाज और उस राज्य और उस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है । केवल पीठ थपथपाने से और सत्ता में आ जाने से राज्य और देश का सुधार नहीं हो सकता है । सही मायने में बिहार की 12 करोड़ जनता की जो वर्तमान पीढ़ी है

या आने वाली पीढ़ी है, उनका कहीं न कहीं भविष्य इस वर्तमान की 15 साल की सरकार ने अंधकार में डाल दिया है ।

महोदय, समय कम है । अब मैं आता हूँ कुछ माँग पर कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की माँगें हैं, मैं पटल पर रखता हूँ कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाय, समान काम का समान वेतन दिया जाय, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाय, सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाय, नियमित शिक्षकों की भाँति समान सेवा-शर्त्त दी जाय, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाय, भविष्य निधि लागू किया जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं एक आम कहावत पर आता हूँ कि अगर किसी दरवाजे पर दो हाथी हैं, एक हाथी को पूरा दाना-पानी दिया जाय और दूसरे हाथी को एक सप्ताह तक भूखा रखा जाय । क्या वह बिना खाये हुये जो हाथी है, वह सनकेगा कि नहीं सनकेगा ? आप इसका निर्णय करिये ।

...क्रमशः...

टर्न-13/आजाद/05.03.2020

..... क्रमशः .....

श्री सुरेन्द्र कुमार : बिहार में 27 हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के विरूद्ध 12 हजार शिक्षकों की बहाली हो सकी, 11हजार से अधिक ग्रेस अंक वाले विद्यार्थियों की नियुक्ति अतिशीघ्र शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाय, क्योंकि जैसी जानकारी प्राप्त हुई है अन्य राज्यों में ग्रेस अंक के आधार पर भी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, अन्त में बिहार का ही मामला है, जमीन एवं भवन के बावजूद निम्न विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया है । सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पथरा को । इस तरह का मामला पूरे बिहार का है, इसलिए इसको संज्ञान में लेकर के प्राथमिकता के आधार पर इसका निदान निकाला जाय । माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के समय में यह सब खुला था और इसको दूसरे जगह मर्ज कर दिया गया है । कल हमारे माननीय सदस्य लोग क्वेश्चन किये थे और बताईए कि नदी पार करके, रेलवे लाईन पार करके, एस0एच0 पार करके हमारे बच्चे-बच्चियां जा रही हैं, एक्सिडेंट होता है, मृत्यु होती है और यह बहुत भयंकर मामला है । अध्यक्ष महोदय, अन्त में हम आपसे आग्रह करते हैं कि औराई विधान सभा क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। मैं रामजीवन उच्च विद्यालय जो औराई प्रखंड में है, उसको आर्थिक सहायता देकर उसको एक विकसित उच्च विद्यालय का प्रारूप दिया जाय और बोलना तो बहुत है लेकिन समय कम है अध्यक्ष महोदय, इसलिए अन्त में मैं इतना ही कहूँगा आपके

माध्यम से कि अपने अन्दर झांक कर हमलोग देखें कि जो शिक्षा की व्यवस्थायें पूर्व में थीं, वह अभी इस तरह कैसे आ गई है । अभी तत्काल में यू0जी0सी0 के द्वारा यूनिवर्सिटी के तरफ से लेक्चरर की बहाली हुई है । रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल, यू0पी0, केरला अन्य राज्यों के जो कैंडीडेचर थे, उनकी सहभागिता इस कम्पटीशन में ज्यादा हुआ है और बिहार का बहुत अल्प हुआ है, इसलिए इसपर बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपने जो मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनायें और अन्त में हर्ष और उल्लास का जो पर्व है होली, मैं अध्यक्ष महोदय के साथ तमाम हमारे जो पक्ष और विपक्ष के सदस्य हैं, मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनायें देता हूँ ।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं और शिक्षामंत्री जी को भी, जो शेर-ए-शायरी के लिए विख्यात हैं, इनको भी बधाई देता हूं कि बिहार को, बिहार का सुशासन एवं न्याय के साथ विकास हो रहा है और बिहार तेजी से बदल रहा है। मैं शिक्षा के सवाल पर मुखातिब होना चाहता हूं बिना कोई लाग-लपेट के । महोदय, बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2004-2005 में मात्र 23885 करोड़ था, वर्ष 2020-2021 में बढ़कर 211761 करोड़ हो गया । वर्ष 2020-21 में शिक्षा का बजट सभी विभाग से ज्यादा 33191.05 करोड़ हो गया । महोदय, राज्य में कितने स्कूल खुले हैं, कितने कॉलेज खुले हैं, कितना विकास शिक्षा में हुआ है । मैं सदन को यह बताना चाहता हूं । महोदय, राज्य में 21264 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए । 19625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है ।

(इस अवसर पर मा0 सभापति,श्री रामचन्द्र सहनी, ने आसन ग्रहण किया)

15056 नए प्राथमिक विद्यालय भवन एवं 276518 अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाया गया है । महोदय, सभी विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल की सुविधाएं प्रदान की गई हैं । साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है । सभापति महोदय, सरकार के अथक प्रयास से स्कूल से बाहर रहने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 12.5 से घटकर मात्र 1 प्रतिशत रह गई है । बालक एवं बालिका साईकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं छात्र-छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पूरे बिहार में उन्नयन बिहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में उच्च

माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । जिसके तहत 5726 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो गया है । महोदय, शेष पंचायतों में ये वर्ग 9 कक्षा की अप्रैल 2020 से शुरू की जाएगी । महोदय, राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय गठन किया गया है । प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कालेज, पॉलिटेकनिक संस्थान, महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, जी0एन0एम0 संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान एवं प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं ए0एन0एम0 संस्थान की स्थापना की जा रही है । राज्य में 11 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है तथा सभी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोलने की कार्रवाई की जा रही है । बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है । महोदय, हमने जो खाका प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट हो गया कि पूर्व की सरकार में न स्कूल का भवन था, न शिक्षा की स्थिति अच्छी थी, पढ़ाई क्या होगी, जब स्कूल के भवन नहीं थे, तब पढ़ाई कहां होती थी, सभी जानते हैं । पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण करते थे विद्यार्थी, बातें की जा रही हैं, त्रेता युग एवं द्वापर युग की । मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आप गहराई से अध्ययन कीजिए । उस समय अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल, कॉलेज नहीं थे, देश-दुनिया की चर्चा नहीं होती थी और हम त्रेता युग एवं द्वापर युग की कल्पना कर रहे हैं । यह सत्य है उस जमाने में, दो पंचायतों के झगड़े को बड़ा आकार दिया गया है ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ये विपक्ष के साथी जो हैं, ये साथी हमारे विकास की बात सुनकर भड़क जाते हैं और चारा घोटाले की बात सुनकर भड़क जाते हैं । जिस तरह से सांढ़ को लाल कपड़ा दिखा दिया जाता है तो भड़क जाता है तो उसी प्रकार से हमारे मित्र लोग विकास की बात सुनकर भड़क जाते हैं। इनके राज में चारा घोटाला हुआ, मैं भी उसी दल का आदमी था, मैं भी लालटेन लेकर चलता था, मैं जानता था पूर्ण रूप से कि वहां क्या होता था और हमारे राज में घोटाला नहीं हुआ है,

..... क्रमशः .....

टर्न-14/शंभु-धिरेन्द्र/05.03.2020

श्री सत्यदेव सिंह : हम परिवारवादी नहीं हैं । श्री नीतीश कुमार जी परिवारवादी व्यक्ति नहीं है जो परिवारवादी होता है वो देशभक्त नहीं होता ।

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : टोका-टोकी नहीं करें ।

श्री सत्यदेव सिंह : इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूँ परिवारवादी व्यक्ति सत्ता नहीं चलायेगा, जहाँ भ्रष्टाचार था, वो शिक्षा की बात थी नहीं । कभी शिक्षा की बात होती नहीं थी, सिर्फ भ्रष्टाचार होता था । परिवारवाद के चलते देश विनाश की ओर जा रहा है और जब विकास नहीं होगा । हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का नाम देश-दुनिया में चल रहा

है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाया ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : शांति बनाए रखें ।

श्री सत्यदेव सिंह : जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाकर आज बिहार देश में प्रथम हो गया। जल की चुनौतियों का सामना करने के लिए 24 हजार 500 करोड़ रुपया जल-जीवन-हरियाली के लिए दिया गया ।

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : शांति बनाए रखें, उनको बोलने दें ।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, 19 जनवरी, 2020 को 18034 कि0मी0 लंबी मानव श्रृंखला बनी, ये विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से भी अधिक लोग शरीक हुए, यह दुनिया में रिकार्ड है । श्री नीतीश कुमार की ऊँचाई दुनिया में बहुत बड़ी हो गयी है । महोदय, हम लोग चिंता करते हैं कि श्री नीतीश कुमार के बाद कौन आयेगा बिहार में एक व्यक्ति नहीं है और आने वाला जो विधान सभा का चुनाव होगा वह जो लोकसभा में हुआ है वही विधान सभा में रिजल्ट आने वाला है । आप तय कर लीजिए कि उस समय आप कहाँ रहेंगे, कैसे आयेंगे आप ? श्री नीतीश कुमार जी ने देश की धरती बचाने के लिए दुनिया को एक संदेश दिया । श्री नीतीश कुमार देश के पहले व्यक्ति हैं जिसने दुनिया को बताया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है । पृथ्वी के अंदर का पानी स्तर बहुत नीचे जा रहा है और जब संकट आयेगा, वृक्ष नहीं रहेंगे, हरियाली नहीं रहेगी तो जीवन नहीं बचेगा । जल नहीं रहेगा तो जीव नहीं बचेगा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जल-जीवन-हरियाली चला कर के दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है । श्री नीतीश कुमार जी पर बिहार को नाज है । पहले क्या था बिहार बदनाम था शांति नहीं थी, पूरे विश्व में बिहार बदनाम हो गया था । जब से नीतीश कुमार जी सत्ता में आये है बिहार का नुमाईश हो रहा है पूरे दुनिया में हो रहा है । बिहार के बाहर अगर जाते हैं तो बिहार का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा । लालू जी का राजपाट सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर रहा है । कोई विकास नहीं हुआ है लालू जी के राज में । इसलिए आप सभी साथी से हम आग्रह करते हैं कि विकास को अपनाईये, विनाश की ओर मत जाईये । श्री नीतीश कुमार का रास्ता विकास

का रास्ता है और आपका रास्ता विनाश का रास्ता है । इसलिए विकास के साथ आईये ।

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : अब समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति जी ।

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : श्रीमती अरूणा देवी । अब उनको बोलने दीजिए ।

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, मैं विपक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के बजट के लिए लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

महोदय, राज्य सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिसके अन्तर्गत सरकार सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 एवं 10 के सभी विषयों के लिए स्मार्ट क्लास की स्थपना का निर्णय लिया है । वर्तमान में अबतक 5565 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हो गई है । महोदय राज्य सरकार द्वारा 21420 लक्ष्य के विरूद्ध 21264 नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना तथा 19725 लक्ष्य के विरूद्ध 19625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ग 1 से 8 तक में नामांकित बच्चे को 75 प्रतिशत की उपस्थिति पूर्ण करने पर पोशाक उपलब्ध करा रही है । शैक्षिक सत्र 2019-20 में 1.08 करोड़ बच्चों को डी0बी0टी0 के माध्यम से पोशाक की राशि दी जा रही है । महोदय, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत वर्ग 1 से 8 तक के 1.09 करोड़ छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन पोशाक भोजन उपलब्ध करा रही है जिसके तहत सप्ताह में दो दिन मौसमी फल एवं एक दिन उबला हुआ एक अंडा तथा मौसमी फल दिया जा रहा है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग के 60628 छात्राओं के लिए प्रति छात्र 10 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है । महोदय, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2019-20 में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण सभी कोटि के अविवाहित 3,62,403 छात्राओं के विरूद्ध 2,96,232 छात्राओं को प्रति छात्रा 10 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है । महोदय, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में राज्य के अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 25 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है । महोदय, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कृत

संकल्पित है । सरकार द्वारा शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं के 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के फलस्वरूप महिला शिक्षकों की संख्या 19 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गई है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 40944 लाभुकों को ई-सुविधा के माध्यम से अबतक कुल 20.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। महोदय, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में अबतक कुल 1.42 लाख लाभुकों को 33 करोड़ रुपये का भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया है । महोदय, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को भी सुविधा प्रदान कर रही है । अबतक वर्ष 2019-20 में अन्तर्जातीय विवाह करने वाली 222 महिलाओं को एक लाख रुपये प्रति लाभार्थी की दर से 222 लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध करा चुकी है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा परवरिश योजना के तहत परिवार तथा अभिभावक विहीन 0 से 18 वर्ष के बच्चों को उनके उत्तक परिवार में पालन पोषण के लिए एक हजार रुपये प्रति माह की दर से पालन पोषण अनुदान भत्ता प्रदान कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12527 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है । महोदय, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत संचालित राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के कुल 32.17 लाख बच्चों को 400 रुपये वार्षिक लागत की दर से पोशाक की राशि उपलब्ध कराई गयी है । महोदय, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर तेज गति से कार्य कर रही है । सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा की पॉच विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राज्य के वृद्धजनों, विधवाओं, नि:शक्त जनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों के लिए 400 रुपये प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान कर रही है । दिसम्बर, 2019 तक 77.28 लाख पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से सरकार द्वारा भुगतान किया गया है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार से किसी प्रकार का वेतन, पेंशन, पारिवारिक या सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं प्राप्त करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी आय के वृद्धजनों को 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 400 रुपये प्रतिमाह, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रुपये प्रतिमाह का पेंशन दिया जा रहा है । अबतक सरकार द्वारा 17.99 लाख प्राप्त स्वीकृत 14.21 लाख आवेदकों को लगभग 383 दशमलव 7 करोड़ रुपये भुगतान किया गया है । महोदय, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान

योजना अंतर्गत दिव्यांग पुरूष या महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है । अबतक कुल 68 लाभुकों को वर्ष 2019-20 में उस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है । महोदय, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार द्वारा वृद्धजनों के पुर्नवास के लिए ओल्ड एज होम (सहारा) का क्रियान्वयन पटना, रोहतास, पुर्णिया एवं भगलपुर में किया जा रहा है । महोदय, सरकार द्वारा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में राज्य के ग्रेड 2 डिफॉरमिटिज के 9685 कुष्ठ रोगियों को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रति कुष्ठरोगी की दर से 18 करोड़ रुपये सहायता राशि का भुगतान किया गया है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अंतर्गत कुल 5162, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत 354 एवं कबीर अंत्येष्ठि योजना अंतर्गत 48694 लाभुकों को मृत्यु अथवा दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान हेतु 20 हजार रुपये एवं शवों की अंत्येष्टि हेतु 3 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से भुगतान किया गया है । महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-15/05-03-2020/ज्योति-पुलकित

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी): अब आप समाप्त करें, उसको दे दीजिये । सभा पटल पर रख दीजिये । श्री रामदेव राय प्रारम्भ करें ।

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं कटौती के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, बजट का जो सर्वाधिक अंश है, सर्वाधिक खर्चा है शिक्षा विभाग उसी की कटौती के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूँ । महोदय...

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय : दूसरे का समय मत बर्बाद कीजिये । जितना टोकियेगा उतना बोलेंगी और उतना समय बर्बाद होगा । जरा दूसरे के समय पर भी ध्यान दीजिये ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : अब बैठ जाईये ।

श्री रामदेव राय : मैं बहुत उत्साहित होकर माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का स्वागत करता हूँ और इसलिए स्वागत करता हूँ कि दोनों मंत्री सादगी के बड़े प्रतीक हैं । देहात में कहावत है कि -''देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर '' मगर ये घाव कभी छूटने वाला घाव होता ही नहीं है,

इनका इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन के सामने कि सबसे पहले बिहार में जरुरी है कि शिक्षा को शिक्षित बनाया जाय । जबतक शिक्षा को शिक्षित नहीं बनायेंगे तब तक बिहार का उजाला अंधकार में ही रहेगा । शिक्षा को शिक्षित बनाने के लिए आपके जैसे कोऑर्डिनेटर की जरुरत है मंत्री जी, आप कोऑर्डिनेट कीजिये ‘‘ Education should be educated" इसका अर्थ क्या हुआ हम नहीं जानते हैं । हम कही से सुन कर लाए है कि मंत्री जी के कान में कहियेगा कि मंत्री जी शिक्षा को शिक्षित कर दीजिये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी और इस राज्य की उपलब्धि मानी जायेगी अगर इस ओर आप ध्यान देते, कारण आप में बहुत उल्लेखनीय कदम उठाने का जिक्र अपने भाषण में किया है, मैं पढ़ तो नहीं पाया हूँ इसलिए आंकड़े के जाल में नहीं जा पाऊंगा, संभव है कि मेरा जो सारा प्रॉब्लम है वही छूट जाय । मंत्री जी आप चल कर देखिये गांव के प्राथमिक विद्यालय की स्थिति को । क्या है वहॉ दुर्दशा? साक्षरता दर आपका 2011 में 61 परसेंट साक्षरता दर है और महिला का उसमें 51 प्रतिशत है । माने पुरुष साक्षरता दर से भी उसका बहुत कम है । 61 प्रतिशत ही साक्षरता दर है इसका मतलब हुआ 40 परसेंट लोग आज भी बिहार में निरक्षर हैं जो खेत और खलिहान में काम करते हैं । चरवाहा स्कूल के नाम पर बड़ा डिंग मारते हैं ये लोग । हर परिवार का बच्चा जो गरीब परिवार में जन्म लेता है वह चरवाहा का काम करता है । बकरी, गाय, बैल ,भैंस चराकर के अपना जीवन-यापन करता है उसके पढ़ने के लिए किसी दार्शनिक व्यक्ति ने इंतजाम किया है उसको आप कहॉ ला दिए हैं ? ला दिए हैं 61 प्वायंट पर । 40 प्रतिशत बच्चा आज भी गांव में है और आप क्या कहते हैं कि स्कूल से बाहर रहने वालों बच्चों की संख्या मात्र 1 प्रतिशत है । चलिए गांव में देख लीजिये कि गांव में बच्चों की क्या संख्या हैं । आज भी बच्चे गाय, बैल, भैंस चराते नजर आयेंगे और गांव में खेलते नजर आयेंगे और भगवा भी नहीं पहनते बच्चे और उनकी संख्या आपने बतायी है एक प्रतिशत बाहर है । यह गलत है मंत्री जी इस पर आप ध्यान दीजिये चूंकि बिल्कुल आप अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र से आते हैं ‘‘जाके पैर में फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई’’ आप तो दूसरे की पीर को जानिये । लैंगिक अंतराल भी अभी आपका बहुत ज्यादा है । 2011 में 19-20 था और 25-26 है । क्यों बढ़ा ? लैंगिक अनुपात भी तो नहीं बढ़ा, मात्र 20-25 है और एक ओर आप कहते हैं कि महिला के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिए हैं नौकरी से लेकर पढ़ाई-लिखाई और नियुक्ति तक में और नौकरी में आपने 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है लेकिन हुजूर मेरे ख्याल से 30 प्रतिशत

से भी ज्यादा नहीं है । भला बताईये आप महिला को क्यों उपेक्षित कर रहे हैं । साईकिल दे दिए, पोशाक दे दिये लेकिन स्कूल में पोशाक नहीं पढ़ेगा, साईकिल नहीं पढ़ेगा, पढ़ना है बच्चे-बच्चियों को जिसके लिए आपके पास ईंट का मकान खड़ा है और ईंट का मकान प्रत्येक दिन अंतिम सांस ले रहा है, गिरने का और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई नहीं हो रही है । बच्चा पढ़ता-लिखता नहीं है । पहले क्या स्थिति थी ? आप लोग भी पहले पढ़े होंगे और हम लोग भी पढ़े थे । हर महीने में एक बार इंस्पेक्टर साहेब स्कूल में जाते थे और विद्यार्थियों की जॉच करते थे, परीक्षा लेते थे और विद्यार्थी जमकर तैयार होकर आते थे । आज क्या स्थिति है चल कर देखिये स्लेट के बदले प्लेट की पढ़ाई होती है । जिस राज्य में स्लेट के बदले प्लेट आ गया हो उस राज्य का भविष्य किसके हाथ से लिखा जायेगा इसकी जरुरत है अब आगे आने वाला चुनाव यह साबित करेगा कि इसका भविष्य कौन लिखेगा । आप लिखेंगे या इधर के लोग लिखेंगे ? इसलिए आपसे निवेदन है । आपको बताते हैं प्राथमिक विद्यालय की हालत । हमारे यहॉ कादराबाद एक स्कूल है बछवाड़ा प्रखंड में, वहॉ बच्चे स्कूल जा रहे थे ।

क्रमशः

टर्न-16/कृष्ण/05.03.2020

श्री रामदेव राय (क्रमशः) - एक बच्चा को एक शिक्षिका के हसबैंड ने धक्का मार कर गिरा दिया और वह बच्चा मर भी गया । महोदय, कोई शिक्षक उसे देखने के लिये भी नहीं आया, आप उसका प्रमाण ले लीजिये । एक भी शिक्षक देखने के लिये नहीं आया कि वह बच्चा मर गया या जिंदा है । सात घंटे के बाद उस बच्चे को अस्पताल भेजा गया और उल्टे प्रधानाध्यापक के द्वारा ग्रामीणों पर केस कर दिया गया । ग्रामीण शिक्षक वहां 14-15 वर्षों से कार्यरत हैं और विद्यालय में एक दिन भी पढाई-लिखाई नहीं होती है । विधायक जी भी शून्य, इन्सपेक्टर साहब भी शून्य, डी0ई0ओ0 साहब भी शून्य और मंत्री जी भी शून्य । अगर विधायक की बात नहीं चलती है, फेल्योर होता है मंत्री जी का । आप भी मंत्री है और मैं भी मंत्री रहा हूं । मंत्री की सार्वजनिक जवाबदेही होती है । पद छोटा हो या बड़ा जवाबदेही महान होती है और जो अपनी जवाबदेही का निर्वहन ईमानदारी से करता है, वही बिहार का सच्चा सपूत है । इसलिये मुझे आप पर यकीन है कि आप अपनी जवाबदेही का निर्वहन करेंगे और मैंने जो दृष्टांत दिया हूं, वह कागज लेकर कार्रवाही करने की कृपा करें अन्यथा इसका गलत मैसेज जायेगा ।

महोदय, ठीक उसी प्रकार मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में बोलना चाहता हूं । आज सारे शिक्षक बाहर हैं, रोड पर है और आप एक ओर प्राथमिक शिक्षक को समान काम समान वेतन के लिये केवल अखबार में न्यूज निकालते हैं लेकिन देते कुछ नहीं हैं । वर्षों से उनकी मांग लंबित पड़ी हुई है । विद्यालय बंद हैं, छात्र कहां जायेंगे, बता दीजिये । आप विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिये हैं, हमारे यहां बछवाड़ा प्रखंड में समसीपुर स्कूल में अभी दो बीघे जमीन है, भवन है, विधायक भी अपने फंड से भवन बनवा रहे हैं और विद्यालय को तीन किलोमीटर भेज दिया गया है, जहां हमारे क्षेत्र का मौजा का स्कूल नहीं है वहां, बोलिये मंत्री जी, मैं आप की ही बात कर रह हूं । आप सोचिये, विचारिये और काम कीजिये । सिर्फ सुनिये नहीं, सिर्फ औपचारिकता है । आप करके दिखाईये । सारे विद्याालयों को उनकी जगहों पर भेज दीजिये । हम तो उतना सामाजिक आदमी नहीं है, मगर गांव के लोग स्कूल का भवन बनाने के लिये तैयार है, विधायक भी भवन बनाने के लिये तैयार है और बनाये भी हैं और उस विद्यालय को आप बाहर मत रखिये । आज अपने भाषण में इसको आप जरूर स्पष्ट कर दीजिये । आजादी के समय से वह विद्यालय है और दो बीघे से ज्यादा जमीन उसके फिल्ड में है । घर बना हुआ है, कुछ घर टूटा हुआ है, उसके बदले विधायक बना रहा है । आप इस समानता को नहीं देखेंगे तो काम नहीं चल सकता है । प्राथमिक विद्यालय की हालत खराब, मध्य विद्यालय की हालत खराब है । आप टी0वी0 से पढ़ाई शुरू किये हैं, स्मार्ट क्लास शुरू किये हैं । क्या कारण है ? आपके पास शिक्षक नहीं हैं? ठीक है, आप टी0वी0 से पढ़ाई शुरू किये हैं । लेकिन देख लीजिये, उसकी हालत क्या है ? वह तो मनोरंजन में बदल गया है । रात को टी0वी0 चोरी हो जाती है, देखनेवाला कोई नहीं है । बहुत खुशी की बात है कि आप प्रबंध समिति बनाने का निर्णय लिये हैं । लेकिन उसको जल्द बनवाईये और माध्यमिक शिक्षा को कंट्रोल कीजिये नहीं तो आपका बिहार पिछड़ा रह जायेगा । एक और बात बताता हूं सम्बद्ध कॉलेज के बारे में । संबद्ध कॉलेज को आप अनुदान देते हैं । जितना आप अनुदान देते हैं, उतना आप वेतन मद में दीजिये । कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं होती है ? कॉलेज के फिल्ड में बकरी चरती है और आप उनको अनुदान देते हैं । हमारा पैसा जाता है लेकिन उससे हमारे बाल-बच्चे को लाभ नहीं मिल पाता है । समस्तीपुर में संत कबीर कॉलेज है, वह सम्बद्ध कॉलेज है । 19.04.2007 के बाद जो नियुक्त शिक्षक होंगे, उनको किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा । 19. 04.2007 के पहले जो थे, उनको आप अनुदान दीजियेगा लेकिन 19.04.2007 के

बाद जो बहाल हुये हैं, विज्ञापन निकाल करके, आवश्यकतानुसार छात्र के अनुपात में बहाली हुई है, उनको आप एक पैसा नहीं देंगे । यह कौन-सा नियम है ?

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): आप समाप्त कीजिये ।

श्री रामदेव राय : किस नियम से गया, इसको देखने की जरूरत है । नहीं तो गरीब शिक्षक जो वहां वर्षों से भूखे मर रहे हैं, वे मर जायेंगे ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिये । श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, एक मिनट । समाज कल्याण पर कहना चाहता हूं । यह सनसनी खेज है । यह पेन ड्राईव देखिये, आप इसको हम से ले लीजिये और जांच करवा लीजिये । इसमें देखियेगा कि क्या हो रहा है, कैसे लूट हो रहा है । आपके जैसे मंत्री को कैसे चिट कर रहा है, इसका यह सबूत हम आपको देते हैं ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : आप रख दीजिये ।

श्री रामदेव राय : आपका आदेश हो तो मैं प्रस्तुत करूं । यह पेन ड्राईव है । इससे आप सुन सकते हैं कि क्या हालत है । हुजूर, आपका आदेश हो तो इस पेन ड्राईव को रख दूं ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : रख दीजिये । माननीय सदस्य श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, आप बोलिये ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : सभापति महोदय, मैं एक आदिवासी महिला हूं । इस सदन के अंदर सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारी राजमाता राबड़ी मैडम, नेता,प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मैं अपने क्षेत्र की तमाम जनता का आभार प्रकट करते हुये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खडी हुई हूं ।

महोदय, सबसे पहले मैं लाखों बार इस सदन को सलाम करती हूं, अगर इस सदन को मैं सलाम नहीं करती तो आज मुझे रोड पर रहने की नौबत आती । आज मैं रोड रहती । आज मुझे शिक्षा के विषय पर बोलने का मौका मिला है । मैं भी पूर्व में एक शिक्षिका थी और आज उन शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, आप सबों के सामने सब चीज खुली किताब की तरह है । महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि -

" आंखें तो सब की एक जैसी होती है,
पर सब का देखने का अंदाज अलग-अलग होता है । "

सही में मैं कहती हूं कि जो देखने का तरीका है, आज की वर्तमान सरकार का वह है धोखेबाज, जुमलेबाज और कितने तरीकों से मैं इनकी चर्चा करूं, ज्यादा बेहतर होगा कि मैं यही कहूं कि आप देख रहे हैं शिक्षकों की क्या स्थिति

है । आज सारे शिक्षक सड़क पर आ गये हैं । आप शिक्षा की कैसी बात करते हैं? अगर शिक्षक ही सड़क पर हैं तो फिर छात्र और छात्रायें भी घर से बाहर निकल कर सड़क पर आयेंगे । आपने तो बहाली कर दी 2006 में शिक्षकों की, आपने जुमले दिखायें और आप ने क्या करने का काम किया ? शिक्षक आज अपने पेट की लडाई लड़ रहे हैं । हरेक मानव को हक है अपने पेट की लड़ाई लड़ने की, एक वक्त की रोटी कमाने का । वे शिक्षक जो आज सड़क पर हैं, उसी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं । मैं सदन में उन शिक्षकों को आपके सामने रखती हूं जिनकी आपने धोखेबाजी के साथ बहाली की और वे आज अपनी मांग पूरी करने के लिये सड़कों पर खड़े हैं । पर आपके सामने एक विकट परिस्थिति आ गयी है। अभी मैट्रिक की परीक्षा की कॉपी की जांच हो रही है, इंटर की परीक्षा की कॉपी की जांच हो रही है और यह भगवान के भरासे है । आपने किनको-किनको इस में लगाया था एक्जाम के टाईम में ? आपने सेविका से लेकर पूरे लोगों को लगा दिया था और अभी जो कॉपी जांच का समय आ गया है, वह भी भगवान भरोसे है । अगर सही रूप से कॉपी की जांच नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा किस स्तर पर जायेगी ।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या के बारे में कहना चाहती हूं । आप एस0सी0एस0टी0 की बात करते हैं । आप उनके उत्थान की बात करते है । हमने इस विषय पर सदन में सवाल भी रखा है कि हमारे कटोरिया प्रखंड के जयपुर क्षेत्र के जयपुर विद्यालय लगभग तीन वर्षों से निर्माण के अभाव में पड़ा हुआ है । अनुसूचित जााति एवं अनुसूचित जनजति छात्रावास को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है ।

क्रमशः

टर्न-17/अंजनी/अभिनीत/दि0 05.03.2020

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : (क्रमशः) : कबतक वह हैंडओवर होगा, यह मैं नहीं कह सकती हूँ । जवाब में हमें मिलता है कि एक महीने के अन्दर, मैं इन्तजार करूंगी कि एक महीना के अन्दर बिजली का काम पूरा हो जाने के बाद प्रधानाध्यापक को हैंडओवर हो जायेगा । एक वैसा ही हमारे क्षेत्र, बौंसी प्रखंड का है एल0एन0बी0 हाई स्कूल, जो लगभग पांच वर्षो से अर्द्धनिर्मित है, कहा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बनाया जा रहा है और वहां के जो संवेदक हैं, उनका कहना है कि राशि नहीं रहने के कारण वह विद्यालय अर्द्धनिर्मित है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि अगर आप उस अर्द्धनिर्मित भवन पूरा नहीं

करते हैं तो क्या उन बच्चों को शिक्षा मिल पायेगी, जो जमीन पर बैठकर आज भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : दो मिनट महोदय । सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा का उद्देश्य एक खुले दिमाग से, एक खाली दिमाग को बदलना है । शिक्षा की जो बात हम करते हैं....

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : महोदय, साथ में, मैं कहूंगी कि "कीमत हर एक चीज की होती है, पर ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है"....

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त करिए । माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ प्रसाद ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : शिक्षा की बात आप करते हैं, आपके कहां हैं कम्प्यूटर टीचर, विद्यालय में कम्प्यूटर टीचर डेढ़ साल से धरना पर बैठे हुए हैं । किनके भरोसे पर आप विद्यालय में कम्प्यूटर छोड़े हुए हैं ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए या गांव या घर के विकास के लिए अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वह है शिक्षा, उसके वगैर हम कहीं पर भी विकास नहीं कर पायेंगे । इस पर एक पंक्ति मैं कहना चाहता हूं महोदय कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान । महोदय, मैं बता दूं कि सबसे पहले गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, खेतीहर मजदूर के बच्चे शिक्षा से वंचित थे, उनको पढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांवों की तरफ रूख किया और जब वर्ष 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्‌दी संभाली तो सबसे पहले शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च किये और उस गांव के प्राथमिक विद्यालयों को जो भवनविहीन थे, उनका भवन बनाया गया और उसे गुलाबी रंगों से रंगा गया । जिस गांव में जाकर देखिएगा कि गुलाबी रंग का कोई भवन दिखायी देता है तो वह प्राथमिक विद्यालय है। महोदय और इतना ही नहीं, जो गरीब-गुरबों के रहनुमा, महादलितों के रहनुमा कहे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दलित के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए टोला सेवकों की बहाली की और वे टोला सेवक पढ़ाकर बच्चों को सीधे विद्यालय ले जाते थे और आज दलित के बच्चे, गरीब के बच्चे, खेतीहर के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो विद्यालय से बाहर थे, वे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं । दूसरी ओर महोदय, प्रोत्साहन के लिए, बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पोशाक देने का एलान किया ताकि अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे एक समान पहनकर आयें

और शिक्षा ग्रहण कर सकें । आज इतना ही नहीं, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बिहार देश का एक ऐसा केन्द्र रहा है, प्राचीन काल से हो या मध्य काल से हो या अभी वर्त्तमान में, प्राचीन काल में भी बिहार शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। इसका प्रमुख केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय, ब्रजाशन विश्वविद्यालय एवं उद्मपुरी विश्वविद्यालय रहे हैं । आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी पुराने विश्वविद्यालयों में से एक आज नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किया और उस पुनर्जीवित विश्वविद्यालय में देश के ही नहीं, विदेश के भी छात्र पढ़ने आते हैं । यह हमारे बिहार के गौरव की बात है, देश के गौरव की बात है । बिहार में शिक्षा मध्यकाल से प्रारम्भ हुई थी और उस काल में शिक्षा का माध्यम फारसी और संस्कृत रहा था । आधुनिक काल का प्रारम्भ हमारे देश में 1835 ई0 में हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरे गरीब के बच्चों, दलित के बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया । इतना ही नहीं महोदय, वर्ष 2020-21 में शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है । 35,191 करोड़ रूपया लगभग शिक्षा के बजट पर प्रावधान किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से जो बालिकायें स्कूल से बाहर रहती थी, उनको पोशाक राशि, साईकिल राशि दिया गया है, जिसके कारण बच्चे 12.5 प्रतिशत जो स्कूल से बाहर रहते थे, वह लगभग एक प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर रह रहे हैं । महोदय, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश का पहला राज्य है केरल, जो साक्षरता के मामले में अव्वल है । अब हमारा बिहार राज्य भी कुछ सालों में देश का अव्वल साक्षर राज्य बनेगा महोदय । माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन चल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन तैयार किया है, उससे बिहार सबसे अगले पायदान पर काबिज होगा महोदय । महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, जो न्यायपालिका में दलित, महादलित को आरक्षण देने का प्रावधान किये । 21,263 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है और इतना ही नहीं, 19,625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया है । इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में पोशाक खरीदने के लिए छात्र-छात्राओं को वर्ग-1 से लेकर वर्ग-8 तक उनके अभिभावकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से 528 करोड़ रूपया उनके गार्जियन के खाते में दिया गया है ताकि बच्चे प्रोत्साहित होकर स्कूल मे आये और शिक्षा ग्रहण करें । प्राथमिक शिक्षा में और अमूल्य परिवर्तन करते हुए मध्याह्न

भोजन में 1 करोड़ 9 लाख वर्ग-1 से लेकर वर्ग-8 तक के बच्चों के लिए पोशाक राशि, पोषक भोजन उपलब्ध कराया गया है । वर्त्तमान में सप्ताह में दो दिन मौसमी फल एवं एक दिन उबला हुआ अंडा बच्चों को दिया जाता है । एक कहावत है कि स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ्य मस्तिष्क का विकास होता है महोदय, । इसलिए हमारे बच्चे जब स्वस्थ्य रहेंगे तो उनका मस्तिष्क स्वस्थ्य रहेगा और शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पायेंगे । इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2019-20 में मैट्रिक की परीक्षा में जो फर्स्ट डिवीजन हमारे बच्चे आयेंगे, उनके लिए दस हजार रूपया राशि उपलब्ध कराया गया है और जो इंटर में फर्स्ट डिवीजन आयेंगे, उनके लिए भी दस हजार रूपया का प्रावधान किया गया है । बी0ए0,बी0एस0सी0 और बी0कॉम0 के जो छात्र-छात्रायें आयेंगे, वे अगर फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे तो उनको 25 हजार रूपया का प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा । हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर तरह से हर क्षेत्र में हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें चाहे प्राइमरी शिक्षा की हो या उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की हो ।

...क्रमश:...

टर्न:18/राजेश-राहुल/5.3.20

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, क्रमश: महोदय, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से नेतरहाट विद्यालय है, उसी तर्ज पर सिमुलतल्ला में, जो जमुई जिला में स्थित है, वहॉ पर नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर 75.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, जो नेतरहाट विद्यालय की तरह पढ़ाई वहॉ पर होगा । इतना ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास के पक्षधर रहे हैं । मदरसा बोर्ड के द्वारा जो बच्चे..............

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद: जो बच्चे पास करेंगे, जो फोकानिया से पास करेंगे, जो मदरसा से पास करेंगे, उनको भी पुरस्कार राशि दी जाएगी, महोदय इतना ही नही, मदरसा बोर्ड द्वारा 110 मदरसों का मान्यता दिया गया है और 80 मदरसों को अपग्रेड किया गया है महोदय, इतना ही नहीं महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा महोदय.............

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद: महोदय, एक मिनट सर । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो रहता है, पर असली ज्ञान वहीं है जिसे अपने अभिमान

का ज्ञान होता है महोदय । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

श्री मिथिलेश तिवारी: सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग के द्वारा लाए गए बजट के पक्ष में एवं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज शिक्षा विभाग पर बहस चल रही है और मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बिहार को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया है कि आज हम दुनिया को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को, जो शेरो शायरी के माध्यम से आज जोरदार हमला करने वाले हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि आज हमारी सरकार ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं, जिसकी चर्चा करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है महोदय और महोदय, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा जो बिहार के बारे में उन्होंने लिखी हैं, मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूंगा:-

'मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर ज्ञान,
मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रहम ज्ञान,
मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर,
मानव के मन का अंधकार, क्या कभी सामने सका ठहर,
मेरा स्वर नभ में गहर-गहर, सागर के जल में छहर-छहर,
इस कोने से उस कोने तक, कर सकता जगती सौरभ में,
मैं अखिल विश्व का गुरु महान ।'

महोदय, जब माननीय अटल जी की मैं कविता पढ़ता हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि इस बिहार का गौरव चाणक्य, चन्द्रगुप्त मौर्य के महामंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना कर विश्व पटल पर आज एक प्रतिष्ठित अपने आप को स्थापित किया, जिनको याद करके हम बिहारवासी गौरव का अनुभव करते हैं बहुत, महोदय और जिन्होंने राजनीति, अर्थनीति, कृषिनीति और समाज नीति पर एक विशेष अधययन एवं विचार आधुनिक युग को दिया, वह हमको हमेशा एक नई दिशा देता है महोदय । महोदय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आठवीं एवं नौवीं शताब्दी में बिहार की धरती पर पूरे विश्व को ज्ञान बांटने वाला अद्वितीय संस्थान था महोदय, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी....

(व्यवधान)

चिंता मत करिये, मैं क्यों कह रहा हूं उसको सुनिए, पूरा सुनिए, उसके बाद बोलिएगा । महोदय, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर में सातवीं शताब्दी में मौर्य वंश के समय करीब 10 हजार विद्यार्थी और दो सौ अध्यापक हुआ करते थे, जिसका वर्णन हवेन्सांग की डायरी में मिलता है । इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के समय हुई थी महोदय, आर्यभट्ट सन् 476 में जन्म लिए, इस महान खगोलशास्त्री, महान गणीतज्ञ पर हमें गर्व हैं, इन्होंने सर्वप्रथम चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण की प्रक्रिया से हमें अवगत कराया । महोदय, आज शिक्षा पर बहस चल रही है और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, दोनों लोग गायब हैं,............

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी हैं, मंत्री जी अभी फिर आ रहे हैं, आएंगे और आते ही मंत्री जी आपलोगों पर छा जाएंगे, आप चिन्ता मत करिए, तो मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को आपने बुलाया था कि नहीं, तो माननीय मंत्री जी ने एक शेर के माध्यम से ये कहा कि:-

'खत को देकर हमने बुलाया, पर ये कातिब ने आकर सुनाया,
उनके पांव में मेंहदी लगी है, वे आने-जाने के काबिल नहीं हैं।'

महोदय, आज शिक्षा पर बहस चल रही है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस बिहार को इन लोगों ने रसातल में पहुंचा दिया, उस बिहार पर भाषण दे रहे हैं, जिस बिहार में डर के मारे बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उसे साइकिल दे करके उनको विद्यालय के लिए भेजा, आज जब बच्चियां साइकिल पर बैठकर घंटी बजाते हुए विद्यालय चलती हैं, तो क्या नजारा होता है, यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनियां इसे देखती है महोदय और ये लोग उसके बावजूद भी भाषण देते हैं महोदय, मैं कहना चाहूंगा जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, जब ये चुनाव में जाएंगे, तो इनको खुद ही लोग बताएंगे लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम भी दर्शन कराना चाहेंगे । महोदय, इन लोगों ने 15 साल का हमारे कई मित्रों ने जिक्र किया, अब तो 15 साल की चर्चा होने ही वाली है और यह होगी ही, क्योंकि 2020 में तो बिहार की जनता 15 साल एक तरफ रखेगी और 15 साल दूसरी तरफ रखेगी, और वे बैठ करके तौलेगी कि किसका 15 साल अच्छा था और किसका 15 साल बुरा था और आप चिन्ता मत करिये, बिहार की जनता बहुत ही होशियार है, ऐसा निर्णय लेगी कि ढूंढ़ते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा । इसीलिए सभापति महोदय, जिस बिहार में इनको मौका मिला महोदय, ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग थे, इनको मौका मिला, तो इन लोगों ने बिहार में चरवाहा विद्यालय खोल दिया और हम लोगों को मौका मिला, तो चाणक्य

विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हमने खोला, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हमने खोला, केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी हमने खोला, सभी जिलों में एक-एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोला, सभी अनुमंडलों में एक-एक पोलिटेक्निक कॉलेज हमने खोला और अब तो आई0आई0एम0 भी बन रहा है, बहुत जल्द आई0आई0एम0 की पढ़ाई भी बिहार में होगी । सभापति महोदय, आपके माध्यम से इनको बताना चाहेंगे और तो और भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च इन्सटिच्यूट हाजीपुर में, ऐसे-ऐसे नाइपर का इन्सटिट्यूट ऐसे-ऐसे संस्थान हमने बिहार में खोल करके बिहार को देश के अन्य राज्यों की तुलना में खड़ा कर दिया महोदय और उसके बाद भी ये 15 साल, 15 साल, 15 साल, अरे भाई 15 साल आपका बुरा हाल था, 15 साल आपका खस्ताहाल था और 15 साल एन0डी0ए0 का जो है, वह अलग से आपके लिए एक भूचाल है, जो हम लोगों ने काम करके दिखाया है, वह हमारी दुनिया में इसकी कल्पना हो रही है, महोदय बिहार के लोग पहले जाते थे, तो होटल में रूम नहीं मिलता था, बिहार के जो डॉक्टर थे, वे जब पटना यूनिवर्सिटी से, पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़कर जाते थे, तो अपने लेटर पैड पर वे लोग पटना पूरा लिखते नहीं थे, आधा पर लिखते थे, ताकि लोग समझेंगे कि ये पटियाला के डॉक्टर साहब हैं, ये हाल था इन लोगों के समय में । महोदय, हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने बिहार की स्थिति को बदलकर दिखाया है और बिहार को हम विश्व का नम्बर वन राज्य बनाने कि दिशा में आगे बढ़ रहे हैं महोदय, उस दिशा में हम काम करने जा रहे हैं, अब 7-8 मिनट टाइम मिला है महोदय, हम क्या कहें लेकिन कुछ बात कहनी जरूरी है और ये भी कहना है महोदय कि आज जो हमारा शिक्षा विभाग का बजट है, इस शिक्षा विभाग के बजट के बराबर उनकी सरकार का पूरा बजट हुआ करता था महोदय, वह काम हमने करके दिखाया है महोदय और महोदय इनके समय में स्कूल में गाय, भैंस चरा करते थे, इनके मुख्यमंत्री जी भैंस के आगे से चढ़ते थे और वहीं दुनिया में दिखाते थे और हम लोग स्कूल के क्लास में स्मार्ट क्लास खोल करके बच्चों को नई-नई तकनीक से अवगत करा रहे हैं और नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उनको हम पढ़ा रहे हैं....

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): ठीक है, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, हमको दो मिनट का समय दीजिए, हमको कुछ विषय के बारे में कहना है । महोदय हम कहना चाहेंगे, यहां माननीय मंत्री जी भी हैं, पूरा विभाग

यहां सुन रहा है, महोदय भारत सरकार के एन0आई0ओ0एस0 के द्वारा जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, हाईकोर्ट ने भी उनको क्लियर किया है महोदय, जो नया शिक्षक की बहाली हो रही है, उसमें डी0एल0ई0डी0 जो एन0आई0ओ0एस0 से ट्रेंड है, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए और महोदय जो नियोजित शिक्षक आज हड़ताल पर हैं, उनके खिलाफ आज बड़ा ऑसू यहां विपक्ष के लोग बहा रहे हैं लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि सरकार ने उनको कहां से कहां पहुंचाया है और आप चिन्ता मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है, उनके आंसूओं को भी पोंछने का काम भी हम ही लोग करेंगे, आपको जब भी मौका मिलेगा तो आप उनको खून की आंसू रूलाईयेगा, इसलिए महोदय आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है, जो स्वयं जल करके दूसरों को रोशनी प्रदान करता है, तो शिक्षकों की बात होनी चाहिए, उनके अगर वेतन वृद्धि की बात है, तो हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र उस पर भी बातचीत होनी चाहिए।

क्रमशः

टर्न-19/सत्येन्द्र-मुकुल/05-03-20

क्रमशः

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, आजकल हमारे विपक्ष के बहुत सारे साथी जिसकी यहां बात करते हैं, हमारी सरकार ने काफी आगे बढ़ाया है लेकिन मदरसों को आगे बढ़ाते-बढ़ाते हम संस्कृत की चिन्ता करना भूल गये हैं। महोदय, हम आग्रह करना चाहेंगे अपनी सरकार से कि बिहार में जो 69 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय अनुदान से वंचित हैं उनको भी तुरंत अनुदान दिया जाय और साथ ही बिहार में गुरूकुल की तर्ज पर एक वेद और शास्त्र की पढ़ाई करने वाले संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की जाय । महोदय, बैकुंठपुर विधान-सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक डिग्री कॉलेज खोला जाय, सिधवलिया के शाहपुर उच्च विद्यालय के निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूरा कराया जाय, सिरसा मानपुर हाई स्कूल के भवन को मॉडल विद्यालय में तब्दील किया जाय और महात्मा गांधी जब गंधुआ आये थे महोदय उनके नाम पर एक स्कूल है हमारे यहां बैकुंठपुर में, बंधुआ उच्च विद्यालय, कोथ उसको भी उत्क्रमित किया जाय तथा कसौर उच्च विद्यालय को उत्क्रमित किया जाय। महोदय, अंत में यही कहेंगे कि तू इधर-उधर की बात न कर । ये हमारे विपक्ष के साथियों के लिए है, तू इधर-उधर की बात न कर, ये बतां कारवां कैसे लूटा। हम ये पूछना

चाहेंगे आज ये जो लगातार हमारे सरकार पर आक्रमण करते हैं, महोदय, ये बिहार किसके कारण इतना पीछे गया था। अगर इनलोगों ने काम किया रहता तो आज बिहार देश का सबसे उन्नत राज्य रहता लेकिन इनलोगों ने रसातल में बिहार को पहुंचा दिया था लेकिन हमारी सरकार ने मेहनत करके बिहार को इतना आगे लाने का काम किया है और आज हमारे एक-एक बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं महोदय और वर्ष 2020 में बिहार की जनता हमको प्रचंड बहुमत से फिर लाने वाली है और जब वर्ष 2020 में हम जीतकर के आयेंगे, हमारी सरकार फिर से बनेगी तो हमारे मुख्यमंत्री का नारा होगा बिहार का, बिहार से हम पूरी दुनिया को हम शिक्षित करने का काम करेंगे और आपको कहना चाहते हैं, विपक्ष के साथियों को हम कहना चाहते हैं अब तो मोदी जी का एल0ई0डी का युग हो गया है और मोदी जी के एल0ई0डी0 युग से और नीतीश कुमार जी की बिजली से बिहार रौशन है आप अपने लालटेन को कहीं और रख दीजिये, अब इसकी जरूरत बिहार को नहीं है। महोदय यही कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करेंगे और साथ में शिक्षा मंत्री जी को हम बहुत-बहुत बधाई देंगे और ये भी कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मैं जानता हूॅ कि बिहार सरकार और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का गौरव बढ़ेगा । विपक्ष के साथियों के लिए अंतिम में एक संस्कृत का भी श्लोक पढ़कर खत्म करेंगे-

अन्नानि भूमौ,पश्वश्च गोष्ठे,
भार्या: गृहद्वारे,जन: श्मशाने,
देहश्चितायां, कर्मानुगो गच्छति जीव एक:

इसलिए अच्छा कर्म करिये नहीं तो यहां पर तो किसी तरह काम चल जायेगा वहां काम चलने वाला नहीं है। आपको एक बार पुन: धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बजट लाये हैं उसके प्रति हम अपना पूरा समर्थन देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूॅ। महोदय, जिस तरह से और खासकर जो बजट में बढ़ोतरी हुई है, 35191.05 करोड़ रू0 दिये गये हैं बजट में इस विभाग को यह एक अच्छी बात है शिक्षा जो हमारे राज्य ही नहीं देश का और हमारे बच्चों का भविष्य होता है और आज उनके भविष्य बनाने वाले शिक्षक सड़क पर खड़े हैं और जो हाल है आज बिहार में शिक्षा की, हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर लें लेकिन शिक्षा का जो स्तर है बिहार में वह बहुत नीचे चली गई है। मुख्य रूप से शिक्षा की जो

स्थिति है आज विद्यालय अपग्रेड हुई और हाई-स्कूल बनी और प्रत्येक पंचायत में हाई-स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है और विद्यालय बनाये भी गये हैं, कई भवनें भी बनायी गयी हैं लेकिन आज उन भवनों में कहीं-कहीं ऐसे भी भवन हैं कि एक भी शिक्षक नहीं है। साथ-साथ जो हमारे शिक्षकों की आज स्थिति है जो लगातार आज शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं और आज सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद है। आज मात्र किसी-किसी विद्यालय में एक शिक्षक बैठकर विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में हम बच्चों के भविष्य और शिक्षा को कितना आगे बढ़ा पायेंगे, यह सोचने की जरूरत है। जिस तरह से कहा गया है कि शिक्षा के बिना जीवन अंधकार है ठीक उसी प्रकार शिक्षकों के बिना विद्यालय बेकार हैं और साथ-साथ जो अभी खासकर बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें से 248 विद्यालय को सिफ्ट किया गया, सिफ्ट करने का मुख्य जो अभी कारण कई बार हम शिक्षा मंत्री जी से भी सुने हैं कि उन विद्यालयों का अपना भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय को सिफ्ट किया गया लेकिन यह सोचने की जरूरत है और सरकार को समझने की जरूरत है कि जो बच्चे छोटे-छोटे बच्चे जो हमारे बसगढ़ा पंचायत कोढ़ा में महादलित परिवार के बगल में वह विद्यालय था उसको एकम्मा एन.एच. से पार करके बच्चे को जाना पड़ रहा है जिसके कारण वे सारे बच्चे आज विद्यालय से वंचित हैं। विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, साथ-साथ कई ऐसे विद्यालय हैं जो कि विद्यालय 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर रहने के कारण आज बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं और कटिहार सहित 7 हजार विद्यालय सिफ्ट कर दिये गये हैं जो यह शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन है । हमारे यहां कटिहार जिला अन्तर्गत 108 उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 122 शिक्षक मात्र हैं और हम शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं। शिक्षा की बात करते हैं लेकिन जो 108 उत्क्रमित मध्य/उच्च विद्यालय स्थापित हैं वहां सिर्फ 122 टीचर्ज हैं और ये हर सब्जेक्ट का शिक्षक भी नहीं है, साथ-साथ मध्याह्न भोजन योजना जो है सुप्रीम कोर्ट एवं केन्द्र सरकार ने कुपोषण दूर करने की रोज-रोज बातें करती रहती हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति एवं महाविद्यालय के शिक्षक आमने-सामने भीड़े हुए हैं जिसके कारण शिक्षा वहां काफी बाधित हो रही है और बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। महोदय, हमारे यहां फलका प्रखंड में एक छात्रावास बना, जहां अभी मवेशियों का तबेला है। पता नहीं छात्र-छात्राओं का कब सपना पूरा होगा, पोठिया बाजार स्थित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए विभागीय जो छात्रावास बन रहा था वह आज भी लंबित पड़ी हुई है। भवन निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से इस छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू किया, पांच

वर्ष बीत जाने के बाद संवेदक की लापरवाही के कारण आज भी वह हैंड-ओवर नहीं किया गया है। गेस्ट टीचर जो पूर्व से कार्यरत हैं उनको पहले नियोजित किया जाय, समायोजित किया जाय साथ ही साथ जो नये टीचर की बहाली होनी है इनके बाद ही उनको बहाल किया जाय और महोदय जो हमारे महिला गेस्ट टीचर/शिक्षक हैं उनको कम से कम महीने में चार दिन छुट्टी देने का प्रावधान किया जाय और साथ-साथ जो हमारे शिक्षक सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं वे पुराने शिक्षक के समान वेतनमान अधिकार की बात कर रहे हैं, उन्हें समान वेतन दिया जाय और राज्य में जो हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को वापस लिया जाय।(क्रमशः)

टर्न-20/मधुप-हेमंत/05.03.2020

..क्रमशः...

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : साथ-ही, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने आज से चार साल पूर्व ही सवाल किया कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो नकीपुर विद्यालय है संदलपुर पंचायत में, वहॉ पर शिक्षक का अभाव है जिसके कारण हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया । उसके बाद पिछले वर्ष भी हमने कहा कि हमारे शिवलाल टोला के विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, लेकिन आज मुझे यह समझ में बात नहीं आ रही कि सरकार बहुत बड़े-बड़े वायदे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करती है कि हमने शिक्षा में सुधार कर दिया, बहुत अच्छी बात है कि कन्या विवाह योजना सरकार लायी, कन्या विवाह योजना में कई लोगों को पैसे मिले हैं लेकिन हमारे क्षेत्र के दोनों ब्लॉक में आज से दो साल पहले हमने सरकार से सवाल किया था कि हमारे प्रखंड में कन्या विवाह योजना के तहत बच्चियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मात्र 125-100 करके बच्चों को पैसे दिये गये, उसके बाद आज तक दो साल बीत गये, कन्या विवाह योजना के पैसे अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं ।

साथ-ही-साथ, अभी हमारे यहॉ काफी विद्यालय में जैसे उपस्कर के लिए कई सामान गए, अच्छी बात है, प्रयोगशाला भी बन रही हैं लेकिन जो अभी स्थिति है, सरकार जल्द इसपर सुनवाई करे और शिक्षकों के धरने को जल्द से जल्द समाप्त कराने की कोशिश करे जिससे कि फिर से बिहार में शिक्षा बहाल हो और बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ पायें और शिक्षा ग्रहण कर पायें ।

महोदय, अभी फिलहाल हमारे कटिहार जिला में एक गॉधी हरिजन विद्यालय है, उस विद्यालय में महात्मा गॉधी जी भी आये थे, उस विद्यालय में मात्र

एक ही भवन है, एक ही रूम में खाना भी बन रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और पानी की भी सही ढंग से व्यवस्था नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वैसे हरिजन विद्यालय पर ध्यान दिया जाय जिससे कि वहाँ जो हमारे दलित विद्यालय बने हैं, उसमें बच्चे अच्छी तरह साफ-सुथरे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पायें ।

इसी के साथ-साथ, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं सभापति महोदय और पूरे सदन को धन्यवाद देती हूँ । जय हिन्द । जय हमारी जनता ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : श्रीमती बेबी कुमारी । 4 मिनट समय आपको एलौटेड है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ है । चाहे जीवनशैली हो या नैतिकता का पालन, शिक्षा विभाग की अहम भूमिका है । इसलिए राज्य सरकार सतत् संकल्पित है और इसीलिए सरकार शिक्षा विभाग का बजट लगभग सबसे अधिक निर्धारित करती है । वर्ष 2018-19 में शिक्षा विभाग की स्कीम मद में 19,107 करोड़ रु0 था तथा स्थापना एवं प्रतिपूर्ति व्यय में 13,018 करोड़ रु0 था, वर्ष 2019-20 स्कीम मद में 20,309 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिपूर्ति व्यय 14,489 करोड़ रु0 था । जो 2020-21 में स्कीम मद में 21,264 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिपूर्ति व्यय में 13,926 करोड़ रु0 किया गया । इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के बजट का कितना हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो रहा है । राज्य के शिक्षा विभाग ने इस देश में बिहार का नाम चमकाने का काम किया और यहां की परीक्षा प्रणाली हो या शिक्षकों की नियुक्ति हो सब के बारे में अध्ययन करने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण किया जायेगा । अभी बहुत सारी जगहों पर उत्क्रमण के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है । सैद्धांतिक उत्क्रमण सभी पंचायतों में हो चुका है । बस शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार है । नियुक्ति होते ही सरकार द्रुत गति से सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में पठन-पाठन प्रारंभ करा देगी । वर्तमान छात्र वर्ग-कक्षा अनुपात 40:1 को बेहतर करने हेतु 2,76,518 वर्ग-कक्षा का निर्माण कराया जा चुका है । कुल स्वीकृत 16,331 नये प्राथमिक विद्यालय एवं भवन के विरुद्ध 12,056 एवं 3000 भवनहीन हैं अर्थात् कुल 15,056 भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है ।

सभापति महोदय, मैं नियोजित शिक्षकों द्वारा किये जा रहे धरना-प्रदर्शन की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय । ये शिक्षक अपनी कर्मठता से राज्य के बच्चों को शिक्षा की रोशनी दिखा रहे हैं और इनकी मांगें लंबे समय से लंबित चली आ रही है।

सरकार ने भी सहानुभूतिपूर्वक समय-समय पर इनके वेतनमान में बढ़ोतरी की है लेकिन कुछ और बढ़ोतरी की आशा शिक्षकगण कर रहे हैं । मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और मैं सरकार से मांग करती हूं कि शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनकी मांगों को माना जाय ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कुछ क्षेत्र की समस्याएँ हैं स्कूल की, हमारे बोचहा में सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल है, वहां चहारदीवारी न होने के कारण पुस्तकालय में आये-दिन चोरी हो जाती है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करती हूं कि उसको करवाया जाय और मुसहरी के बिंदा हाई स्कूल में भवन न होने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है । शैला रामपुर, बोचहा में एक स्कूल है जहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां भवन नहीं होने के कारण पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, खासकर जहां भी हाई स्कूल बने हुए हैं वहां भवन नहीं होने के कारण पढ़ाई में काफी कठिनाई होती है । हमारे बोचहा क्षेत्र के देवगण पंचायत में घरवारा हाई स्कूल बन चुका है लेकिन ठेकेदार के द्वारा हैंडओवर नहीं किया जा रहा है ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया मैं बोचहा की महान जनता की तरफ से और अपनी तरफ से साधुवाद देती हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को मैं सहृदय धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, वादा तो किया था कृष्णनंदन बाबू से कि कुछ नहीं कहेगा नेमत, काली घटा देखकर नीयत बदल गई । इसलिये कि जो शिक्षा पर काली घटा छाई हुई है, उसपर तो कुछ कहना ही पड़ेगा ।

आज जो शिक्षक हड़ताल पर हैं, आज आप उनपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप उनके उपर एफ0आई0आर0 कर रहे हैं । आप निगोसिएशन करके उनसे सम्मानजनक समझौता कीजिए । आज स्टूडेंट रोड पर भटक रहे हैं, रोज जाते हैं स्कूल में और ताला बंद रहता है, लौट आते हैं । आप देखिये, शिक्षा का क्या हाल है । सबसे कम पढ़े-लिखे लोग बिहार में निवास करते हैं । यह स्थिति है शिक्षा की । महोदय, आज इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । अक्टूबर, 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के रूप में जारी हुआ था, जिसमें बिहार नीचे से सेकंड किया है, नीचे से दूसरे स्थान पर है,

अर्थात् 20 बड़े राज्यों में 19वॉं स्थान बिहार का है। यह एजुकेशन को आपने बनाकर रखा है । महोदय, बिहार में सारी शिक्षा पूर्णत: बर्बाद हो चुकी है ।

...क्रमश:...

टर्न-21/आजाद:अंजली/05.03.2020

..... क्रमश: .....

श्री मो0 नेमतुल्लाह : आप प्राईमरी स्कूल को देख लीजिए, प्राईमरी स्कूल में टीचर्स नहीं हैं । टीचर्स का अभाव है और पूरे नेशनल लेवल पर 40 स्टुडेंट पर एक टीचर्स की आवश्यकता है, आपके यहां कितना है 63 स्टुडेन्ट पर एक टीचर हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 40 स्टुडेन्ट पर एक टीचर की आवश्यकता है । महोदय, अधिकांश जो नियोजित शिक्षक हुए हैं, उसमें 52 हजार शिक्षकों के खिलाफ शिकायत मिली, लेकिन 60 हजार से अधिक प्राथमिक स्कूल में कोई फुलफ्लेज हेडमास्टर नहीं है। 2800 प्राथमिक स्कूल में क्लास रुम नहीं है और मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में बरौली के क्षेत्र के मांझा प्रखंड में गोपालगंज कोल्हुआ श्रीरामपुर में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में एक भी भवन नहीं है, उसमें हमने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से एक भवन दिया, जो नाकाफी है । इतने स्टुडेन्ट हैं कि उससे काम नहीं चलता है । इसलिए आप उसमें भवन बनवाने की कृपा करें । एक मांझा प्रखंड में एक शेखटोली है, उसमें पैसा भी है, जमीन भी है लेकिन सरकार उसमें भवन नहीं बना सकी है, इसलिए भवन बनवाने की कृपा करेंगे । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि यूनाइटेड इनफॉरमेशन सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन से मिले वर्ष 2014-15 से लेकर तक 2016-17 के आंकड़े के विश्लेषण से उपर्युक्त खुलासा हुआ है कि 2014-15 में 25.33 प्रतिशत ड्रौपआऊट हुआ, 2015-16 में 25.90 प्रतिशत ड्रौपआऊट हुआ, 2016-17 में 39.73 प्रतिशत ड्रौपआऊट हुआ, वही झारखंड में 23.15 प्रतिशत 2014-15 में और 2015-16 में 24.00 प्रतिशत, 2016-17 में 36.64 प्रतिशत, वही उत्तरप्रदेश में 7.30 प्रतिशत, 2015-16 में 10. 22 एवं 2016-17 में 12.71 प्रतिशत तो यह रेसियो है । आप सरकार में हैं तो आप ड्रौपआऊट पर अपना पीठ अपने थपथपाते हैं कि हमने साईकिल दे दिया, हमने पोशाक दे दिया,

रोशनी का फूल दिखाकर मुझे धोखा न दो,
याद है चमन में आग लग जाने की रात मुझे ।

महोदय, आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, आज लोग क्यों भाग रहे हैं प्राइवेट की तरफ । आज कोई भी हाईस्कूल किसी माननीय सदस्य को इनवाईट

नहीं करता है कि हमारे यहां कल्चरल प्रोग्राम होगा या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी । प्राइवेट स्कूल वाले आकर कहते हैं कि विधायक जी हमारे यहां प्रोग्राम दे दीजिए, आज कल्चरल प्रोग्राम है, आज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना है, क्यों, कहां गिर गया विद्यालय का स्तर, क्यों भाग रहे हैं गार्जियन, अपने बच्चों का नाम लिखाते हैं यहां और पढ़ाते कहीं और हैं । मीड-डे भोजन दे दिया, इसमें कितना भारी घोटाला है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए । इसकी भी आपको जांच करानी चाहिए, लेकिन आपके कान में जूँ नहीं रेंग रहा है आप तो एकदम अनसुने बैठे हुए हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं । आप सेविका को जो है वो आप नहीं देते हैं । महोदय, अभी हमारा दस मिनट टाइम है, अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुआ है और आपने हरी बत्ती जला दिया ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : आपका 10 मिनट समय था, अब 5 मिनट समय है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, ये बिहार की स्थिति है । महोदय, आप ने रसोईया को, आप देख लीजिए 1500 रू0 महीना देते हैं और बारह महीना खटाते हैं और दस महीना का पैसा देते हैं क्यों ? यही इंसाफ है आपका, आप उनका भी पैसा मानदेय बढ़ाइए । आप अपने संसाधन से उनको बढ़ा सकते हैं केन्द्र की तरफ आप क्यों ताक रहे हैं, अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप जो चाहिएगा आपको मिलेगा तो आप तो चाह नहीं रहे हैं, आप तो मांग नहीं कर रहे हैं, आप मांग कीजिए और आप लीजिए ।

महोदय, आप से मैंने गुहार लगाया था कि बरौली में डिग्री कॉलेज की स्थापना कीजिए । बच्ची और बच्चियां जाते हैं गोपालगंज में पढ़ने । मांझा में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कीजिए, जाते हैं बच्चे और बच्चियां पढ़ने । महोदय, सबसे इम्पोंटेंट बात है कि मदरसा के बारे में, संस्कृत का टीचर तक बहाल नहीं किया, न्यास बोर्ड आप तो बनाए नहीं, जिससे मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। महोदय, आप मदरसा में आठ साल पहले 2459 मदरसों को आपने केबिनेट से पास किया था, स्वीकृति दी थी लेकिन सिर्फ 805 मदरसे आपने स्वीकृत किए बाकि 475 मदरसा आपके फाइल में दबे हुए हैं लालफीताशाही का शिकार हो रहे हैं, आपके कान में जूं नहीं रेंग रहा है, आंदोलन कर रहे हैं मदरसा के यूनियन के टीचर्स लेकिन आप मौलना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी फारसी आपने बना दिया, लेकिन टीचर दिया है, एक भी टीचर है, वह आलिम और फाजिल नहीं पढ़ाता है, वहां मौलवी पढ़ाता है और एम0ए0 की पढ़ाई और इंटर और मैट्रिक के लोग पढ़ावेंगे ये व्यवस्था है आपके पास महोदय । इस तरह से एक भी टीचर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है किसके यहां, तो मदरसा बोर्ड के यहां और डिग्री कहां से

मिलती है उर्दू पारसियन फारसी मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी से और इस तरह से आपके पास टीचर हैं, एक भी नहीं, पढ़ाते कौन हैं जो अपने नहीं पढ़ पाते हैं । ये क्या व्यवस्था है आपकी सिर्फ डिग्री देने के लिए, फर्जी डिग्री बांटने के लिए। महोदय,

ना जाने कौन सी साजिश हुई बादलों के बीच,
मेरा ही घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई ।

महोदय, आप जो काम कर रहे हैं, उसमें सुधार लाइए, जनता माफ नहीं करेगी। झारखंड ने दिखा दिया आपके मुख्यमंत्री हार गए, आपके अध्यक्ष हार गए, पार्टी अध्यक्ष हार गए, आपके स्पीकर तक हार गए और आपकी उलटी गिनती शुरू हो गई और दिल्ली में क्या हुआ, हम सबलोग जानते हैं, आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब किया लेकिन जनता ने ठुकरा दिया आपको और बिहार से भी ठुकरायेगी और आपको रास्ता बाहर का दिखलाएगी । इसलिए आप अभी से सुधर जाइए और शिक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण है, व्यवस्था है, हमारा स्रोत है, मानव स्रोत है, ह्यूमेन रिर्सोस है,

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : उसको मजबूत कीजिए और एक छात्रावास है बरौली में मध्य विद्यालय में, जर्जर हालत में कब गिर जाएगा, कब घटना हो जाएगी, कब दुर्घटना हो जाएगी, कब लोग मर जाएंगे, इसलिए उसको भी शीघ्र बनाने की कार्रवाई कीजिए । आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया, समय के पहले ही हमको बैठा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया ।

डॉ0 जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग का बजट पेश हुआ है और मैं समझता हूँ कि बजट का बड़ा हिस्सा होता है शिक्षा बजट । विपक्षी कह रहे थे कि विकास दिखता नहीं है लेकिन यही विपक्षी जब घर में बैठते हैं, अपने लोगों के बीच बैठते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में निश्चित रूप से विकास हुआ है, काम हुआ है । भले राजनीतिक कारणों से कहें कि कोई विकास दिखता ही नहीं है । लेकिन घर में बैठते हैं तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है, स्कूलों में परिवर्तन हुए हैं, स्कूलों के भवन बने हैं, शिक्षक की बहाली हुई है, हाईस्कूल का निर्माण हुआ है, उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण हुआ है । यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा का निर्माण हुआ, जो खण्डहर के समान था, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनकी रचनात्मक सोच, उनकी सकरात्मक सोच, उनके सकारात्मक विचार ने जो हमारे धरोहर थे, उस धरोहर को नये सिरे से

कायम किया है । एक समय था, हमलोग भी पढ़ते थे 2005 के पहले, 2005 में मुझे विधायक बनने का मौका मिला, क्या स्थिति थी, हमलोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, लोगों की मानसिकता यही हो गई थी और स्थिति यही थी कि बिहार में पढ़ाई नहीं होती है । 2005 के पहले मैं भी पढ़ता था एम0एम0 में कॉलेज में, पढ़ाई नहीं होती थी, हमलोग दिल्ली जाकर पढ़ते थे, हमलोग दूसरे जगह आकर पढ़ते थे । हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने शून्य से शुरू किया, जो कार्य होना चाहिए था 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 के पहले, वह काम हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में 2005 से शुरू हुआ । यह हम नहीं कहते हैं कि यह हमारी पराकाष्ठा है, हम यह नहीं कहते हैं कि सब कुछ हो गया लेकिन जो काम 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले होना चाहिए था, उस काम को शून्य से शुरू करना पड़ा ।

.... क्रमशः ....

टर्न-22/शंभु-धिरेन्द्र/05.03.2020

डॉ0 जितेन्द्र कुमार : क्रमशः....इसलिए महोदय, हम तो जाकर देखते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं । गॉव में स्कूल नहीं थे, भवन नहीं थे, स्कूल में शौचालय नहीं थे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए ब्लॉक में जाना पड़ता था । भवन नहीं थे क्या स्थिति थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया है और आने वाले दिन में हर हाईस्कूल में स्कूल खुलेंगे, अब देखिये जनसंख्या की आधी आबादी महिला की है और महिलाएँ जब पढ़ नहीं पाएगी तो विकास अवरूद्ध हो जाएगा । माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है एक सृजन का विचार है । इन लोगों ने कहा कि केवल साइकिल है वो साइकिल नहीं है पीन ड्रॉप साइलेंस रिवोल्यूशन हैं । मौन क्रांति है एक समय जब हमलोग पटना में पढ़ते थे और जब लड़कियॉ लोग साइकिल चलाती थी पटना की सड़कों पर तब लोग घूर-घूर कर देखते थें, फब्तियां कसते थे । आज गॉव की पगडंडियों पर लड़कियॉ साइकिल चला रही है तो क्या यह विकास नहीं है । यह एक सामाजिक क्रांति है । एक सोशल रिवोल्यूशन है यही तो विकास है । जो लोग सोचते नहीं थे उस काम को माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, जिसके बारे में लोग सपना भी नहीं देखते थे उस काम को अमलीजामा पहनाने का काम किया है और सबसे बड़ी खासियत है हमारे नेता में हर पल सोचते है हर वक्त सोचते हैं और केवल खाका ही नहीं तैयार करते योजनाओं का, उस योजना का शिलान्यास भी करते है ।

शिलान्यास भी सिर्फ नहीं करते हैं, उस कार्य को अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं, ये है आदरणीय नीतीश कुमार जी । हम और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है । शिक्षा के सहारे ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, स्वावलंबी हो सकते है, निरक्षर व्यक्ति से पूछिये कि कितनी तकलीफ है, वो बयान करेंगे काफी तकलीफ है । एक डेग चल नहीं पाएंगे, एक कदम चल नहीं पाएंगे, इसलिए शिक्षा का महत्व हमलोगों ने समझा है और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को और गति देने का काम किया है । शिक्षा एक ऐसा धन है जिसके सहारे हम हर झंझावातों का सामना कर सकते हैं, हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हर परिस्थितियों का सामना कर सकते है और अगर कोई शिक्षित हो जाए कोई व्यक्ति तो धन बर्बाद हो सकता है लेकिन शिक्षा बर्बाद नहीं कर सकता है कोई । कोई चोरी भी नहीं कर सकता है शिक्षा का, कोई डकैती भी नहीं कर सकता है शिक्षा का, कोई किडनैपर भी उस शिक्षा को किडनैपिंग नहीं कर सकता है । शिक्षा जीवनपर्यंत आपके साथ अच्छे मित्र की तरह रहता है और हर चुनौतियों में आपका साथ देता है । भाई-भाई अलग हो सकता है लेकिन जो शिक्षा है वो जीवनपर्यंत आपके साथ रहता है और इसकी काफी भूमिका रही है । महोदय, लगातार हमारी सरकार ने काम किया है आज लड़कियों के उत्थान के लिए किया, अगर मैट्रिक में वो प्रथम डिविजन से पास करती है तो 10 हजार की राशि, इंटरमीडिएट में पास करती है तो 10 हजार की राशि, स्नातक करती है तो 25 हजार की राशि, यही तो विकास है महोदय, यही तो तरक्की है महोदय, की लगातार विकास किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, इंजीनियर नहीं बना पाते थे, डॉक्टर नहीं बना पाते थे, हायर एजूकेशन नहीं दिलवा पाते थे, मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि उनमें भी प्रतिभा है, उनमें भी काबिलियत है, उनमें भी क्षमता है, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की नीति बनाई, आज उस योजना से लोग डॉक्टर बन रहे है, इंजीनियर बन रहे हैं, हायर एजूकेशन ले रहे हैं, यही तो विकास है महोदय । आज महोदय कह रहे हैं नियोजित शिक्षक के बारे में, एक समय था याद कीजिए कि जब नियोजित शिक्षक बहाल किए जा रहे थे तो कई तरह की टिप्पणियाँ आ रही थी कि शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है, शिक्षक में कोई क्षमता नहीं है, आज हितैषी बन गए हैं । हम जानते हैं कि आपलोग केवल घड़ियाली आँसू रो रहे हैं अगर उनकी माँग भी मानी जाएगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सहानुभूति से विचार कर के उनकी माँग भी मानी जा रही है, विचार भी किए जा रहे हैं, लेकिन आप तो केवल क्रेडिट लेना जानते हैं कि हम

ही ने किया है । नियोजित शिक्षक के बारे में टिप्पणियाँ क्या थी अखबार के पन्नों में देखिए, उस टिप्पणियों को अगर देखा जाए तो वो शिक्षक आपको माफ नहीं करेंगे, ऐसी टिप्पणियाँ थी । तो महोदय, आज देखिए हमलोग प्राईवेट स्कूलों में जाते है, स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, पढ़ते हैं । लेकिन हाई स्कूल में हमलोगों ने शुरू किया है उन्नयन बिहार योजना का हर घर 9वीं और 10वी क्लास में उन्नयन बिहार योजना के तहत, टी0वी के माध्यम से, पेन-ड्राइव के माध्यम से पढ़ाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मनोरंजन है । मनोरंजन करते-करते पढ़ाना, ये भी एक खासियत है, इसलिए हमलोग यही चाहते हैं कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है वो ग्रामीण क्षेत्र में । हम तो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं । ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति थी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे, आज देखियेगा कि जिला स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज । आज जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर आई0टी0आई है तो महोदय, इतने सारे विकास हो रहे हैं । आज ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है यह सर्वविदित है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में बिहार तरक्की किया है, बिहार विकास किया है, लेकिन महोदय, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय भी बैठे हैं । हमारे नालंदा जिला में सरमेरा प्रखंड है महोदय, हमने कई बार 2005 के पहले, हमने एक निर्माण हुआ था बी0आर0सी0 भवन और आज भी बी0आर0सी भवन नहीं बन पाया । मेरा सुझाव है कि उसे देख लेने की आवश्यकता है ताकि वहाँ का जो अवरोध है, उस अवरोध को दूर करते हुए, वहाँ भी बी0आर0सी0 भवन का निर्माण होना चाहिए । मेरा एक सुझाव है महोदय जितने भी हाई-स्कूल हैं या मध्य विद्यालय हैं, या माध्यमिक विद्यालय हैं उसकी भी घेराबंदी हो महोदय । ताकि वहाँ भी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं हो महोदय ।

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : समाप्त करे, आपका समय हो गया ।

डॉ जितेन्द्र कुमार : 2 मिनट महोदय, हम कहना चाहेंगे कि जिन विद्यालयों या हाई-स्कूलों में भूमि है उस भूमि को घेराबंदी किया जाए महोदय, ताकि वहाँ भी खेल मैदान आदि का निर्माण हो सके । अंत में कहना चाहेंगे महोदय कि कई ऐसी जगह है जहाँ इंगलिश के 10 शिक्षक है, उर्दू के 5 शिक्षक हैं, बैलेंस तरीके से संतुलित तरीके से पदस्थापन किया जाए, ताकि इसका भी लाभ लोगों को मिल सके ।

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी) : अब समाप्त करें ।

श्रीमती रेखा देवी : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज हमे सदन में बोलने का मौका मिला । मैं आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को, मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिनकी कृपा से आज में सदन में बोल रही हूँ । महोदय, आज मैं सरकार द्वारा शिक्षा एवं अन्य विभाग पर लाया गया अनुदान मांग के विरोध में विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ । महोदय, हम दलित परिवार से आते हैं, बहुत संघर्ष करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा सदन जानता है किसी भी वर्ग के विकास के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है जबकि आज-कल विद्यालय में शिक्षा के नाम पर बच्चे को कटोरा थमा दिया गया है । स्कूल की क्या हालत है महोदय । शिक्षक हड़ताल पर हैं, कई प्रखंडों में शिक्षक पदाधिकारी नहीं हैं, कोई अनुशासन नहीं है तो गरीब लोग आगे कैसे बढ़ेंगे । मैं आपसे बता देती हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव राज्य बहुजन का स्वर्णिम राज्य था । जिससे उनका उचित विकास हुआ, लेकिन आज शिक्षा अराजकता का रूप ले चुकी है ।

क्रमशः

टर्न-23/05-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्रीमती रेखा देवी : महोदय, शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है । आज वर्तमान समय में इस मानव जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, आवास के बाद शिक्षा की अति आवश्यकता है । आज हमारे राज्य में डिजीटल इंडिया की बात भारत सरकार एवं राज्य सरकार करती है । महोदय, माध्यमिक विद्यालय, श्री राम हरि उच्च विद्यालय बहेड़ा, धनरुआ एवं नंद किशोर उच्च विद्यालय, बलरामपुर धनरुआ में मात्र दो कमरा है, जिसमें कार्यालय चलता है । छात्र छात्राओं को बैठने के लिए कोई कमरा नहीं है । माननीय मंत्री महोदय, द्वारा पिछले सदन में भवन निर्माण की बात कही गई थी लेकिन आज तक भवन नहीं बन पाया है, जिससे बच्चे-बच्चियों को पठन-पाठन में कई कठिनाई हो रही है । जो कि उनके मूल अधिकार से वंचित होना पड़ता है । महोदय, शिक्षा के लिए कुशल शिक्षक की आवश्यकता है, जिसकी घोर कमी है वर्तमान सरकार शिक्षकों को नियोजन कर उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाकर के गरीब बच्चे-बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं । महोदय, सभी शिक्षक-शिक्षकाओं को विद्यालय की योजनाओं यथा भवन-निर्माण में मध्याह्न, भोजन से दूर रखा जाए। अधिकतर शिक्षक-शिक्षकाएँ मध्याह्न भोजन, योजना एवं भवन-निर्माण के लिए आवास में गुटबाजी करते हैं जिससे बच्चे-बच्चियों का पठन-पाठन प्रभावित होता

है । महोदय, वास्तव में शिक्षा का जो बजट है सिर्फ दिखलावा है । उससे गरीब बच्चे-बच्चियों को सही लाभ नहीं मिल पाता है । सभापति महोदय, आज विद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है । जिसकी बहाली नहीं होने पर उच्च शिक्षा अध्ययन का कार्य बिल्कुल बंद है जिससे पिछड़े, अति पिछड़े, छात्र-छात्राओं को आर्थिक मजबूरी के कारण निजी विद्यालयों एवं विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं । सभापति महोदय, इन दिनों सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का हड़ताल चल रहा है, जिसमें गरीब बच्चे-बच्चियों का पठन-पाठन बंद है । जिससे राज्य सरकार जानबूझकर शिक्षकों के मामले पर मौन है, जिसका प्रभाव बच्चे-बच्चियों के अध्ययन पर ज्यादा पड़ता है क्योंकि वो ऊंची फीस देकर निजि विद्यालयों में महाविद्यालयों में नहीं जा सकते । इन बातों के ध्यान के साथ मैं अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देती हूँ । महोदय, आज सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि शिक्षा का विकास हो रहा है ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमति रेखा देवी : अब शिक्षा गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है । अब समय नहीं है इसलिए मैं सभापति महोदय आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरे सदन को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुनने का काम किया और अपनी जनता मालिक को भी धन्यवाद देती हूँ । जय हिन्द, जय भारत, जय लालू प्रसाद ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : श्री राजीव नन्दन ।

श्री राजीव नंदन : सभापति महोदय, मैं विपक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के बजट के लिए लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । शिक्षा विभाग द्वारा पेश बजट पर शुरुआत करने से पहले मैं पहले एक दो लाईन की पंक्ति सदन के बीच में रखना चाहूँगा :

''जरुरी नहीं रोशनी लालटेन से ही हो,
जरुरी नहीं रोशनी लालटेन से ही हो,
शिक्षा से भी घर रोशन होते है,
शिक्षा से भी घर रोशन होते है ।''

आज महोदय, जिस शिक्षा की बात की जा रही है । यह निश्चित है कि भारत पूरे विश्व में मगध की धरती पर बिहार शिक्षा के मामले में वर्षों से रहा है, केन्द्र रहा है आज हम विश्व प्रसिद्ध हैं, ज्ञान की भूमि को लेकर, मोक्ष की भूमि को लेकर, बोध गया को लेकर तो कहीं न कहीं शिक्षा तो हमारे कण-कण में है लेकिन इस कण-कण को संभालने के बदले बिगाड़ने का काम किसने

किया ? विचार करने की जरुरत है । आज हमारे यहाँ विद्यालय, नालन्दा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय बहुत छोटे-छोटे विश्वविद्यालय हुआ करते थे और आज तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में चला गया है तो कहीं-न-कहीं बिहार में दो विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय थे, आज क्या हो गया ? आज इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1830 में जब अंग्रेजों के द्वारा पूरे भारत पर कब्जा हो गया तो उन्होंने एक आदमी को भारत भेजा कि जाओ पता लगाओ कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में क्या काम किया जाय जिससे लंबे समय तक भारत में अंग्रेजों का शासन चलता रहे ।

सभापति(श्री रामचंद्र सहनी) : अब समाप्त करें ।

श्री राजीव नंदन : वो आदमी, महोदय, एक मिनट ।

सभापति (श्री रामचंद्र सहनी): समय नहीं है समाप्त करें, सरकार का उत्तर होना है ।

श्री राजीव नंदन : सभापति महोदय, 8 मिनट था, महोदय । अब वो जो विषय था लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मैं भारत में ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहा हूँ कि रोज एक नया अंग्रेज पैदा होगा और वही शिक्षा नीति अभी भी चल रही है, जिसको बदलने की जरुरत है ।

सभापति(श्री रामचंद्र सहनी): आप समाप्त करें । श्री अनिल कुमार यादव ।

श्री अनिल कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों के प्रस्ताव पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन एवं सरकार के प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, सरकार ने शिक्षा विभाग का कुल बजट 35191.05 करोड़ का पेश किया है । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े बजट होने के बावजूद बिहार में जो हमारी शिक्षा का गौरवशाली इतिहास था और आज हमारे पक्ष के साथी कहते हैं, सरकार के साथी इतना बड़ा बजट और बावजूद इसके शिक्षा की इतनी बदहाल हालत है बिहार में । बड़ी-बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है । विद्यालय भवन जरुर बने हैं, महाविद्यालय भवन जरुर बने हैं, तकनीकी संस्थान जरुर बने हैं, मेडिकल कॉलेज जरुर बने हैं लेकिन वहाँ शिक्षक कहाँ है ? वहाँ आपके छात्रों को पढ़ने के लिए शिक्षण संस्थान खाली रहते हैं और हमारे बिहार का पैसा बंगलौर जाता है, मद्रास जाता है, वहाँ जाते हैं लोग पढ़ने के लिए । हमारी शिक्षा की बदहाली- इस बात पर भी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैंने समाचारपत्र में पढ़ा कि 7 हजार सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त है और उसमें से बहाली होगी 4500 की तो 7 हजार रिक्त पद हैं जबकि छात्रों के अनुपात में और चाहिए और आप बहाली कर रहे हैं । आपके साथ क्या कारण है कि 4500 की ही बहाली करेंगे और फिर

बहाली करने में कई साल लगेंगे इसका भी हमलोगों को इंतजार हैं । मैं आपसे बता देना चाहता हूँ श्रीमान् आज वित्त रहित कॉलेज, को इन्होंने कलंक कहा है, जिसने शुरु में खोला लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वित्त रहित कॉलेज में जो शिक्षक हैं उनको मैं अनुदान के माध्यम से पैसा दूँगा । सही बात है और सारे लोग खुश हुए । सारे वित्त रहित शिक्षक आपके मुरीद हो गए और आज छात्र पढ़ते हैं तो उसी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी वित्त रहित कॉलेज के अंदर हमारे छात्रों की पढ़ाई होती है लेकिन 2011 से आपने उसका अनुदान बंद कर रखा है । उसको एक सपना दिखाकर आपने उसको ठगने का काम किया और फिर कह रहे हैं कि 2011 से बंद होने के बाद, हम जो दो साल का देंगे।

क्रमशः

टर्न-24/कृष्ण/05.03.2020

श्री अनिल कुमार यादव (क्रमशः) - इसके बाद नियोजन आपने किया । जो विद्यालय आज हमारे बंद हैं और नियोजित शिक्षक सड़क पर हैं । महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यह एक मात्र यह नियोजन पद्धति है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चलाने का काम किया है । कबीर दास की एक दो पंक्ति मैं सुना देना चाहता हूं - कबीर दास की उल्टी वाणी,
बरसे कम्बल भींगे पानी ।

पहले तो आपने कहा कि डिग्री लाओ, नौकरी पाओ । चाहे वह फर्जी डिग्री क्यों न हो । एक मिनट । फिर आपने कहा कि दक्षता जांच परीक्षा लेंगे । महोदय, यह पहला उदाहरण है कि पहले बहाली होती है और परीक्षा बाद में होती है । फिर आपने दक्षता जांच परीक्षा लेने का काम किया, फिर आपने उनको ट्रेंड करने का काम किया । जब आपने ऐसा काम किया तो फिर आप उनको नियमित शिक्षकों की तरह वेतन क्यों नहीं देते है ?

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : सभापति महोदय, किसी महापुरूष ने ठीक ही कहा है कि किसी कॉम को बर्बाद करना है तो उससे उसकी शिक्षा छिन लो और यही शिक्षा छिन लेने के नक्शे कदम पर भाजपा समर्थित नीतीश कुमार की सरकार चल रही है ।

महोदय, शिक्षा घोटाला । ए0सी0डी0सी0 तो आपने सुना होगा, बिहार में मेधा घोटाला हो रहा है, पूरे विश्व में केवल बिहार में ही मेधा घोटोला हो रहा है । शिक्षा के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या है, यह इसी बात से पता चलता है कि महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की जो उपेक्षा हुई, अवहेलना हुई, उसकी लाश का

जिस तरह से अपमान हुआ, उनके प्रति जो शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार का जो आचरण हुआ, यह शर्म की बात है ।

महोदय, आंकड़ा के भ्रम जाल में फंसा करके नीरस को सरस नहीं बनाया जा सकता है । महोदय, मैं दावा करता हूं कि पढ़ाई-लिखाई बर्बाद हो गयी है, शिक्षा बर्बाद हो गयी है, यह सच बात है । हमारे विरोधी दल के बहुत से हमारे दोस्त यह बोलते हैं कि बात तो सच है महबूब साहब लेकिन क्या करें, हमलोगों को तो तारीफ के पुल बांधने हैं ।

महोदय, आज प्राथमिक विद्यालयों में गरीबों के बच्चों की पढाई नहीं हो रही है और जब हम गरीबों के बच्चों की बात करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को गरीबों की बात बकवास लगती है । महोदय, अगर यह बकवास है तो हम यह बकवास हमेशा करते रहेंगे । महोदय, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई नहीं हो रही है । गरीबों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई होगी कैसे ? भवनहीन विद्यालय 1773 है और 1140 विद्यालय को बंद कर दिया गया है ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : आप बैठ जाईये । माननीय सदस्या श्रीमती मंगिता देवी ।

श्रीमती मंगिता देवी : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। साथ ही साथ मैं अपने नेता सामाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्षता के प्रणेता आर0जे0डी0 सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू यादव के प्रति, नेता,प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं ।

सभापति महोदय, बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है । अप्रील,2020 में इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । महोदय, सरकर द्वारा मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किये जाने से पहले शिक्षक, वर्ग कक्ष, उपस्कर एवं आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाना चाहिए था । इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु एक भी शिक्षक की नियुक्ति आज तक नहीं की गयी है । छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है । भवन का भी आभाव है । वैसे मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित कर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

महोदय, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्व शिक्षा अभियान मद में 14013.59 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावाधान किया है । महोदय, मेरा

मानना है कि वर्तमान सरकार के शासन काल में सबसे ज्यादा लूट सर्व शिक्षा अभियान मद में राशि की हो रही है ।

महोदय, अपने राज्य बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की स्थापना 1991 में हुई थी । इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु के बच्चों को, वर्ग 1 से 8 आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना एवं 15 से 35 आयु वर्ग के बाल निरक्षरों को साक्षर बनाना था । तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा0 रामचन्द्र पूर्वे ने सीतामढ़ी जिला में सर्वप्रथम 1992 में इसे लागू किया ।

महोदय, भारत सरकार के 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत, बिहार की साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत और सीतामढ़ी जिला की साक्षरता दर 53.53 प्रतिशत है ।

महोदय, बिहार के 38 जिलों में साक्षरता के मामले में सीतामढ़ी का 37वां स्थान है । वर्तमान सरकार विगत 15 वर्षों में साक्षरता के नाम पर अरबों रूपये सरकारी खजाने से निकाल कर सरकारी राशि का बंदर बांट किया । वर्तमान सरकार विकास की बात करती है परन्तु ऐसा सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलता है । धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है । जब तक हम शत्-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, विकास की बात करना बेमानी है ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : आप समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र पासवान ।

श्री उपेन्द्र पासवान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद जी के द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मैं खडा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । महोदय, मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने स्वतंत्र भारत मे आजादी की दूसरी लडाई लडकर गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, अकलियत वर्ग के लोगों के मुंह में आवाज और ताकत देने का काम किये है, जो आज सामाजिक न्याय की युद्ध में युद्धबंदी बनाये गये हैं।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र की महान जनता का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे चुनकर इस सदन में भेजने का काम किया है ।

महोदय, आज भारतीय राजनीति में अगर राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष न होते तो मौजूदा हालत में लोकतंत्र को बचा पाना मुश्किल है ।

महोदय, कल देश में नफरत का प्रसाद बांटनेवाले लोग आज महात्मा बुद्ध का उपदेश दे रहे हैं, गांधी जी की हत्या करनेवाले की पूजा कर महिमामंडित

करने का प्रयास किया जा रहा है, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराओं को भी खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है । इस अमीरी वाले देश में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है । बाबा साहेब अम्बेदकर द्वारा पारित संविधान को छेड़छाड़ कर संविधान मे वर्णित आरक्षण को भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । माननीय उप मुख्यमंत्री ने चरवाहा विद्यालय का जिक्र अपने बजट में किया है । उन्होंने जिक्र किया है-चरवाहा विद्यालय बनाम आधुनिक विद्यालय । महोदय, मुझे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चरवाहा विद्यालय को भी बजट में समावेश करने का काम किये हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ..

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी : आपका समय समाप्त हो गया । आप समाप्त कीजिये ।

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदयय, एक मिनट, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में 150 चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किये थे । इसके पीछे उनका यह उद्देश्य था कि हमारे गरीब, दलित, शोषित वर्ग के जो भाई हैं, जो गाय, भैस, बकरी चरानेवाले हैं, वे चरवाहा विद्यालय के माध्यम से भी अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

क्रमश :

टर्न-25/अंजनी-अभिनीत/05.03.2020

श्री उपेन्द्र पासवान: (क्रमश:) : और इसी उद्देश्य से उन्होंने गरीब, दलित, शोषित वर्ग के लोगों को चरवाहा विद्यालय के माध्यम से उन्होंने स्वर देने का काम किया । समय-सीमा का अभाव है, मैं अपने क्षेत्र की ओर...

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह।

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदय, मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इसी सदन में मैंने अपने क्षेत्र के अनुमंडल डिग्री कॉलेज के लिए मुद्दा उठाया था और माननीय मंत्री महोदय ने एक सप्ताह के अन्दर भूमि.....

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बजट पर विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, विपक्ष के हमारे माननीय साथीगण शिक्षा विभाग पर कई प्रकार का तर्क और कुतर्क कर रहे थे और बता रहे थे कि लालू जी के 15 साल के राज-काज और माननीय नीतीश कुमार, श्री सुशील मोदी और आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी के 15 साल की तुलना कर रहे थे । महोदय, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वह 15 साल का जो राज था, वह राज था लाठी भजावन और तेल पिलावन और यह जो 15

साल का राज है, इस राज में था स्याही भरावन और कलम पकड़ावन । यह राज कलम पकड़ावन का राज था और महोदय जब घोटालों की बात आती है तो याद होगा कि हमारे विपक्ष के साथियों सहित सदन के सभी साथियों को, सुरेन्द्र भाई आप प्रोफेसर हैं, जरा सुन लीजिए कि क्या हुआ था, जब उस समय लालू जी का राज था और प्रोफेसर घोटाला हुआ था तो आज भी इसी सदन में एक माननीय हैं, जिनको उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने प्रोफेसर बनाया था और वह प्रोफेसर साहेब जब पटना के वीमेंस कॉलेज में ज्वाईन करने गये थे तो वीमेंस कॉलेज की प्रिंसपल मिस्टर निसोरिया ने कहा था कि आपको एप्लीकेशन लिखने का लूर नहीं है, इसलिए आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा और उस समय के माननीयों ने अपने ड्राईवर को, अपने नौकर को, कई लोगों को प्रोफेसर बनाया था जिसको विचार मीमांसा पत्रिका ने पूरा उद्धृत किया था और जब सरकार की तौहीनी होने लगी थी तो उस विज्ञापन को कैंसिल किया गया था । आपको उस समय का राज याद होगा, जब आप चरवाहा, हलवाहा की बात करते थे और आज बिहार के नौजवान, बिहार के पढ़े-लिखे लोग देश के टॉप परीक्षाओं में टॉपर कर रहे हैं, चाहे वह आई0ए0एस0 की परीक्षा हो या देश स्तर का कोई भी परीक्षा हो तो आज यह स्थिति है । आप शिक्षा की बात करते हैं, जब आपका समय था और बारिस होती थी तो विद्यालय के शिक्षक छुट्टी दे दिया करते थे चूंकि स्कूल का छत नहीं था । कहीं लीची के गाछ के नीचे तो कहीं आम के गाछ के नीचे पढ़ाई होती थी लेकिन आज बिहार के सभी स्कूलों के भवन हैं, अधिकाधिक स्कूलों में भवन है, 99 प्रतिशत स्कूलों में भवन हैं जहां बच्चे बैठकर पढ़ते हैं । आज की क्या स्थिति है एक प्रतिशत से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर नहीं हैं और आप तुलना करके कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त करिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आप याद कीजिए उस दिन को गरीब घर की बच्चियों को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते थे, सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती थी और इसी सरकार ने उन बच्चियों को तन ढकने के लिए कपड़ा दिया और वह विद्यालय जा रही है । समय बहुत कम है, दो मिनट सर । मैं कहना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षकों की चर्चा हो रही थी जो हड़ताल पर हैं, उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए लेकिन इनको भी याद करना चाहिए कि जब आदरणीय लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे तो देश का सबसे बड़ा हड़ताल 6 महीने से ज्यादा का हुआ था । इसलिए नियोजित शिक्षकों पर भी विचार

होना चाहिए, चूंकि मुझे समय कम मिला है और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : माननीय सदस्य श्री कमरूल होदा ।

श्री कमरूल होदा : सभापति महोदय, मैं इस मजलिस का एक विधायक हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद । शिक्षा विभाग के द्वारा जो बजट लाया गया है, उसके विरोध में और जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं जिस जगह से आया हूँ, वह राजधानी से 400 किलोमीटर दूर किशनगंज है । बिहार में सीमांचल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा जिला है । सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास और गुणवत्ता शिक्षा। बिहार की जनता ढूंढ़ रही है कि कहां है गुणवत्ता शिक्षा और कहां है न्याय के साथ विकास । बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साल में एक बार बिहार राज्य की तरफ से फरोग-ए-उर्दू के लिए सेमिनार किया जाता है, क्या इससे उर्दू का फरोग बहाल हो जायेगा । फरोग-ए-उर्दू के लिए यहां जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल में उर्दू का किताब नहीं है, प्राइमरी स्कूल में उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहां पर हिन्दी पढ़ाने वाला शिक्षक है, उर्दू पढ़ाने वाला शिक्षक वहां पर नहीं है और आप गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं । प्राइमरी विद्यालय को मध्य विद्यालय बना दिया और उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बना दिया गया और आज स्थिति यह है कि पूरे बिहार में......

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त करें ।

श्री कमरूल होदा : जितने भी हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं रहने के वजह से शिक्षा बाधित हो रही है । चूंकि मुझे बोलने का मौका दिया, मैं समर्थन करता हूँ भाई नेमतुल्लाह जी का ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर सिंह निषाद, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : सभापति महोदय, आज मैं सदन में शिक्षा विभाग की मांग के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आज संपूर्ण मानव के लिए शिक्षा का कितना महत्व है यह सब जानते हैं लेकिन मैं विपक्ष के साथियों की तरफ से जो शिक्षा विभाग के बजट में कटौती का प्रस्ताव लाये हैं उस पर मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ सुरेन्द्र यादव जी बोलते हैं कि शिक्षा विभाग के बजट को बढ़ाया जाय और दूसरी तरफ इनलोगों का

कटौती प्रस्ताव आया है, पता नहीं आपस में ही इन लोगों के विचारों में विरोधाभास है। साथ-ही उपेन्द्र पासवान जी बोल रहे थे और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। ये लोग लालू जी के कार्यकाल की बड़ी सराहना कर रहे थे कि डेढ़ सौ चरवाहा विद्यालय खोले गये थे । मैं तो समझता हूं कि वह काल लगभग शायद लालू जी के लिए बहुत ही बड़ा काला दिन होगा जिन्होंने जिस दिन चरवाहा विद्यालय खोला था और पूरे भैंस को और चरवाहों को उस विद्यालय में बंद कर दिया, पूरा चारा डकार गये और रांची के जेल में आज सड़ रहे हैं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विद्या सागर निषाद जी आप अपनी बात एक मिनट में कह लीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है।

श्री विद्या सागर सिंह निषाद: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक इन्दिरा गांधी रामजी राय विद्यालय है जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं इसको सुलझायें । साथ ही मेरे क्षेत्र में चार ऐसे बड़े-बड़े हाई स्कूल हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग डेढ़ हजार से ऊपर है। एक हाई स्कूल सोंगर, एक हाई स्कूल राय टोली, एक हाई स्कूल तिसवारा और एक हाई स्कूल बाजितपुर करनैल जिसमें भवनों की कमी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन हाई स्कूलों के भवनों को अतिशीघ्र बनाने की कृपा करेंगे और अंत में सरकार के द्वारा लाये गये बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे कि विधायक लोग विश्वविद्यालय के सीनेट के मेम्बर होते थे लेकिन चार साल के बाद एक भी विश्वविद्यालय में मेम्बर नहीं है ।

टर्न:26/राजेश-राहुल/5.3.20

<u>सरकार का उत्तर ।</u>

अध्यक्ष: अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री कृष्णननंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने शिक्षा विभाग की डिमांड पर अपने विचार रखें । कुछ लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। महोदय, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, जिससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं और 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार की बागडोर आयी, उसके बाद से काफी काम हुए न शिर्फ शिक्षा विभाग में, बल्कि

अन्य विभागों में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और आज सब उन कामों की प्रशंसा करते हैं । शिक्षा विभाग में शिक्षा की उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लगातार यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भौतिक बल और चरित्र शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है । प्राचीन काल से ही शिक्षा के मामले में बिहार का इतिहास बहुत की गौरवशाली रहा है, वर्ष 2005 से माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा गौरवशाली इतिहास को पुनः प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास किए गए हैं, इस हेतु बिहार के चतुर्दिक विकास में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ शिक्षा बल्कि अन्य विभागों में भी हम लोगों ने न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास किया है और इसका मतलब यह है कि हम सभी लोगों को, तमाम लोगों को साथ ले करके, बगैर किसी भेदभाव के सब लोगों के हितों का ख्याल करते हुए, सब लोगों के विकास के लिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि:-

''अपना तो काम है, जलाते चलो चिराग,
रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले ।''

आपकी आवाज में बहुत बुलंदी है लेकिन आपसे एक वादा लेना चाहेंगे हम कि:

''आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो,
आज जाने की जिद न करो ।''

महोदय, वर्तमान में राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों-बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए अनेक योजनाएँ संचालित कि जा रही हैं । सरकार की योजना में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है और सभी वर्गों एवं धर्मों के मानने वालों को अपनी क्षमता के विकास का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है । इसमें हमें सफलता भी मिली है । मैं सिलसिलेवार ढंग से सदन के समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को रखता हूं:

प्राथमिक शिक्षा: महोदय, 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों को विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र सापेक्ष दक्षता देकर शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है । 2005-06 में सर्वे कराया गया था कि कितने बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, तो पता चला कि साढ़े बाहर प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, इसमें सबसे अधिक बच्चे या तो अल्पसंख्यक समाज के थे या फिर

महादलित वर्ग के थे, उनको स्कूल पहुचाने के लिए 30 हजार उत्थान केन्द्र और तालीमी मरकज खोले गए । उत्थान केन्द्र टोला सेवक के द्वारा एवं तालीमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवी के माध्यम से संचालित किए गए ताकि बच्चे स्कूल आए और इसका एवं अन्य योजनाओं का सुपरिणाम यह है कि विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की संख्या मात्र एक प्रतिशत से भी कम है, सरकार इन बच्चों को भी विद्यालय से जोड़ने के लिए कृतसंकल्पित है और हमें विश्वास है कि उन्हें भी जल्द से जल्द विद्यालय से जोड़ दिया जाएगा ।

प्रारम्भिक विद्यालय की स्थापना: महोदय, सभी बसावट क्षेत्र के एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय एवं तीन किलोमीटर की परिधि में मध्य विद्यालय सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 से अब तक 21,264 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए तथा 19625 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया, यहीं नहीं 16,145 नए प्राथमिक विद्यालय भवन और 2,70,403 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण पूर्व से अवस्थित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में किया गया है । राज्य सरकार की संजिदगी इससे भी छलकती है कि भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नए प्राथमिक विद्यालय के भवन के निर्माण हेतु राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण नौ सौ सैंतालसि नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य योजना से 1,91,39,84,438 रूपये की राशि दिनांक 27.02.2020 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गई ।

पुस्तक क्रय हेतु राशि का स्थानांतरण: महोदय, बिहार राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पुस्तक की आपूर्ति की जाती है । यह परम्परा बिहार में भी थी । इससे बच्चों तक पुस्तक पहुचने में काफी विलम्ब होता था और माह अक्टूबर, नवम्बर तक बच्चों को पुस्तक मिल पाता था । माननीय नीतीश कुमार जी ने इस समस्या पर गम्भीर चिन्तन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि छात्र को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होते ही पुस्तक क्रय हेतु राशि उपलब्ध हो जाय ताकि बच्चों को पुस्तकों के अभाव में शिक्षा में रूचि की कमी नहीं आवे । माननीय नीतीश कुमार जी के दिशा निदेशन में शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 से पाठ्य पुस्तक क्रय हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों के खाते में राशि हस्तांतरित करना प्रारंभ किया गया । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,66,47,955 छात्र-छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों के खाते में राशि हस्तांतरित किया गया है । इतना ही नहीं, गत तीन वर्षों से बच्चों द्वारा उपयोग किए गए पुस्तकों को उनसे प्राप्त कर विद्यालय स्तर पर

बुक बैंक का संचालन किया जा रहा है । इससे लगभग 30 से 35 प्रतिशत बच्चों को बुक बैंक के माध्यम से भी पुस्तकें उपलब्ध हो रहा है । इस प्रकार इतने पुस्तकों की छपाई कम हो रही है, जो पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा कदम है । बिहार राज्य इस तरह का कार्य करने वाला पहला राज्य है ।

आर0टी0ई0 एक्ट के आलोक में डिटेंशन पॉलिसी का क्रियान्वयन: महोदय,बच्चों के मेधा के मूल्यांकन एवं उसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षा की योजना पर शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधान को बिहार सरकार के द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 से क्रियान्वित किया जा रहा है । इसके तहत वर्ग 5 एवं वर्ग 8 के बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन करते हुए उसके फलाफल के आधार पर आगे की कक्षाओं में नामांकन दिया जाता है । इस प्रकार का डिटेंशन पॉलिसी को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है ।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम: महोदय, हमारी सरकार बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा देने के लिए कार्य कर रही है । इस हेतु एक महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालय किया जा रहा है । इसके तहत विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा राज्य के 73,500 विद्यालयों में मनाया गया । अलग-अलग आपदाओं के विषय-वस्तु की जानकारी, क्षमतावर्द्धन एवं उस आपदा से संबंधित अभ्यास कराया गया है । बच्चों में इस कार्यक्रम से आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित हुई है तथा विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपने सुरक्षा तथा लोगों के सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हुए है । कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए गत वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक अध्ययन दल ने बिहार का दौरा किया । पुन: यह तथ्य साबित करता है कि बिहार राज्य जो आज करता है, वह दूसरे राज्य कल करते हैं ।

राजकीय बुनियादी विद्यालय का सुदृढ़ीकरण: महोदय, बिहार में बापू के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोग किया गया और उनकी प्रेरणा से बुनियादी विद्यालय की स्थापना हुई । वर्तमान में राज्य में राजकीय बुनियादी विद्यालयों की कुल संख्या-391 है । गांधीजी के चम्पारण सत्याग्रह की 150 वीं जयंती पर विभाग के द्वारा पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिला के वैसे छ: बुनियादी विद्यालयों, जहॉ बापू के कदम पड़े थे, के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ बीस लाख की राशि स्वीकृति की गई । इसके अतिरिक्त पश्चिमी चंपारण जिला के गौनहा प्रखंड के अन्तर्गत भितिहरवा बुनियादी विद्यालय संकुल के 12 विद्यालयों एव एक कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय के उन्नयन एवं बुनियादी शिक्षा

के लिए विकास प्रबंधन संस्थान द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं । इस कार्य हेतु उक्त संकुल के 20 शिक्षकों को नई तालिम पर प्रशिक्षण आनन्द निकेतन, सेवा ग्राम, वर्धा महाराष्ट्र में सम्पन्न कराया गया है । सभी विद्यालयों को आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री एवं अन्य उपकरणों को उपलब्ध कराया गया है । साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीन की उपलब्धता एवं विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना कर पुस्तकों को उपलब्ध कराया गया है । विद्यालयों में कृषि, बागवानी आदि से संबंधित उपकरणों की उपलब्धता एवं बच्चों में कृषि संबंधित ज्ञान का प्रसार कराया गया है ।

क्रमशः

टर्न-27/सत्येन्द्र-मुकुल/05-03-2020

क्रमशः

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, विभाग राजकीय बुनियादी विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र छात्राओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए चलाये जा रहे सभी तरह के लाभुक योजनाओं से उन्हें भी आच्छादित किया जा रहा है। किसी भी योजना की सफलता में उसका सतत अनुश्रवण किया जाना एक अहम कड़ी है। शिक्षा विभाग नयी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रारम्भिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं का सतत अनुश्रवण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। इस हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 के तहत जनवरी, 2020 तक 41,893 प्रारंभिक एवं 257 माध्यमिक विद्यालयों का Bihar Easy School Tracking (BEST) के माध्यम से अनुश्रवण किया गया है एवं इस अनुश्रवण से शिक्षक एवं छात्र की उपस्थिति में सुधार हुआ है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है और उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका सर्वेक्षण विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। इनमें भारत सरकार द्वारा वर्ग 3, 5 एवं 8 के बच्चों को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) एक प्रामाणिक सर्वेक्षण है, जो प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर होता है और इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के बच्चों का वर्ग 8 के सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि, वर्ग 5 में राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर एवं वर्ग 3 में राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम उपलब्धि है। भारत सरकार द्वारा वर्ग 10 के बच्चों का भी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) कराया गया। इसमें वर्ग 10 के गणित विषय में राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर एवं भाषा विषय में राष्ट्रीय औसत से थोड़ी

कम उपलब्धि है। सर्वेक्षण के माध्यम से जो कमियां इंगित होती हैं उसपर विभाग चिन्तन करके आगे की रणनीति तय करता है। मध्याह्न भोजन योजना- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस पर बच्चों को गरमागरम भोजन कराया जाना है। इस हेतु मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सभी प्रारम्भिक विद्यालयों में किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं बिहार मध्याह्न योजना समिति के द्वारा दैनिक रूप से इस योजना का अनुश्रवण आई.भी.आर.एस. माध्यम से किया जाता है। इसके तहत विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में मोबाईल से सूचना दी जाती है। इसके आधार पर वर्ग 1 से 8 तक के औसतन 1,09,96,083 (एक करोड़ नौ लाख छियानबे हजार तेरासी) छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन पोषाक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए राज्य सरकार मध्याह्न भोजन योजना, जो एक केन्द्र प्रायोजित...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: मंत्री जी, अब बहुत हो गया है। हम दो चीज जानना चाहते हैं आपसे कि पिछले वर्ष जो आपको शिक्षा का बजट मिला राशि मिली उसमें आपने कितना खर्च किया, कितना लैप्स किया आप एक ये बतला दीजिये और दूसरा जो 150वां साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हमलोग मना रहे हैं और राज्य ने मनाया तो आपने कहा भितिहरवा और फलां जगह किया और आप खुद ही बोले कि 300 कुछ जो बुनियादी विद्यालय हैं तो उन बुनियादी विद्यालयों को अप-टू-डेट करने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं यह न बतलाइए? वादा न वफा करते वादा तो किया होता, कम से कम वफा का वादा नहीं तो कम से कम वादा तो कर लीजिये।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सिद्दिकी साहब खड़े होते हैं, आपको देखते हैं और आप बैठ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि आप दोनों के बीच में ही आसन है इधर भी देख लिया कीजिये और असली बात तो आप बतला नहीं रहे हैं जो हमको बतलाये थे कि आप आज अपने जवाब में महत्वपूर्ण बात सब अंतिम 5 मिनट में बोलने वाले हैं, यह बतला दिये न इनको ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: मगर महोदय उनको इसके लिए सब्र रखने की जरूरत है इसलिए हम ..

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: चूंकि इनसे मेरा अच्छा संबंध है इस वजह से हम और वह डायरेक्ट हो जाते हैं।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: पूरी बात सुन लीजिये, सारी बातों की चर्चा इसमें की गयी है और आखिर में आपको पूरी तसल्ली हो जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के हर तबके के विकास के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण को लेकर भी सचेष्ट हैं उन्हीं की प्रेरणा से राज्य के 1097 विद्यालयों में किचन-गार्डन लगाया गया है जिससे बच्चों को ताजी सब्जी के रूप में पोषण के साथ-साथ विद्यालयों में हरित आवरण तैयार करने में भी मदद मिल रही है। सदन अवगत है कि पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर जिला ए0ई0एस0 से प्रभावित था वहां बीमारी से बच्चे प्रभावित हुए थे राज्य सरकार स्वास्थ्य महकमा पूरी मुस्तैदी से तैयार है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो । शिक्षा विभाग भी स्वास्थ्य विभाग से कदम से कदम मिलाकर इस भयानक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए मुजफ्फरपुर जिला के पांच प्रखंड यथा मीनापुर, बोचहां, मुशहरी, कांटी एवं सरैया के कुल ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप बतलाइए न कि सब्र का फल मीठा होता है।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: आपको आखिरी तक इंतजार करना होगा असली बात हम आखिरी में बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: आपको तो डिपार्टमेंट ने इस पर बोलने का अधिकार नहीं दिया इसलिए लिख कर दिया कि इसी को पढ़ना है और वही पढ़े जा रहे हैं इसलिए शिक्षा चौपट, प्राइमरी एजुकेशन चौपट, सेकेन्ड्री एजुकेशन चौपट। कुछ नहीं हमलोग अब नहीं सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इतना सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी की..

अध्यक्ष: अब जब बोल रहे हैं तो इनको जाने दीजिये न, फिर आप स्थिर से बोलियेगा।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: इतने सारे काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बहुत सारे काम हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करना चाहता हूॅ और हमलोगों के काम की सभी लोग सराहना करते हैं और मुझे अफसोस है कि ये लोग सदन से वाक-आउट कर गये। हम चाहते थे कि ये लोग मेरी पूरी बात सुन लें चूंकि आप तो जानते हैं कि असली बात हम आखिरी में बोलते हैं। महोदय..

अध्यक्ष: हम तो पूरे सदन को यह बात बतला दिये हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, हम चाहते थे कि ये आखिर तक रहते और हमारी बहुत सी बातों को सुनते लेकिन कुछ सुने नहीं और हम पे इल्जाम ए बेवफाई है। एक शेर है हम पे इल्जाम ए बेवफाई है इतना सब कुछ करने के बाद

हम पे इल्जाम ए बेवफाई है,
कमली वाले तेरी दुहाई है।

महोदय, विभिन्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में यह बात सामने आयी है कि यदि लड़कियां 10वीं/इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होती हैं तो प्रजनन दर (Total Fertility Rate) में भारी कमी आ जाती है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा सर्वेक्षणों को ध्यान में रखकर बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी पंचायतों में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय वर्ष 2013 में लिया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन में अबतक 2676 माध्यमिक विद्यालय से विहीन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का सर्वे कराया गया। इसके आधार पर उक्त 3290 उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में वर्ग-9 के संचालन हेतु इन पंचायतों में स्थित मध्य विद्यालयों को चिन्हित किया गया। 1817 पंचायतों के चिन्हित मध्य विद्यालयों में पूर्व से दो अतिरिक्त वर्गकक्ष उपलब्ध हैं। 1313 पंचायतों के चिन्हित मध्य विद्यालयों में एक अथवा दो अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जा रहा है।

क्रमशः

टर्न-28/मधुप-हेमंत/05.03.2020

..क्रमशः...

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : और 160 पंचायतों में आवश्यक भूमि एवं कमरों के अभाव के कारण दो पालियों में विद्यालय का संचालन करते हुए वर्ग-9 का संचालन किया जायेगा ।

अतिरिक्त वर्ग-कक्षों एवं अन्य सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4 अरब 25 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार राज्य के सभी 8,386 पंचायतों में अप्रैल, 2020 से वर्ग-9 का संचालन प्रारंभ करने की योजना है, जिसे उच्च माध्यमिक तक क्रमिक रूप से विस्तारित किया जायेगा ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति - महोदय, बड़ा अफसोस है कि वे नहीं सुन पायेंगे, जो उपलब्धि हमारी है, इस राज्य की उपलब्धि है, इसको जरूर उनको सुनना चाहिए था । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कादाचारमुक्त परीक्षा आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन के मामले में पूरे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है । समिति द्वारा Advanced Technological Changes के द्वारा वर्ष 2019 में देश के इतिहास में सबसे पहले मार्च महीने में ही इण्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया एवं अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया गया ।

इसी कम में छत्तीसगढ़ बोर्ड एवं पड़ोसी देश नेपाल के परीक्षा बोर्ड ने बिहार बोर्ड द्वारा रिकार्ड समय में परीक्षाफल जारी करने के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तथा बिहार आकर बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के माध्यम से किये गये बदलावों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2018 में राज्य में पहली बार Online Facilitation System for Students (OFSS) के माध्यम से इंटर कक्षा में नामांकन की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी । इस योजना से छात्रों को नामांकन के लिए अलग-अलग महाविद्यालयों में भटकने से जहाँ एक ओर निजात मिली है वहीं दूसरी ओर नामांकन के लिए आवेदन में काफी कम राशि की आवश्यकता हुई है । वर्ष 2019 में इस ऑनलाईन व्यवस्था (OFSS) के माध्यम से बिहार में इंटर कक्षा में 12 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों का ऑनलाईन नामांकन किया गया है, जो नामांकन के दृष्टिकोण से अबतक की सर्वाधिक संख्या है ।

राज्य सरकार द्वारा परीक्षा सुधारों की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में 67 वर्ष पुराने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1962, जिसके कई प्रावधान आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हो गये थे, के स्थान पर आधुनिक आवश्यकताओं एवं नई तकनीक इत्यादि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए नया "बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019" बना कर लागू किया गया है । इस नए अधिनियम के बनने के बाद समिति में कई प्रकार के नए Reforms लागू किये गए हैं, जिनसे समिति के कार्य बेहतर एवं सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं ।

महोदय, बहुत सारी बातों की चर्चा इसमें है और बिहार में जिस तरह से बिहार की सरकार ने आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में जो विकास किया है और शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया है और आगे करने की जो योजना है, उसको हू-ब-हू यहाँ पर रखने में काफी समय लग जायेगा

और वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है लिहाजा मैं अपने शेष भाषण को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाने के लिए देता हूँ ।

अध्यक्ष : एकदम ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, एक बात हमको और बतानी है जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष : आप महत्वपूर्ण चर्चा कर लीजिये, फिर जो आप सदन पटल पर रखियेगा, वह आपके भाषण का अंश बन जायेगा ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, सदन इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि वर्ष 2003 और 2005 में पंचायत शिक्षामित्रों का नियोजन 11 महीने के अनुबंध पर 1500 रुपये प्रति माह के मानदेय पर तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया था । सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले और न्याय के साथ विकास में अपनी आस्था रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार वर्ष 2005 में बनी और उन्होंने इन पंचायत शिक्षामित्रों की सुध लेते हुए इनके समायोजन और शिक्षकों के नियोजन के लिए वर्ष 2006 में नई शिक्षक नियोजन नियमावली बनाई । इस नियमावली के प्रावधान के आलोक में उस समय कार्यरत लगभग एक लाख पांच हजार पंचायत शिक्षामित्रों को 01 जुलाई, 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित करते हुए उन्हें प्रति माह 4000 (अप्रशिक्षित के लिए) एवं 5000 (प्रशिक्षित के लिए) का नियत वेतन स्वीकृत किया गया । यही नहीं इनकी सेवा को 60 वर्ष की आयु तक किया गया ।

पंचायत शिक्षकों के नियोजन के उपरांत सरकार ने अपने संसाधन को ध्यान में रखकर इनके नियत वेतन में भी वर्ष 2010 से वर्ष 2015 की अवधि में समय-समय पर एकमुश्त वृद्धि की, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन शिक्षकों को 30 जून, 2015 तक इनका वेतन 9,000 एवं 10,000 रुपये प्रति माह हो गया ।

नियोजित शिक्षकों के द्वारा वेतनमान देने की मांग लगातार की जा रही थी । वैसे इन शिक्षकों का नियोजन इनके द्वारा नियमावली में अंकित शर्तों के अधीन कार्य करने की सहमति की शर्त पर हुआ था । बावजूद इसके सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण की मांग को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया और समिति की अनुशंसा पर उन्हें 01 जुलाई, 2015 से 5200 से 20200 का वेतनमान स्वीकृत किया गया । यही नहीं नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों की भांति ही महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी गई ।

राज्य कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिस गुणक के आधार पर वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया, उसी गुणक को आधार बनाकर नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में भी 2.57 की वृद्धि अन्य राज्य कर्मियों की भांति दिनांक-01.04.2017 से प्रभावी की गई है । इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2006 में जिन पंचायत शिक्षामित्रों को 1500 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलता था, उन्हें वर्तमान में लगभग 29,000 प्रति माह से अधिक का वेतन मिलने लगा ।

नियोजित शिक्षकों के द्वारा ''समान काम के बदले समान वेतन'' विषय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न वाद भी दायर किए गए। इस मामले पर पूर्ण विराम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका 20/2018 में दिनांक-10.05.2019 को न्यायादेश पारित करते हुए किया गया ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक-10.05.2019 के न्यायादेश का अध्ययन सभी संबंधितों को करना चाहिए । माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2005-2006 से अब तक माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो-जो कार्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से किए गए, उसपर गौर करते हुए उसकी सराहना की गई । साथ ही, माननीय न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के ''समान काम के बदले समान वेतन'' की मांग को नहीं मानते हुए यह आदेश की कंडिका-79 में स्पष्ट किया कि नियोजित शिक्षकों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं किया गया और न ही उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया गया है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश वस्तुतः सरकारों के लिए नियमन है और सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं । इस प्रकार नियोजित शिक्षक भी इस आदेश से बंधे हुए हैं । बावजूद इसके इनकी मांगों को यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो यह ज्ञात होगा कि अधिकांश शिक्षक संघ की पहली मांग ''समान काम के बदले समान वेतन'' ही है । ऐसे में यह हड़ताल उस विषय पर है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया है।

राज्य सरकार शिक्षकों की हितैषी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सार्वजनिक मंच से एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद पर सरकार का उत्तर देते हुए बिहार विधान परिषद् में पुनः यह दोहराया कि सरकार अपनी हैसियत के हिसाब से पहले भी वेतन में वृद्धि की गयी है और आगे भी करेगी ।

शिक्षकों की हड़ताल का समय भी देखिए । यह हड़ताल मैट्रिक एवं इण्टर की परीक्षा को बाधित करने के साथ-साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने के

उद्‌देश्य से भी की गयी, प्रतीत होता है । इससे छात्रों के भविष्य पर नियोजित शिक्षकों की संवेदनशीलता क्या है, यह भी स्पष्ट होता है ।

महोदय, 2005 के पहले भी इन्होंने हड़ताल की थी और वह काफी समय तक चली थी । मुझे एक छोटी-सी घटना याद आती है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी गुजर रहे थे हड़तालियों के करीब से, तो हड़तालियों ने नारा लगाया - लालू यादव मुर्दाबाद, तो उन्होंने गाड़ी रोककर कहा था कि वेतन मिलेगा फगुआ बाद, होली के बाद । हम ऐसे नहीं हैं ।

महोदय, हम सचमुच में शिक्षकों के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते हैं और हम यह चाहते हैं कि यह हड़ताल उनको ऐसे समय में नहीं करनी चाहिए थी और बातचीत के माध्यम से ही बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान होता रहा है ।

...क्रमशः...

टर्न-29/आजाद/05.03.2020

...... क्रमशः .....

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : इसलिए हम उनके प्रति जो हमारा नरम रुख है, हमने उसकी चर्चा कर दी है और हड़ताल पर जाने की सूचना से पहले हमारे द्वारा अपील किया जा रहा है और आज भी मैं सदन के माध्यम से सभी शिक्षकों से अपील करता हूँ कि वे विद्यालयों में योगदान कर बच्चों को मन से पढ़ायें और राज्य सरकार अपनी हैसियत के अनुसार उनके वेतन में वृद्धि करेगी और वर्तमान सेवा शर्त्तों में सुधार करेगी । मुझे आशा है कि उनके प्रति जो हमलोगों के मन में भाव है, चूँकि हमलोग समझते हैं कि ये हमारे शिक्षक हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खड़े किये गये शिक्षक हैं और हमलोगों का उनके प्रति हमेशा अच्छा भाव रहा है, हमेशा हमलोगों ने इनके कष्टों को, तकलीफों को दूर करने के लिए भी सोचा है, इसलिए इनको कठोर न लेकर के वर्तमान परिस्थितियों को कॉपी जॉंच हो रही है, परिक्षायें हुईं, सबको बाधित किया, इसपर गौर करते हुए अपने निर्णय पर विचार करें ये और सरकार इनके विरोधी नहीं हैं । हमलोग इनके कभी विरोधी नहीं हैं, इनको तो हमलोगों ने खड़ा किया, ये तो हमारे शिक्षक हैं, यह बात हमेशा कहते रहे हैं । इसलिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम उनसे अपील करते हैं कि वे अपने निर्णय पर सोचें और हड़ताल को समाप्त करें ।

साथ ही मैं माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इसे वापस ले लें और इसे प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जो अपना लिखित वक्तव्य अपने सदन पटल पर रख रहे हैं, वह इनके भाषण का एवं कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे । सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

(माननीय मंत्री के भाषण का लिखित अंश –परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अब मैं कटौती प्रस्ताव को लेता हूँ । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 351,91,04,56,000/- (तीन सौ इक्यावन अरब इक्यानवे करोड़ चार लाख छप्पन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण । अब विधायी कार्य ।

(इस अवसर पर विपक्ष के मा0 सदस्यगण सदन में आ गये)

राजकीय विधेयक

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन)विधेयक, 2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन)विधेयक, 2020 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन)विधेयक, 2020 को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन)विधेयक, 2020 पर विचार हो । "

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन(संशोधन) विधेयक, 2020 के सिद्धांत पर विमर्श हो । "

अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: आपने देखा होगा कि मैं कभी भी संशोधन विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का कोई प्रस्ताव नहीं करता हूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जो विधेयक इस सदन में पारित करके कानून बनता है उसमें संशोधन लाये जाने पर उसके सिद्धांत पर विमर्श का कोई औचित्य नहीं है लेकिन यह संशोधन विधेयक मेरी समझ से सिद्धांत पर विमर्श के लायक है । अभी माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2020 को लम्बा वक्तव्य बजट प्रबंधन पर दिया गया है । ऋण प्रबंधन का भी बजट में उल्लेख है, परंतु आनन-फानन में आया यह विधेयक उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है ।

महोदय, आप अवगत हैं कि राजकीय विधेयक के लिए दिनांक- 26 एवं 30 मार्च की तिथि निर्धारित है । अचानक ऐसी कौन सी हड़बड़ी आ गई जिसके लिए आज इस पर विमर्श कर निर्णय लिया जाना आवश्यक हो गया है ।

महोदय, इसके उद्देश्य एवं हेतु में उल्लेख है कि अतिरिक्त ऋण सुविधा 5688 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकती है अगर अधिनियम में संशोधन कर दिया जाय । ऋण लेने का कोई औचित्य होना चाहिये और उसे अनुत्पादक कामों में खर्च तो किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिये । इसीलिए मैंने इसके सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन(संशोधन) विधेयक, 2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

महोदय, इस संशोधन में राज्य सरकार को भारत सरकार के सामने एक तरह से घुटना टेक देने वाली बात है । महोदय, इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य में ही उल्लिखित है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य को हस्तांतरित किए जाने वाले राजस्व में कमी की भरपाई के लिए यह ऋण लेने की सीमा बढ़ायी गयी, जो बिहार जैसे बीमारू राज्य के लिए सही नहीं है महोदय । महोदय, राज्य सरकार को राज्य में हस्तांतरित होने वाले राजस्व में बढ़ोत्तरी की मांग करनी चाहिए, ऋण की सीमा को बढ़ाने की मांग की जानी चाहिए महोदय । महोदय उल्लेखनीय है कि 2005 में प्रति व्यक्ति, महोदय इस राज्य के जनता पर 5 हजार से कम था ऋण, आज महोदय 2019 तक राज्य सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन के चलते प्रति व्यक्ति 1 लाख 32 हजार लगभग हो गया है महोदय । इस विधेयक संशोधन होने से राज्य की आम जनता पर कार्य बढ़ेगा महोदय, यह सही नहीं है महोदय । महोदय, राज्य की स्थिति हर मानक पर 2005 की जगह पर है, उससे कहीं बढ़ोत्तरी नहीं हुई है महोदय । जबकि प्रति व्यक्ति ऋण में राज्य की वित्तीय कुव्यवस्था, सृजन घोटाला समेत 55 घोटाले के चलते बढ़ोत्तरी हुई है । महोदय, जब सरकार ऋण लेकर विकास की बात करता है तो विकास के सभी मानक आज बिहार में 2005 की तरह है महोदय तो विकास एक गंभीर अनियमितता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । हम इस संशोधन विधेयक को आज पास न करके

इसे जनमत जानने के लिए महोदय हम आग्रह करेंगे कि जनमत जानने की इसकी अनुमति दी जाए, महोदय हम लोग एक कहावत स्कूल में सुनते थे -

यावत् जिवेत् , सुखम जिवेत,
ऋणम कृत्वा, घृतम पिवेत ।

यानी कर्जा लेकर ही सरकार घी पीने के लिए कर्जा लेकर ही सरकार ये काम करना चाहती है, मुबारक हो महोदय ऐसे विधेयक का हमलोग विरोध करते हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020 दिनांक, 31 मार्च, 2020 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-30/शंभु-धिरेन्द्र/05.03.2020

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब प्रवर समिति का प्रस्ताव । इसमें माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020'' को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे ।''

महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव इसलिए दिया, क्योंकि यह विधेयक एक दिन के अंदर जल्दबाजी में आया है । ऋण लेना कोई गौरव का विषय नहीं होता, यह अत्यंत जरूरत होने पर और पूरे आकलन के बाद ही लिया जाना चाहिए । केन्द्र सरकार ने अनुमति दी और आनन-फानन में उतने ही राशि का संशोधन आप ले आये हैं । मेरा अनुरोध है कि आप ऋण ले, लेकिन उसका अच्छे तरीके से आकलन कर ले कि कितनी जरूरत है और क्यों है । इसे प्रवर समिति में विचार-विमर्श हेतु भेजा जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ खण्ड 2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी हॉं, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खण्ड-2 के प्रस्तावित संशोधन के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाए:-

''परन्तु यह कि प्रस्तावित ऋण अधिसीमा में कोई बढ़ोतरी भविष्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि पुराने ऋण और उसके सूद को चुका न दिया जाएगा ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया कि ऋण लेने की सीमा लगातार सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही है । पहले जी0डी0पी का 3 प्रतिशत था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2016-17, वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत तक कर दिया गया । महोदय, आज इस राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के जन्म के साथ-साथ वह 15 हजार कर्ज उसके माथे पर आ जाता है । दुनिया जानता है इसलिए कर्ज की प्रवृत्ति पर रोक लगायी जाए और सबसे पहले सरकार का प्रयास हो कि लिये गये कर्ज एवं सूद की वापसी करे, ताकि यहॉं के नागरिक कर्ज मुक्त हो सकें । अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर 15 साल पहले एक-तिहाई था जो 15 हजार से ज्यादा, जो बच्चा जन्म लेता है उसके माथे पर ये कर्ज आ जाता है । इसलिए अति-आवश्यक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खण्ड-2 के प्रस्तावित संशोधन के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''परन्तु यह कि प्रस्तावित ऋण अधिसीमा में कोई बढ़ोत्तरी भविष्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि पुराने ऋण और उसके सूद को चुका न दिया जायेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि :

''खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है इस बात का कि कार्य-मंत्रणा समिति में सभी दलों के लोग हैं और वहॉ पर सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस बिल को पारित कराना है और आश्चर्य की बात नेता प्रतिपक्ष भी थे, सिद्दिकी साहब भी थे और आज यहॉ पर या तो सिद्दिकी साहब अपने सदस्यों को पूरी जानकारी नहीं

देते हैं और यहाँ पर ये उसका विरोध कर रहे हैं । कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो । यह तो एक ऐसा दायित्व है कि जिसका निर्वाह और ललित बाबू आप किस कमिटी के चेयरमैन है प्राक्कलन समिति । जो भी समिति के आप, वित्तीय समिति के चेयरमैन है । अध्यक्ष महोदय, केन्द्र या राज्य उसके आमदनी का 4 स्रोत है । राज्यों का पहला स्रोत है केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा, ये इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये जो एक्साइज, ये जो कर संग्रह होता है इसमें राज्यों का बंटवारा होता है कि राज्यों को कितना मिलेगा, वो एक आय का बड़ा स्रोत है और वित्त आयोग ..... अरे सुन लीजिए न, कुछ तो सुन लीजिए.... सुन लीजिए न बात .... तो केन्द्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो आमदनी का एक बड़ा स्रोत है । दूसरा है केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जो अनुदान मिलता है, वो चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आवास हो, जितनी भी केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्य का अंश और केन्द्र का अंश है । वो दूसरा हिस्सा हो, आपको अनुदान के रूप में मिलता है । तीसरा है राज्य का अपना राजस्व, ये ट्रांसपोर्ट, निबंधन, वाणिज्य कर, ये तीसरा स्रोत है और चौथा स्रोत है राज्य का कर्ज और जो कर्ज है अध्यक्ष महोदय, ये कोई राज्य मनमाने तरीके से नहीं ले सकता है । ललित बाबू सुन लीजिए, कोई राज्य सरकार चाहेगी भी अगर कर्ज लेना तो जमाना चला गया कि ''ऋणम् कृत्वा, घृतम् पिवेत'' कि कर्जा लेकर घी पीयो और चुकाने का नाम नहीं है । अब अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि कोई राज्य कितना भी कर्ज ले सकता है, वो निर्धारित है, उससे ज्यादा कर्जा आप ले ही नहीं सकते है और ये जो कर्ज कितना लेना है, यह हम लोगों ने कानून बना दिया, एफ0आर0बी0 में ये जो बिहार राजकोषीय और उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम है । ये हम ही लोगों ने कानून बनाया और किसके कहने पर कानून बनाया, तो वित्त आयोग के कहने पर हम लोगों ने कानून बनाया और कितना कर्ज ले सकते हैं । आप एक साल के अंदर जो जी0एस0डी0पी है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 3 परसेंट से ज्यादा आप नहीं ले सकते है । बाद में उसको केन्द्र ने बढ़ाकर उसको 3.5 प्रतिशत कर दिया । तो अगर आपका जी0एस0डी0पी0, जितना है और वह भी निर्धारित केन्द्र की सरकार करती है कि हर राज्य का इस साल सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा । एक आकलन करती है और उसका 3 प्रतिशत ही केवल आप कर्ज ले सकते हैं । चाह कर भी 4 नहीं ले सकते है, 5 नहीं ले सकते हैं बाद में वित्त आयोग की अनुशंसा पर इसको बढ़ा कर 3.5 प्रतिशत किया गया । इसलिए ये आप अपने से नहीं कर सकते, वित्त

आयोग ने कहा राज्यों को कि अगर आपका वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा तो आप 3 की तुलना में आप 3.5.........सुन लीजिए ललित बाबू ....

क्रमशः

टर्न-31/05-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री सुशील कुमार मोदी, उपमुख्यमंत्री : तो आप तीन की तुलना में, सुन लीजिए ललित बाबू, कि वित्त आयोग ने अनुशंसा किया कि जिन राज्यों का बेहतर वित्तीय प्रबंधन होगा उनको ज्यादा कर्ज लेने की अनुमति प्रदान करेंगे और इतना ही नहीं सभापति मैं यह भी बताना चाहूँगा और अगर 2004-2005 की बात हो रही थी तो जब 2005-2006 में जब हम लोगों की सरकार बनी तो उस समय जो जी0एस0डी0पी0 था सकल, घरेलू, उत्पाद उसकी तुलना में 60 प्रतिशत का कर्ज था । अगर 100 रूपये था जी0एस0डी0पी0 तो 60 रूपये कर्ज था और आज हम लोगों ने घटाकर जी0एस0डी0पी0 का केवल 25 प्रतिशत पर पहुँचा दिया । हम लोगों ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया, जिसका परिणाम 60 प्रतिशत से घटकर और यह 25 प्रतिशत तक आ गया है और आगे आने वाले दिनों में और इसको घटाकर और 15 प्रतिशत से नीचे लाने का काम करेंगे और सभापति महोदय, और अभी जो... (व्यवधान)

समीर महासेठ जी, अगर बजट की किताब में सब लिखा हुआ है, आप अगर पहले बजट की किताब पढ़ लेते तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती और सभापति महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पूरे देश के सभी राज्यों को और 58 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति प्रदान की, केवल बिहार ही नहीं है, केरल भी है, बंगाल भी है, यू.पी. भी है, केंद्र शासित कोई राज्य हो 2019-2020 में 58,843 करोड़ रुपया राज्यों को अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति प्रदान की भारत सरकार ने और इसलिए जो साढ़े 3 प्रतिशत की जो सीमा है उसके ऊपर राज्य अगर चाहे तो कर्ज ले सकते हैं और बिहार को भी 5,688 करोड़ रुपया अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति केन्द्र ने प्रदान की है और शर्त है कि आप एफ0आर0बी0एम एक्ट में उसके अनुरूप संशोधन कर दीजिए और आपने पूछा जल्दी क्या है, तो जल्दबाजी इसलिए है कि केवल 6 दिन पहले केन्द्र की सरकार ने राज्यों को अनुमति प्रदान की है और 31 मार्च से पहले ही कर्ज लेना है और केवल कर्ज ही नहीं लेना कर्ज लेकर उसका खर्च भी करना है और इसलिए हम लोग आज यह संशोधन विधेयक लाये ताकि पारित होने के बाद विधान परिषद् से पारित हो जाए,

राज्यपाल की सहमति मिल जाए और हम 9 तारीख को 2 हजार करोड़ रुपये की जो मार्किट बौरोइंग है ये पहली किस्त लेंगे और अगले 21 दिनों में बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो हम लेने का काम करेंगे और एक बात और मैं बता दूँ सदस्यों को कि हम जो भी कर्ज ले रहे हैं वो पैसा वेतन पर खर्च नहीं होगा, वो पैसा पेंशन पर खर्च नहीं होगा, हम जो भी कर्ज लेते हैं वो निर्माण कार्यों पर खर्च होता है, केवल पुल-पुलियाँ, बिजली, आधारभूत संरचना के निर्माण पर खर्च होता था और एक जमाना था जब आप कर्ज लेते थे- वेतन, पेंशन का भुगतान करने के लिए । हम लोगों ने बिहार को उस वित्तीय अराजकता से निकालकर आज यहाँ पर पहुँचाया है और इसलिए कर्ज लेना यह कोई गुनाह नहीं है देश के सभी राज्य लेते हैं । बंगाल और केरल ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया तो उस जमाने में 2005 में और इतना ज्यादा कर्ज ले लिया और क्योंकि हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया, हमारी सरकार ने तो जिसको रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट कहते हैं इस साल केरल को 15 हजार करोड़ रुपया रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगा जो वामपंथी राज्य है जो अपने आपको प्रगतिशील राज्य कहता है और क्यूँकि हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया और हम रेवन्यू-सर-प्लस है और इसलिए हमको रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगा, लेकिन केरल को मिलेगा 15 हजार करोड़, बंगाल को मिलेगा क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि वित्त आयोग ने कहा कि अगर इनकी मद्द नहीं करेंगे तो इनका तो दिवाला निकल जाएगा और हमने बेहतर किया तो हमको नुकसान हो गया और उन्होंने इतना ज्यादा कर्ज लें लिया कि ब्याज का भुगतान और मूलधन वापस करते-करते उनके पास पैसा नहीं बचा । इसलिए वित्त आयोग ने उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने का काम किया इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि यह राज्य हित का यह बिल है इसलिए भली आपने इसका ओर विरोध कर दिया होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि सर्वसम्मिति से यह बिल पारित किया जाना चाहिए ताकि हम आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा विकास का कार्य कर सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

मान्नीय सदस्यगण, आज दिनांक 5 मार्च, 2020 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 29 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न के लिए स्थगित की जाती है ।

माननीय मंत्री के भाषण का अंश परिशिष्ट

बिहार में शिक्षा की उन्नति के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नैतिक बल और चरित्र, शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा के मामले में बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। वर्ष 2005 से माननीय श्री नीतीश कुमार के द्वारा गौरवशाली इतिहास को पुनः प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास किये गए है। इस हेतु बिहार के चतुर्दिक विकास में शिक्षा को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। वर्ष 2005 से शिक्षा का बजट प्रतिवर्ष बिहार सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। फलतः बिहार सरकार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार सभी वर्गो के लिए ख़ासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों–बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिएं अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। सरकार की योजना में कोई भेद–भाव नही किया जाता है और सभी वर्गों एवं धर्मो के मानने वालो को अपने क्षमता के विकास का पर्याप्त औसर दिया जा रहा है। इसमें हमें सफलता भी मिली है। मैं सिलसिलेवार ढ़ंग से सदन के समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो को रखता हूँ।

प्राथमिक शिक्षा :	
1. 6–14 आयुवर्गो के बच्चों को विद्यालय से अच्छादित करना।	–6–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र–सापेक्ष दक्षता देकर शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में राज्य ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2005–06 में सर्वे कराया गया था कि कितने बच्चे विद्यालय से बाहर है तो पता चला कि 12.5प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर है। इसमें सबसे अधिक बच्चे या तो अल्पसंख्यक समाज के थे या महादलित वर्ग के थे। उनको स्कूल पहुँचाने के लिए 30,000 (तीस हजार) उत्थान केन्द्र और तालिमी मरकज खोले गये। उत्थान केन्द्र टोला सेवक के द्वारा तथा तालिमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवी के माध्यम से संचालित किये गये ताकि बच्चे स्कूल जाये। इसका एवं अन्य योजनाओं का सुपरिणाम यह है कि अब विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों की

	संख्या 1% से भी कम रह गया है। सरकार इन बच्चों को भी विद्यालय से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है और हमें विश्वास है उन्हें भी जल्द से जल्द विद्यालय से जोड़ दिया जायेगा।
2. प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना।	– सभी बसावक्षेत्र के एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय एवं तीन किलोमीटर की परिधि में मध्य विद्यालय सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005–06 से अब तक एक्कीस हजार दो सौ चौसठ नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए, उन्नीस हजार छः सौ पच्चीस प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। यही नहीं सोलह हजार एक सौ पैतालीस नए प्राथमिक विद्यालय भवन और दो लाख सत्तहतर हजार चार सौ तीन अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण पूर्व से अवस्थित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में किया गया है। राज्य सरकार की संजिदगी इससे भी छलकती है कि भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नए प्राथमिक विद्यालय के भवन के निर्माण हेतु राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण नौ सौ सैतालिस नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य योजना से एक अरब एकानवे करोड़ उन्नतालिस लाख चौरासी हजार चार सौ अरतीस रूपये की स्वीकृति दिनांक 27.02.2020 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई।

3. पुस्तक क्रय हेतु राशि का स्थानांतरण	– बिहार राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पुस्तक की आपूर्ति की जाती है। यह परम्परा बिहार में भी थी। इससे बच्चों तक पुस्तक पहुचने में काफी विलम्ब होता था और माह अक्टूबर नवम्बर तक बच्चों को पुस्तक मिल पाता था। माननीय नीतीश कुमार ने इस समस्या पर गम्भीर चिन्तन करते हुए यह निर्णय लिया कि छात्र को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होते ही पुस्तक क्रय हेतु राशि उपलब्ध हो जाए ताकि बच्चों को पुस्तकों के अभाव में शिक्षा में रूचि की कमी नहीं आवे। माननीय नीतीश कुमार जी के दिशा निदेशन में शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2018–19 से पाठ्यपुस्तक क्रय हेतु Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से कक्षा 1 से 8 छात्र–छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों के खाते में राशि हस्तांतरित करना प्रारम्भ किया गया। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 1,66,47,995 छात्र–छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों के खाते में राशि हस्तांतरित किया गया है। इतना ही नहीं, गत तीन वर्षों से बच्चों द्वारा उपयोग किए गए पुस्तकों को उनसे प्राप्त कर विद्यालय स्तर पर बुक बैंक का संचालन किया जा रहा है। इससे लगभग 30 से 35 प्रतिशत को बच्चों को बुक बैंक के माध्यम से भी पुस्तकें उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार इतने पुस्तकों की छपाई कम हो रही है जो पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा कदम है। बिहार राज्य इस तरह का कार्य करनेवाला पहला राज्य है।

4. आर.टी.ई. एक्ट के आलोक में Detention Policy का क्रियान्वयन।	–बच्चों के मेधा के मूल्याकंन एवं उसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षा की योजना पर शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधान को बिहार सरकार के द्वारा शैक्षिक सत्र 2018–19 से क्रियान्वित किया जा रहा है । इसके तहत वर्ग V एवं वर्ग VIII के बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन करते हुए उसके फलाफल के आधार पर आगे की कक्षाओं में नामांकन दिया जाता है। इस प्रकार का Detention Policy को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है।
5 मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	– हमारी सरकार बच्चों को सुरक्षित वातावरण मे शिक्षा देने के लिए कार्य कर रही है। इस हेतु एक महत्वकाक्षी योजना–मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा राज्य के 73500 विद्यालयों में मनाया गया। अलग–अलग आपदाओं के विषय–वस्तु की जानकारी, क्षमतावर्द्धन एवं उस आपदा से संबंधित अभ्यास कराया गया है। बच्चों में इस कार्यक्रम से आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित हुई है तथा विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपने सुरक्षा तथा लोगों के सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हुए है। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए गत वर्ष छतीसगढ़ राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक अध्ययन दल ने बिहार का दौरा किया। पुनः यह तथ्य साबित करता है कि बिहार राज्य जो

	आज करता है वह दूसरे राज्य कल करते हैं।
6. राजकीय बुनियादी विद्यालय का सुदृढीकरण ।	–बिहार में बापू के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोग किया गया और उनकी प्रेरणा से बुनियादी विद्यालय की स्थापना हुई। वर्तमान में राज्य में राजकीय बुनियादी विद्यालयों की कुल संख्या–391 है। गांधीजी के चम्पारण सत्याग्रह की 150 वीं जयंती पर विभाग के द्वारा पश्चिम चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिला के वैसे छः बुनियादी विद्यालयों, जहाँ बापू के कदम पड़े थे, के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ बीस लाख की राशि स्वीकृति की गई। इसके अतिरिक्त पश्चिम चंपारण जिला के गौनहा प्रखंड के अन्तर्गत भितिहरवा बुनियादी विद्यालय संकुल के 12 विद्यालयों एवं एक कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के उन्नयन एवं बुनियादी शिक्षा के लिए विकास प्रबंधन संस्थान द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे है। इस कार्य हेतु उक्त संकुल के 20 शिक्षकों को नई तालिम पर प्रशिक्षण आनन्द निकेतन, सेवा ग्राम, वर्धा महाराष्ट्र में सम्पन्न कराया गया है। सभी विद्यालयों को आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री एवं अन्य उपकरणों को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीन की उपलब्धता एव विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना कर पुस्तकों को उपलब्ध कराया गया है। विद्यालयों में कृषि, बागवानी आदि से संबंधित उपकरणों की उपलब्धता एवं बच्चों में कृषि संबंधित ज्ञान का प्रसार कराया गया है।

	विभाग राजकीय बुनियादी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए चलाये जा रहे सभी तरह के लाभुक योजनाओं से उन्हें भी आच्छादित किया जा रहा है।
7. बेस्ट एप के माध्यम से अनुश्रवण।	– किसी भी योजना की सफलता में उसका सतत् अनुश्रवण किया जाना एक अहम कड़ी है। शिक्षा विभाग नयी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रारम्भिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं का सतत् अनुश्रवण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम् से करता है। इस हेतु शैक्षिक सत्र 2019–20 के तहत जनवरी, 2020 तक 41,893 प्रारंभिक एवं 257 माध्यमिक विद्यालयों का Bihar Easy School Tracking (BEST) के माध्यम से अनुश्रवण किया गया है एवं इस अनुश्रवण से शिक्षक एवं छात्र की उपस्थिति में सुधार हुआ है।
8. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण।	– सरकारी विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है और उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पर रहा है, इसका सर्वेक्षण विभिन्न ऐजेसियों के द्वारा किया जाता है। इनमें भारत सरकार द्वारा वर्ग 3, 5 एवं 8 के बच्चों का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) एक प्रमाणिक सर्वेक्षण हैं, जो प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर होता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के बच्चों का वर्ग 8 के सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि, वर्ग 5 में राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर एव वर्ग 3 में

	राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम उपलब्धि है । भारत सरकार द्वारा वर्ग 10 के बच्चों का भी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) कराया गया। इसमें वर्ग 10 के गणित विषय में राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय में राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर एव भाषा विषय में राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम उपलब्धि है । सर्वेक्षण के माध्यम से जो कमियाँ इंगित होती है उसपर विभाग चिन्तन करके आगे की रणनीति तय करता है।
9. मध्याह्न भोजन योजना।	– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस पर बच्चों को गरमागरम भोजन कराया जाना है। इस हेतु मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सभी प्रारम्भिक विद्यालयों में किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं बिहार मध्याह्न योजना समिति के द्वारा दैनिक रूप से इस योजना का अनुश्रवण आई.भी.आर.एस. माध्यम से किया जाता है। इसके तहत विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा मध्याहन भोजन योजना के संबंध में मोबाईल से सूचना दी जाती है। इसके आधार पर वर्ग 1 से 8 तक के औसतन 1,09,96,083 (एक करोड़ नौ लाख छियानबे हजार तेरासी) छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हम सभी जानते है कि एक स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए राज्य सरकार मध्याहन भोजन योजना, जो एक केन्द्र प्रायोजित

	योजना है, में राज्य सरकार के योजना मद से बच्चों को सप्ताह में एक दिन अंडा दिया जा रहा है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते है उन्हें मौसमी फल दिया जाता है। इस योजना पर राज्य सरकार दो सौ चौसठ करोड़ रूपये का व्यय कर रही है। यही नही हमलोग रसोईयॉ–सह–सहायक के मानदेय में वृद्धि के लिए भी संवेदशील है। जहाँ केन्द्र सरकार के द्वारा रसोईयॉ–सह–सहायक को मानदेय के लिए एक हजार की राशि स्वीकृत है वहीं बिहार में इन्हें 1500 रूपये प्रति माह दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार योजना बनाकर अपनी निधि से प्रति रसोईयॉ–सह–सहायक को पाँच सौ रूपये अलग से दे रही है। सरकार इस मद में एक सौ पन्द्रह करोड़ रूपये व्यय कर रही है। माननीय मुख्यमंत्रीजी समाज के हर तबके के विकास के साथ–साथ पर्यावरण के संरक्षण को लेकर भी सचेष्ट है। उन्हीं की प्रेरणा से राज्य के 10,097 विद्यालयों में किचेन गार्डेन लगाया गया है। इससे बच्चों को ताजा सब्जी के रूप में अतिरिक्त पोषण के साथ–साथ विद्यालय में हरित आवरण तैयार करने में भी मद्द मिल रहा है। सदन अवगत है कि पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर जिला ए.ई.एस. से प्रभावित था। इस बीमारी से बच्चे प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार स्वास्थ्य महकमा पूरी मुस्तैदी से तैयार है कि इसकी पुनरावृत्ति नही हो। शिक्षा विभाग भी स्वास्थ्य विभाग से कदम से कदम मिलाकर इस भयानक बीमारी से लरने के लिए तैयार है। इसके लिए

	मुजफ्फरपुर जिला के पाँच प्रखंड यथा–मीनापुर, बोचहाँ, मुशहरी, काँटी एवं सरैया के कुल 1053 विद्यालयों में दिनांक 01 फरवरी, 2020 से सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को प्रति छात्र–छात्रा 150MLदुध उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसे कुल 1,69703 छात्र–छात्रा लाभान्वित हो रहे है।
माध्यमिक शिक्षा :	
1. सभी छुटे हुए पंचायतों में अप्रैल, 2020 से वर्ग–09 की पढ़ाई शुरू किया जाना।	– विभिन्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि यदि लड़कियाँ 10वीं / इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होती हैं तो प्रजनन दर (Total Fertility Rate) में भारी कमी आ जाती है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा सर्वेक्षणों को ध्यान में रखकर बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी पंचायतों में एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय वर्ष 2013 में लिया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन में अबतक 2676 माध्यमिक विद्यालय से विहीन पंचायतों में चिन्हित मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का सर्वे कराया गया। इसके आधार पर उक्त 3290 उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में वर्ग–9 के संचालन हेतु इन पंचायतों में स्थित मध्य विद्यालयों को चिन्हित किया गया। 1817 पंचायतों के चिन्हित मध्य विद्यालयों में पूर्व से दो अतिरिक्त वर्गकक्ष उपलब्ध हैं। 1313 पंचायतों के चिन्हित मध्य विद्यालयों

	में एक अथवा दो अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जा रहा है और 160 पंचायतों में आवश्यक भूमि एवं कमरों के अभाव के कारण दो पालियों में विद्यालय का संचालन करते हुए वर्ग–9 का संचालन किया जायेगा। अतिरिक्त वर्ग–कक्षों एवं अन्य सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्श में ₹4,25,00,000/– (चार अरब पचीस करोड़) रूपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार राज्य के सभी 8386 पंचायतों में अप्रैल 2020 से वर्ग–9 का संचालन प्रारंभ करने की योजना है, जिसे उच्च माध्यमिक तक क्रमिक रूप से विस्तारित किया जायेगा।
2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।	– बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कदाचारमुक्त परीक्षा आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन के मामले में पूरे देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। समिति द्वारा Advanced Technological Changes के द्वारा वर्ष 2019 में देश के इतिहास में सबसे पहले मार्च महीने में ही इंटर का रिजल्ट घोषित किया गया एवं अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बोर्ड एवं पड़ोसी देश नेपाल के परीक्षा बोर्ड ने बिहार बोर्ड द्वारा रिकार्ड समय में परीक्षाफल जारी करने के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तथा बिहार आकर बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के माध्यम से किये गये बदलावों

	के बारे में जानकारी भी प्राप्त किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2018 में राज्य में पहली बार Online Facilitation System for Students (OFSS) के माध्यम से इंटर कक्षा में नामांकन की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। इस योजना से छात्रों को नामांकन के लिए अलग–अलग महाविद्यालयें में भटकने से जहाँ एक ओर निजात मिला है वहीं दूसरी ओर नामांकन के लिए आवेदन मे काफी कम राशि की आवश्यकता हुई है। वर्ष 2019 में इस ऑनलाईन व्यवस्था (OFSS) के माध्यम से बिहार में इंटर कक्षा में 12 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों का ऑनलाईन नामांकन किया गया है, जो नामांकन के दृष्टिकोण से अबतक की सर्वाधिक संख्या है। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा सुधारों की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में 67 वर्ष पुराने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952, जिसके कई प्रावधान आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हो गये थे, के स्थान पर आधुनिक आवश्यकताओं एवं नई तकनीक इत्यादि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए नया "बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019" बना कर लागू किया गया है। इस नए अधिनियम के बनने के बाद समिति में कई प्रकार के नए Reforms लागू किये गए हैं, जिनसे समिति के कार्य बेहतर एवं सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार के

	सभी 09 प्रमण्डलीय मुख्यालयों यथा– पटना, मुंगेर, गया, पूर्णियाँ, सहरसा, छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से समिति के परीक्षा भवनों–सह–क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कराया गया है, जिसमें एक साथ लगभग 4 से 5 हजार परीक्षार्थी सी.सी.टी.वी. की निगरानी में परीक्षा दे सकेंगे। इन सभी परीक्षा भवनों की यह भी विशेषता है कि इसमें आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं की सभी गतिविधियों की Live Monitoring संबंधित जिले के डी० एम० कंट्रोल रूम एवं बिहार बोर्ड के कंट्रोल रूम द्वारा वेबकास्टिंग (Webcasting) के माध्यम से किया जाएगा। यही नहीं, पटना में पचीस हजार परीक्षार्थियों को एक साथ परीक्षा लेने हेतु परीक्षा भवन का निर्माण किया जा रहा है।
3. उन्नयन बिहार कार्यक्रम।	– उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांका जिला में उन्नयन बांका कार्यक्रम चलाया गया। इसके अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के लिए स्मार्ट वर्गकक्ष स्थापित कर छात्र/छात्राओं को पढ़ाया गया। स्मार्ट वर्गकक्ष में एक बड़ा TV Screen रहता है, जिसमें विकसित E-Content के माध्यम से दिखाकर अध्यापन कार्य किया जाता है। यह बच्चों के सीखने के लिए सुविधाजनक एवं प्रभावी माध्यम है। बांका जिला में इस योजना को अपार सफलता मिली। यह गणित,

	सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के लिए संचालित किया गया। वहाँ पर बच्चों के उपस्थिति एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता के प्रतिशत में सराहनीय वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा उन्नयन बांका योजना का स्वयं अवलोकन बांका जाकर किया गया और उन्होंने निदेश दिया कि गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के साथ–साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में ई–कंटेन्ट तैयार कर इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में किया जाए। इसके अनुपालन में यह निर्णय लिया गया कि स्मार्ट वर्गकक्ष की सुविधा सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के उक्त पॉचों विषयों के लिए उपलब्ध करायी जाय। इस हेतु विभाग के द्वारा 90,000/– (नब्बे हजार) प्रति विद्यालय की दर से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट वर्गकक्ष स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध कराया गया। 5 सितम्बर, 2019 को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के लिए उक्त पॉच विषयों में E-Content के माध्यम से अध्यापन हेतु उन्नयन योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना से वर्तमान में संचालित सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय को अच्छादित किया गया है। साथ ही, अप्रैल 2020 से माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्ग 09 के संचालन के क्रम में भी उन सभी विद्यालयों में भी उन्नयन योजना को लागू करने की योजना है।

4. बालिका शिक्षा पर जोर।	–माननीय मुख्यमंत्रीजी को जनता ने सेवा करने का जबसे अवसर दिया उसी दिन से वे बालिका शिक्षा के लिए सजग एवं चिन्तित रहे। उनके सफल नेतृत्व में बालिका शिक्षा के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएँ यथा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यकम (सैनिटरी नैपकिन) आदि प्रारम्भ हुई। वर्तमान में समेकित रूप से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संचालित है, जो बालिका के जन्म से लेकर स्नातक होने तक बालिकाओं के लिए चलाए जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि वर्ग एक से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी कोटि एवं वर्गों के छात्राओं को आज पोशाक योजना से आच्छादित है। बालिकाएँ आत्मनिर्भर हो रही है। मैट्रिक में आज छात्र/छात्राओं की संख्या लगभग बराबर हो गई है। इससे समाज की दशा एवं दिशा दोनों बदल रहा है। राज्य सरकार बालिकाओं के उत्थान के लिए आगे भी इसी प्रकार से माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य करती रहेगी।
5. शिक्षक नियोजन	–शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाये गये है। टी.ईटी. 2012 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि मई 2019 को समाप्त हो चुकी थी। लगभग दो वर्षो तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लम्बित रहने की वजह से नियोजन की कार्रवाई स्थगित थी। इस पृष्ठभूमि 2012 मे उत्तीर्ण टी.ई.टी. अभ्यर्थियों के हित में अगले दो वर्ष के लिए वैधता की अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। एस.टी.ई.टी–2012 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र की अवधि जो जून

	2019 में समाप्त हो चुकी थी। इसे भी अगले दो वर्ष के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप शिक्षक नियुक्ति के लिए शुरू किए गए छठे चरण में लगभग नब्बे हजार टी.ई.टी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो प्रशिक्षित है तथा सोलह हजार एक सौ छियानवे एस.टी. ई.टी. उत्तीर्ण जो प्रशिक्षित है को भाग लेने का अवसर मिला है। वर्ष 2006–07 से लेकर वर्ष 2016–17 तक लगभग 3.19 लाख प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन किया गया। इसी दौरान माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 30,000 शिक्षकों का भी नियोजन किया गया। वर्तमान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध लगभग तीस हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पद पर नियोजन हेतु छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कारवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे इस माह के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद स्वीकृत नही रहने से संबंधित लगातार प्रश्न किये जाते है। सरकार भी इस विषय पर चिंतित है और इस हेतु 33916 माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजित करने की कारवाई प्रक्रियाधिन है। इसके साथ–साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय के 1000 पद के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उच्च शिक्षा :	
1 उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना।	–प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक के बालिका शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार कृत्त संकल्पित है। इस क्रम में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य में बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के निमित्त मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसमें स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रति छात्रा ₹25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) मात्र उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 40,651 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को ₹101 (एक सौ एक) करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए है।
2. बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना।	– बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना दिनांक–02 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ है। इस योजना के अंतर्गत इच्छुक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए चार लाख रूपये की अधिसीमा तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जी0ई0आर0 (GER) की वृद्धि करना है। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रारंभ में यह योजना बैंकों के माध्यम से संचालित हो रही थी, परन्तु अनुश्रवण के क्रम में यह पाया गया कि बैंकों के द्वारा आवेदकों को अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है। बैंकों के माध्यम से योजना की वांछित प्रगति नहीं होने पर राज्य सरकार के द्वारा दिनांक–01 अप्रैल, 2018 से राज्य सरकार के अधीन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन कर बैंकों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ–साथ छात्रों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जैसे कि छात्रों के

	लिए चार प्रतिशत तथा छात्राओं, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांग आवेदकों के लिए मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित किया गया। इसके अलावा मोरीटॉरियम अवधि तक ब्याज मुक्त ऋण की राशि का प्रावधान किया गया एवं वैसे आवेदक जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है के ऋण की वसूली स्थगित रखने का प्रावधान किया गया है। अबतक लगभग 1 लाख 50 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 1,09,443 छात्रों को लगभग 2844 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए लगभग 89540 आवेदकों को 1029 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के द्वारा राज्य के युवाओं को आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बाधा समाप्त हो गयी है।
3. महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने की कार्रवाई।	–उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में हो रहे सुधार का साकारात्मक प्रभाव डिग्री स्तर के शिक्षा पर देखने को मिल रहा है। इस हेतु जहॉ एक ओर अनुमंडल स्तर पर सरकारी महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई भी की जा रही है। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 3364 पद के विरूद्ध 2776 पद पर विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों के नियुक्ति की कारवाई में गति प्रदान करने की उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग क्रियाशील है और शीघ्र ही महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर उसकी कमी को दूर कर लिया जायेगा।

4. नए सरकारी महाविद्यालय तथा निजी विश्वविद्यालयों का स्थापना ।	– राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में बढ़ रहे मांग की आपूर्ति के लिए पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा 07 निजी विश्वविद्यालयों यथा– अमिटी विश्वविद्यालय पटना, संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी, के0 के0 विश्वविद्यालय नालन्दा, डॉ सी0वी0 रमण विश्वविद्यालय, वैशाली, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार (सासाराम), अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार एवं माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज की स्थापना की गई है। हमारे राज्य के छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत नैनो सांयस एवं नैनो टेक्नॉलौजी के अध्ययन की व्यवस्था है तथा "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" एवं "Centre for Geographical Studies" के रूप में चार स्वायत् शासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार बिहार के शैक्षणिक जगत में ठोस और परिणामकारी कार्य करने की ओर हम अग्रसर हैं।
5. जल जीवन हरियाली	–वर्तमान पीढ़ी के साथ–साथ भविष्य की पीढ़ी की चिन्ता करने वाला अगर कोई नेता है तो व हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्रीजी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों एवं नेताओं विचार–विमर्श कर **जल–जीवन–हरियाली योजना** तैयार कराया गया है। इसमें ग्यारह विभाग है, जिसमें

	शिक्षा विभाग भी है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग को दिए गए दायित्वों के निर्वहन के लिए विभाग तत्पर है। इस कड़ी में दिनांक 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृखंला के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा अन्य सभी विभागों, सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता के सहयोग से अठारह हजार चौतीस कि०मी० लम्बी अद्वितीय मानव श्रृखंला बनाई। जिसमें पॉच करोड़ से अधिक लोग सम्मिलित हुए। इसके लिए सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मैं सरकार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
6. मदरसा बोर्ड।	– राज्य सरकार अकलियतों के शैक्षणिक विकास को लेकर भी सजग है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के लिए संचालित प्रायः सभी योजनाओं को राज्य के 1942 अनुदानित मदरसों के लिए किया गया है। मदरसा शिक्षा का प्रबंधन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। यह बोर्ड वास्तानिया (मिडिल समकक्ष), फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) एवं मौलवी (समकक्ष इन्टरमिडिएट)स्तर तक की परीक्षा का आयोजन करता है। मदरसा बोर्ड भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरह अभिनव प्रयोग कर रहा है और नई तकनीक का इस्तेमाल कर परीक्षा के स्तर में सुधार लाया जा रहा है। वर्ष 2019 में पहलीबार फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) का परीक्षाफल ऑन–लाईन किया गया और लगभग नब्बे हजार छात्र–छात्रओं को ऑन–लाईन

	मार्कसीट उपलब्ध हुआ। मदरसा बोर्ड के कार्यो के संबंध में सीमांचल क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को पटना आना होता था। इससे उन्हें असुविधा होती थी। इन क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं एवं अनुदानित मदरसा के प्रबंधन समिति के सदस्यों की सुविधा के लिए मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णियाँ प्रमंडल में स्थापित किया गया है। मदरसों में अपादा प्रबंधन की शिक्षा प्रारम्भ की गई है। इसके लिए मदरसों को शिक्षकों को ए०एन० सिन्हा संस्थान एवं यूथ हॉस्टल में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
7. साक्षरता को बढ़ाने का संस्थागत प्रयास	– आज भी **महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग** की महिला में साक्षरता का दर कम है।इन वर्गो की महिलाओं के साक्षरता को बढ़ाने के लिए **अक्षर आँचल योजना** संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में 27,138 शिक्षा सेवकों के माध्यम से उक्त वर्गो के 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5,42,020 महिलाओं को साक्षरता प्रदान किया गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहें विभिन्न योजनाओं को लाभुको तक पहुचाने में यह योजना कारगर साबित हो रहा है।
8. गाँधी जी के विचारों को जनजन तक पहुचाना।	– माननीय मुख्यमंत्रीजी का यह दृढ़ विश्वास है कि गाँधी जी के विचार से यदि आज के नवयुवक परिचित हो लेंगे तो उनके जीवन में ही नहीं पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। माननीय

	मुख्यमंत्रीजी के इस विश्वास को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे है। गांधीजी के विचारों के प्रचार–प्रसार हेतु गांधी चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर वर्ष 2017–18 में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गांधीजी की जीवन पर आधारित "एक था मोहन" (कक्षा 09 से 12) तथा "बापू की पाती" (कक्षा 01 से 08) पुस्तक का प्रतिदिन चेतना सत्र में बच्चों द्वारा वाचन किया जाता है। साथ ही, बापू के महत्वपूर्ण संदेश को सभी शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों में दीवार पेंटिंग कराया गया। पुनः 2019 में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर दिनांक– 02 एवं 03 अक्टूबर, 2019 को पटना में दो दिवसीय गांधी विचार समागम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात गांधी विचारकों ने भाग लिया। इससे समाज में नई चेतना की लहर फैली है।

****

प्राथमिक शिक्षा :

1. 6–14 आर्युवर्गों के बच्चों को विद्यालय से अच्छादित करना।
2. प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना।
3. पुस्तक क्रय हेतु राशि का स्थानांतरण।
4. आर.टी.ई. एक्ट के आलोक में Detention Policy का क्रियान्वयन।
5. राजकीय बुनियादी विद्यालय का सुदृढीकरण ।
6. बेस्ट एप के माध्यम से अनुश्रवण।
7. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण।
8. मध्याह्न भोजन योजना।

माध्यमिक शिक्षा :

1. सभी छुटे हुए पंचायतों में अप्रैल, 2020 से वर्ग–09 की पढ़ाई शुरू किया जाना।
2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।
3. उन्नयन बिहार कार्यक्रम।
4. बालिका शिक्षा पर जोर।
5. शिक्षक नियोजन।

उच्च शिक्षा :

1 उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
2. बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना।
3. महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने की कार्रवाई।
4. नए सरकारी महाविद्यालय तथा निजी विश्वविद्यालयों का स्थापना ।
5. जल जीवन हरियाली।
6. मदरसा बोर्ड।
7. साक्षरता को बढ़ाने का संस्थागत प्रयास।
8. गाँधी जी के विचारों को जनजन तक पहुचाना।

नियोजित शिक्षकों का वेतन और हड़ताल

सदन इस तथ्य से भलिभांति अवगत है कि वर्ष 2003 और 2005 में पंचायत शिक्षामित्रों का नियोजन 11 महीने के अनुबंध पर 1500 रूपये प्रति माह के मानदेय पर तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया था। सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार वर्ष 2005 में बनी और उन्होंने इन पंचायत शिक्षामित्रों की सुध लेते हुए इनके समायोजन और शिक्षकों के नियोजन के लिए वर्ष 2006 में नई शिक्षक नियोजन नियमावली बनाई। इस नियमावली के प्रावधान के आलोक में उस समय कार्यरत लगभग एक लाख पांच हजार पंचायत शिक्षामित्र को 01 जुलाई, 2006 के प्रभाव से पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजित करते हुए उन्हें प्रति माह 4000 (अप्रशिक्षित के लिए) एवं 5000 (प्रशिक्षित के लिए) का नियत वेतन स्वीकृत किया गया। यहीं नहीं इनकी सेवा को 60 वर्ष की आयु तक किया गया।

पंचायत शिक्षकों के नियोजन के उपरांत सरकार ने अपने संसाधन को ध्यान में रखकर इनके नियत वेतन में भी वर्ष 2010 से वर्ष 2015 की अवधि में समय–समय पर एकमुश्त वृद्धि किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन शिक्षकों को 30 जून, 2015 तक इनका वेतन 9000 एवं 10,000 रूपये प्रति माह हो गया।

नियोजित शिक्षकों के द्वारा वेतनमान देने की मांग लगातार किया जा रहा था। वैसे इन शिक्षकों का नियोजन इनके द्वारा नियमावली में अंकित शर्तों के अधीन कार्य करने की सहमति के शर्त पर हुई थी। बावजूद इसके सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण की मांग को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया और समिति की अनुशंसा पर उन्हें 01 जुलाई 2015 से 5200 से 20200 का वेतनमान स्वीकृत किया गया। यहीं नहीं नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों की भांति ही मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी गई।

राज्य कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिस गुणक के आधार पर वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया, उसी गुणक को आधार बनाकर नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में भी 2.57 की वृद्धि अन्य राज्य कर्मियों की भांति दिनांक–01.04.2017 से प्रभावी की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2006 में जिन पंचायत शिक्षामित्रों को 1500 रूपये प्रति माह का मानदेय मिलता था, उन्हें वर्तमान में लगभग 29,000 प्रति माह से अधिक का वेतन मिल रहा है।

नियोजित शिक्षकों के द्वारा "समान काम के बदले समान वेतन" विषय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न वाद भी दायर किए

गए। इस मामले पर पूर्ण विराम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका 20/2018 में दिनांक–10.05.2019 को न्यायादेश पारित करते हुए किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक–10.05.2019 के न्यायादेश का अध्ययन सभी संबंधितों को करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने वर्ष 2005–2006 से अबतक माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो–जो कार्य समाजिक न्याय के दृष्टिकोण से किए गए, उसपर गौर करते हुए उसकी सराहना की गई। साथ ही, माननीय न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के "समान काम के बदले समान वेतन" की मांग को नहीं मानते हुए यह आदेश की कंडिका–79 में स्पष्ट किया कि नियोजित शिक्षकों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं किया गया और न हीं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश वस्तुतः सरकारों के लिए नियमन है और सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। इस प्रकार नियोजित शिक्षक भी इस आदेश से बंधे हुए हैं। बावजूद इसके इनके मांगों को यदि माननीय सदस्य देखेंगें तो यह ज्ञात होगा कि अधिकांश शिक्षक संघ का पहला मांग "समान काम के बदले समान वेतन" ही है। ऐसे में यह हड़ताल उस विषय पर है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया है।

राज्य सरकार शिक्षकों की हितैशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सार्वजनिक मंच से एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद पर सरकार का उत्तर देते हुए बिहार विधान परिषद् में पुनः यह दोहराया की सरकार अपने हैसियत के हिसाब से पहले भी वेतन में वृद्धि की गई है और आगे भी करेगी।

शिक्षकों का हड़ताल का समय भी देखिए। यह हड़ताल मैट्रिक एवं इण्टर की परीक्षा को बाधित करने के साथ–साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने के उद्देश्य से भी किया गया, प्रतीत होता है। इससे छात्रों के भविष्य पर नियोजित शिक्षकों की संवेदनशीलता क्या है, यह भी स्पष्ट होता है।

हड़ताल पर जाने की सूचना से पहले से ही मेरे द्वारा अपील किया जा रहा है और आज भी मैं सदन के माध्यम से सभी शिक्षकों से अपील करता हूँ कि वे विद्यालयों में योगदान कर बच्चों को मन से पढ़ाएें एवं राज्य सरकार अपनी हैसियत के अनुसार उनके वेतन में वृद्धि करेगी एवं वर्तमान सेवाशर्तो में भी सुधार करेगी।